हिन्दुस्तान 1936

# चीन का रुख

मतभेदों से भरी दुनिया में किसी सहमति तक पहुंचने की कोशिश सदा स्वागत-योग्य है। भारत की ओर से अक्सर चीन के प्रति उदारता के संकेत मिलते रहते हैं, पर चीन की ओर से ज्यादातर तल्ख टिप्पणियों का त्रासद सिलसिला ही रहा है। भारत विरोधी आतंकवादियों को विश्व स्तर पर किसी भी हद तक जाकर बचाने का मुद्दा हो या किसी भारतीय इलाके पर गिद्ध दृष्टि, साल 1962 से हम यही देखते आ रहे हैं। हां, पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच गलवान सीमा विवाद पर जो सहमति बनी, उसके बाद चीन के रुख में कुछ बदलाव दिख रहा है, जिससे एक उम्मीद जरूर जगती है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में इस उम्मीद को बढ़ाते हुए जो कहा है, उस पर विचार की जरूरत है। वांग ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में चार साल से चल रहे सैन्य गतिरोध को सुलझाने में पिछले साल मिली सफलता के बाद भारत-चीन संबंधों ने सभी स्तरों पर उत्साहजनक प्रगति की है। गौर करने की बात है कि भारत सीमा विवाद सुलझाने को तरजीह देता है। चूंकि अब सीमा विवाद को कुछ सुलझा लिया गया है, इसलिए चीन संबंध सुधारने के पक्ष में दिख रहा है।

क्या चीन के ताजा रुख पर हमें खुशी से उछल पड़ना चाहिए? वास्तव में, चीन का रुख स्थिर नहीं है। हमें ऐसे और ठोस संकेतों की जरूरत पड़ेगी, जिससे लगे कि वह भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शक्तिशाली सदस्य वांग का यह कहना साकार होना चाहिए कि दो प्राचीन सभ्यता के रूप में दोनों देशों में उच्च स्तरीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त ज्ञान व क्षमता है। सबसे बड़े पड़ोसियों के रूप में दोनों देशों को एक-दूसरे की सफलता का समर्थन करना चाहिए। गौर करने की बात है कि वांग ने ड्रैगन और हाथी के बीच सहकारी साझेदारी को एकमात्र सही विकल्प बताया है। वांग ने अनेक अच्छी बातें कही हैं, जिन्हें जमीन पर उतारने के लिए ठोस पहल की जरूरत है। इतिहास गवाह है, भारत ने कभी चीन की परेशानियों में इजाफा करने के लिए कुछ नहीं किया है। अतः गलवान के समय भारतीय पक्ष को जो हासिल हुआ, उसे भूलने में वक्त लगेगा। जो हुआ, उसे चीन टाल सकता था। वांग के रुख से ऐसा लगता है कि चीन अब भारत के साथ मिलकर चलने में ही व्यापक हित देख रहा है, तो इसमें वैश्विक मजबूरियों की ज्यादा भूमिका है।

**जैसा रवैया अमेरिका इन दिनों दिखा रहा है, उससे तमाम देशों को चिंता हो रही है। चिंतित देशों में अगर भारत शामिल है, तो भारत से भी ज्यादा चिंता चीन को सता रही है।**

ध्यान रहे, जैसा रवैया अमेरिका इन दिनों दिखा रहा है, उससे तमाम देशों को चिंता हो रही है। चिंतित देशों में अगर भारत शामिल है, तो भारत से भी ज्यादा चिंता चीन को सता रही है। वाकई, दोनों देश अगर एक-दूसरे का हित देखते हुए आगे बढ़ें, तो पूरे दक्षिण एशिया में अमन-चैन को बल मिल सकता है। आज दक्षिण एशिया में आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक तनाव की स्थिति है, तो इसमें चीन को अपनी भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए। इतना तो तय है कि अगर अमेरिकी रुख में तल्खी बढ़ी, तो चीन और भारत को एक-दूसरे की जरूरत पड़ेगी। वाकई, दोनों देशों को मिलकर चलना चाहिए और व्यावसायिक रूप से दोनों देश बहुत हद तक एक-दूसरे से मिलकर चल रहे हैं, पर दोनों के बीच जिस तरह का सामरिक-कूटनीतिक-राजनीतिक तनाव है, उसे दूर करने के लिए चीन को ही पहले ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। परस्पर विश्वास बढ़ाने का काम बहुत बड़ा है और मिलकर चलने के इरादे से भारत कभी पीछे नहीं हटा है।

## हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 08 मार्च 1950

### चीनी उद्योग कसौटी पर

चीनी के बिना लोग सामान्यतः काम नहीं चला सकते। चीनी उनके भोजन का आवश्यक अंग बन गई है। गत वर्ष जब अचानक लोगों को चीनी मिलना कठिन हो गया, तो उनमें काफी असंतोष फैल गया था। चीनी उद्योग और सरकार दोनों की खूब आलोचनाएं हुईं। सरकार को चीनी के वितरण पर पुनः नियंत्रण लगाना पड़ा और आगे के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ा। चीनी लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक आज भी नहीं मिल रही है और चीनी में चोर बाजार भी चल ही रहा है।

देश के उद्योगों को पनपाने के लिए उन्हें विशेष संरक्षण देना जरूरी होता है। चीनी उद्योग देश के उन कतिपय भाग्यशाली उद्योगों में से है, जिसे विदेशी शासन ने भी संरक्षण प्रदान किया। उसे पिछले १८ वर्षों से संरक्षण प्राप्त है। इतने लंबे अर्से तक संरक्षण पा लेने के बाद कम से कम इस उद्योग को तो अपने पांवों पर खड़ा हो जाना चाहिए था। किन्तु यह आज भी विदेशी चीनी के मुकाबले में खड़ा नहीं रह सकता। विदेशी चीनी पर यदि आयात-कर न लगाया जाये, तो वह देश की चीनी से सस्ती पड़ेगी। देशी चीनी की कीमत २८ रु. ८ आने प्रति मन है, जबकि विदेशी चीनी २२ रु. ८ आने प्रति मन के हिसाब से पड़ेगी। देश के चीनी उद्योग को टिकाये रखने के लिए ही सरकार ने विदेशी चीनी पर आयात कर लगाया हुआ था। स्वदेशी की भावना से प्रेरित होकर लोगों का महंगी होने के बावजूद देशी चीनी का उपयोग करना उचित है। किन्तु इस त्याग की भी कोई सीमा तो जरूर होनी चाहिए। यदि चीनी उद्योग सरकारी संरक्षण के भरोसे निश्चिन्त हो जाये और उपभोक्ताओं से यह आशा रखे कि वे अधिक मूल्य देते रहेंगे, तो यह न्याय नहीं होगा। जब उन्हें मालूम होगा कि विदेशी चीनी लंबे यातायात का खर्च बर्दाश्त करके भी सस्ती पड़ती है, तो देशी उद्योग की कार्यक्षमता पर उन्हें संदेह करने का उचित कारण मिलेगा। उनकी ओर से यह मांग भी पेश की जा सकती है कि सरकार को विदेशी चीनी के आयात पर से प्रतिबंध हटा लेना चाहिए, ताकि देशी उद्योग और किसी खयाल से नहीं, तो प्रतिस्पर्द्धा के डर से अपने घर को दुरुस्त करने की चिंता करे।

देश की आबादी बढ़ी है, तो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ेंगी। परिसीमन का वर्ष 2026 करीब आ गया है और दक्षिण के कई नेताओं ने शिकायतों का झंडा उठा लिया है। सर्वदलीय बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दक्षिण के राज्य अपनी वर्तमान राजनीतिक शक्ति को खोना नहीं चाहते। साल 2002 में 7 मई को लोकसभा में परिसीमन पर जो बहस हुई थी, ठीक वैसी ही बहस फिर शुरू हो गई है।

# किसी राज्य से भेदभाव नहीं किया जाएगा

यहां स्कैन करें

अरुण जेटली | तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री

- निर्वाचन क्षेत्रों के आकार की विसंगति को दूर किया जाएगा।
- परिवार नियोजन लागू करने वाले राज्यों को नुकसान नहीं होने देंगे।
- ज्यादातर सांसद मानते हैं कि सीटों में सेटेशन की व्यवस्था ठीक नहीं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2002 पर विचार किया जाए।... अभी संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या में असमान वृद्धि तथा एक ही राज्य में लोगों तथा मतदाताओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने से एक ही राज्य के भीतर आश्चर्यजनक रूप से अलग-अलग आकार के निर्वाचन क्षेत्र हो गए हैं।...

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य परिसीमन आयोग गठित करना है, ताकि निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में आई उपरोक्त विसंगति को दूर किया जा सके। प्रस्तावित परिसीमन आयोग 1971 की जनगणना के आधार पर स्थानों की कुल संख्या को प्रभावित किए बिना 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या भी पुनःनिर्धारित करेगा।

...इस संविधान संशोधन की तीन विशेषताएं हैं। पहली तो यह कि चुनाव क्षेत्र परिसीमन का आधार वर्ष 1991 होगा न कि वर्ष 1971 और दूसरा, दोनों सदनों तथा पूरे देश के राज्य विधानमंडलों या विधानसभाओं में वर्तमान सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक यही रहेगी। यह शंका जताई जा रही है कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू नहीं किया है, उन्हें परोक्ष रूप से अपने राज्यों में सीटों के बढ़ने से लाभ मिलेगा। इस विधेयक में मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, ताकि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कारगर रूप से लागू किया है, उनके प्रति भेदभाव नहीं किया जाए। ...

महोदय, प्रक्रिया का यह इतिहास रहा है कि 1951 में राष्ट्रपति के आदेश के बाद पहला परिसीमन कार्य हुआ था। इसके बाद 1962 में 1952 के अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन कार्य हुआ और अंतिम परिसीमन कार्य, परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत हुआ और इसके परिणामों को 1 दिसंबर 1976 को अधिसूचित किया गया। ...परिसीमन करते समय निर्वाचन क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं को ध्यान में रखना होगा। ...जिस समय परिसीमन आयोग के सामने चुनाव क्षेत्र बांटे जाएंगे, उनका जो आकार होगा, इस कानून के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि हर सीट का आकार लगभग समान होगा। अब एकदम अधमिटिकली बराबर हो जाए, तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ उसमें बदलाव किया जाएगा, जिसमें सीटों की संख्या और साइज लगभग बराबर हो।

महोदय, रोटेशन का प्रावधान इसमें इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि जब संविधान के 84वें संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई थी, तो कुछ लोगों का मत था कि रोटेशन होनी चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों का मत था कि रोटेशन से नुकसान हो सकता है।... एक तर्क यह है कि रोटेशन के जो नुकसान हो सकते हैं, उनमें एक यह भी है कि कई बार इस प्रकार की स्थिति भी आ सकती है कि जो क्षेत्र होगा, वह रोटेट होते-होते ऐसी स्थिति में आ सकता है, जहां एसटी की संख्या बहुत कम हो, जिससे वह क्षेत्र रोटेशन की दृष्टि से एसटी घोषित हो जाए और जहां एसटी ज्यादा संख्या में हों, वह क्षेत्र जनरल (या सामान्य) घोषित हो जाए।...84वें संशोधन में इसका स्पष्ट उल्लेख है। किसी राज्य की जनगणना बढ़ने मात्र से हम स्थानों या सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। संविधान संशोधन के अनुसार, संपूर्ण देश में स्थिरीकरण की स्थिति है। हर राज्य में स्थिरीकरण है, इसलिए एक राज्य या दूसरे के लिए एक अपवाद गढ़ना संभव नहीं होगा।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

**आमने-सामने**

# आबादी पर नियंत्रण से हमें नुकसान होगा

यहां स्कैन करें

के येरन नायडू | तत्कालीन सांसद

- हम दक्षिण के राज्य निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में बढ़ोतरी के खिलाफ हैं।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने का हमें नुकसान होगा।
- सीटों में रोटेशन व्यवस्था सही है और इसके लिए सहमत होना चाहिए।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय विधि मंत्री को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। ...वर्ष 1972 के बाद देश में किसी परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया, परंतु जनसंख्या की अनियमित वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के लगातार पलायन के कारण भी आज कुछ संसदीय क्षेत्रों के साथ-साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कम मतदाता हैं, जबकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक है।

महोदय, पिछली बार इस सम्मानीय सभा ने निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को स्थिर करने के लिए विधान पारित किया था। हमारी पार्टी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में बढ़ोतरी के खिलाफ थी। हमारी एक जनसंख्या नीति है, परंतु यदि निर्वाचन क्षेत्र को स्थिर करने जैसे निवारक उपाय नहीं किए जाएंगे, तो राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए नहीं जाएंगे। इसलिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भारत सरकार को यह सुझाव दिया कि वे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में बढ़ोतरी का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वर्ष 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों को स्थिर नहीं किया गया, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन चार राज्यों की लोकसभा की सीटें जो वर्तमान में 204 हैं, 2026 तक बढ़कर 229 हो जाएंगी। इसके विपरीत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल इन चार राज्यों की लोकसभा में सीटें, जो वर्तमान में 129 हैं, साल 2026 तक घटकर 113 रह जाएंगी। इन राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। हम भी राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों को पूरी तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं, इसीलिए हम निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने के खिलाफ थे।

...आज कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में केवल तीन से चार लाख मतदाता हैं, जबकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 20 से 22 लाख अथवा इससे भी अधिक मतदाता हैं। अतः ऐसे मामलों में परिसीमन की आवश्यकता है। हमें प्रत्येक दस अथवा बीस वर्षों में परिसीमन आयोग की स्थापना करनी चाहिए। इसे एक अनिवार्य उपबंध बनाया जाए। ...वैसे, हम संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि सत्ता में आई सभी पार्टियां सभी मामलों में संविधान के अनुसार कार्य करती हैं, तो ऐसी समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। अतः मेरा यह सुझाव है कि इसके बाद जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है, प्रत्येक दस वर्ष के बाद परिसीमन आयोग गठित किया जाए।

महोदय, इस विधेयक में चक्रानुक्रम या (रोटेशन) प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में जनार्दन रेड्डी नेल्लोर जिले के हैं, इस निर्वाचन क्षेत्र को 8 सीटें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य में अन्य निर्वाचन क्षेत्रों को भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाए। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाना उचित होगा। जो भी हो, इस विधेयक में रोटेशन को शामिल नहीं किया गया है। इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य परिसीमन आयोग की नियुक्ति करना है। शुरू से ही सभी लोग रोटेशन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। विधि मंत्री इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए यथाशीघ्र सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। यदि सभी लोग रोटेशन व्यवस्था के लिए सहमत होते हैं, तो संसद के अगले सत्र में रोटेशन व्यवस्था के लिए भी एक पृथक विधेयक पुनःस्थापित किया जा सकता है।

हमें पारदर्शिता बरतनी होगी। ...हम नियम और विनियम बना सकते हैं, ताकि निर्वाचन क्षेत्रों का पारदर्शी और सार्थक परिसीमन किया जा सके।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)

# बचपन से बुढ़ापे तक बलवती होती गई मातृ शक्ति

यहां स्कैन करें

कमलेश जैन | वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

मार्च की 8 तारीख महिलाओं को समर्पित है। इस दिन पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत की बात करें, तो यहां की स्त्रियों में असीम संभावनाएं हैं और वे तमाम तरह की उपलब्धियां हासिल भी कर रही हैं, जिसमें भारतीय संविधान और कानून का विशेष योगदान है। यह यात्रा 1950 में संविधान लागू होने के साथ शुरू हो गई थी। इसमें महिला और पुरुष, दोनों को बराबर माना गया है। मगर कई ऐसे मौके आए, जब कानून में इस बात्त कुछ सुधार की जरूरत महसूस हुई। जैसे- पहले बलात्कार के मुकदमे में एफआईआर करने वाली महिला भी सह-अपराधी समझी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज जांच और ट्रायल के लिए उसका बयान ही काफी है और वह सह-अभियुक्त भी नहीं है। वास्तव में, पिछले 25 वर्षों में महिलाओं ने कानून के बल पर बिल्कुल बराबरी का अधिकार पा लिया है। सन् 2005 में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) ऐक्ट द्वारा संयुक्त परिवार की बेटी को संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार दिया गया। यह अधिकार जन्म के साथ प्राप्त है। इसके साथ ही, परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बेटे के बराबर तय की गई है। अब तक बेटी को पैतृक संपत्ति में कुछ नहीं मिलता था, इसलिए यह आर्थिक रूप से किसी न किसी पर निर्भर थी। मगर अब वह आर्थिक गुलामी से मुक्त हो चुकी है।

विवाह पश्चात भी कई ऐसे अधिकार हैं, जिनसे स्त्रियां लाभ उठा सकती हैं। अब उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना पर रोक लगाई गई है। यह रोक इतनी है कि पुरुष उनसे डरने लगे हैं, इसलिए उम्मीद है कि इन अधिकारों का महिलाओं द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। सुखद यह भी है कि अब विवाह की शर्त यह नहीं रही कि बच्चा न हो, तो पुरुष विवाह से आजादी पा सकता है। इसी तरह, घरेलू हिंसा कानून, 2005 एक ऐसा कानून है, जिसके अंतर्गत स्त्री विवाह के पश्चात सभी तरह की प्रताड़नाओं का कानूनी मुकाबला आसानी से कर सकती है। वह पति और ससुराल वालों को जेल भेजे बिना अपनी शिकायतें कर सकती है, और घर तोड़े बिना अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। ऐसा ही एक अन्य कानून है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम। इसका लाभ यह हुआ है कि अब कार्यस्थल पर महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और भौतिक शोषण काफी हद तक रुक गया है। अगर कोई अधिकारी कुचेष्टा करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

**पिछले 25 वर्षों में महिलाओं ने कानून के बल पर बराबरी का अधिकार पा लिया है। 2005 के हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून द्वारा बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर हक मिला है। महिला दिवस विशेष :**

स्त्रियों के सामने समस्या यह भी रही है कि राह चलते उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ का खतरा बना रहता था। नहीं कुछ तो, उसे बुरी नजरों से देखा जा सकता था। मगर कानून ने अब महिलाओं को घूरने, कैमरे लगाकर उसका पीछा करने, सार्वजनिक जगहों पर उस पर नजर टिकाए रखने आदि को अपराध माना है और इसकी शिकायत करने पर पुलिस आरोपी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करने को बाध्य है। देखा जाए, तो हमारा कानून हर जगह स्त्री की सुरक्षा का ख्याल रखता है। यदि उसके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार होता है, तो आरोपी को कानून सजा दिलाई जा सकती है। कुछ मामलों में तो अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान है।

पहले 18 वर्ष तक के लड़के नाबालिग माने जाते थे और कोई भी अपराध करके बिना सजा पाए बच्चों की तरह जेल की सजा से छूट जाते थे। इधर, किशोर न्याय अधिनियम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब 16 से 18 वर्ष की उम्र वाले किशोर यदि बर्बर अपराध करते हैं, तो उन पर भी वयस्कों की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और सजा भी बड़ों जैसी होगी। अभी हाल में पांच वर्ष की बच्ची के साथ ऐसी बर्बरता की गई थी कि उसके जननांग में 20 टांके लगाने पड़े थे। इस मामले को भी बड़ों की अदालत में भेजने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, बुजुर्ग होने पर यदि बाल-बच्चे घर की महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम का लाभ वे उठा सकती हैं।

देखा जाए, तो आज भारतीय स्त्री जीवन के हर मोड़ पर कानूनी सुरक्षा के घेरे में है। उसे पुरुषों की तरह सशक्त बनाया गया है। वह आज स्वावलंबी और स्वतंत्र है। इसीलिए, अब कहा जाने लगा है कि भारतीय महिलाओं की सीमाएं आकाश की तरह अंतहीन हो गई हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

## मनसा वाचा कर्मणा

### राष्ट्रवाद की मांग

अंग्रेजों ने भारतीय समाज की धार्मिक विभिन्नताओं का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश बहुत पहले से प्रारंभ कर दी थी और फिर मुसलमानों को हिंदुओं के विपरीत खड़ा करने की नीति खुले तौर पर अपनाई जाने लगी। नई विधान परिषदों में मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, वह भूमि की संतान, भारतीय जनता के एक संयुक्त हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से एक अलग और प्रतिकूल हित के रूप में।... हिंदुओं को आत्मघोष ही गया है। उन्हें एक आवाज सुनाई दी है, जो मानो उन्हें पुकारकर कह रही हो, 'मृत को त्यागकर उठो और जीवन को अपनाओ, मेरा अनुसरण करो' और अप्रतिरोध रूप से बढ़कर वे एक जीवंत व शक्तिशाली राजनीतिक बल बनते जा रहे हैं।

राष्ट्रवाद अपनी सफलता के लिए राष्ट्र की समूची शक्ति को जागृत करने और उसे संगठित करने पर निर्भर करता है; अतः राष्ट्रवाद के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को जागृत किया जाए और उन्हें राजनीतिक जीवन की धारा में जोड़ा जाए; रूढ़िवादी हिंदुओं का एक विशाल समूह... जो राजनीतिक रूप से निष्क्रिय बना रहा; दुकानदार, कारीगर वर्ग, अनपढ़ और भोले किसानों का एक भारी तबका, दलित वर्ग, यहां तक कि जो जातियां हिंदू सभ्यता के दायरे से बाहर रही हैं, राष्ट्रवाद इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकता।

राष्ट्रवाद की पहली और सब चीजों से बढ़कर मांग है जीवन की; उसकी पुकार है जीवन, और अधिक जीवन। पहले हम अकर्मण्यता और निष्क्रियता के अकथनीय दबाव को अपने से दूर करें, जो लंबे अरसे से हमारे लिए एक अभिशाप रहा है; यह हमारी पहली और अनिवार्य आवश्यकता है।

श्री अरविंद

**द्रौपदी मुर्मू** | राष्ट्रपति, भारत

**ऐसे प्रयास होने चाहिए कि अन्य देशों के शिक्षण संस्थानों से हमारी उच्च-शिक्षा व्यवस्था का जुड़ाव बढ़े। वैश्विक प्रयासों व सहयोग के मजबूत होने से हमारे विद्यार्थी विश्व में अपनी और अधिक प्रभावी पहचान बनाएंगे।**

# लगातार बढ़ रहे आधी आबादी के कदम

नारी महज एक शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। भारतीय संस्कृति में उसे शक्ति, ममता और त्याग का स्वरूप माना जाता है। आज महिलाओं की स्थिति पहले से काफी अच्छी हुई है। महिलाएं न सिर्फ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में तो वे पुरुषों पर भारी पड़ने लगी हैं। यही कारण है कि उनके मान-सम्मान में भी इजाफा हुआ है। यहां तक कि कई ऐसे कानून भी बनाए गए हैं, जो महिलाओं को हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार करते हैं। यह सही है कि कुछ मामले में चुनौतियां बनी हुई हैं। मगर घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, दहेज जैसी समस्याओं पर आखिरी चोट की जाए, तो आने वाला वक्त महिलाओं का ही होगा। देश की तरक्की में उनके योगदान की जितनी चर्चा हम आज कर रहे हैं, आने वाले समय में उससे कहीं ज्यादा करेंगे। यह महिला दिवस हमारा भरोसा मजबूत बना रहा है।

**सुमन सिंह, टिप्पणीकार**

महिला दिवस का मकसद उस ज्वाला को भी प्रज्वलित करना है, जो हरेक महिला को यह एहसास दिलाए कि वह कमजोर नहीं, बल्कि एक शक्ति है। यह दिन हमें उनकी हर छोटी-बड़ी लड़ाई को सम्मान देने और उनके सपनों को पंख देने का मौका देता है। यह सही है कि आज भी महिलाओं की समस्याएं हमारे समाज की जड़ों में गहरे तक धंसी हुई हैं, लेकिन अंधेरे बादलों के बीच उम्मीद की किरणें कहीं अधिक चमक रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जो नारी की छोटी से छोटी जरूरत को समझते हुए उसे सशक्त करने का रास्ता दिखाते हैं। शिक्षा को नारी की आजादी का पहला द्वार मानते हुए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान ने समाज की सोच को झकझोरा है। जहां कभी बेटियां गर्भ में ही मार दी जाती थीं, आज उनकी हंसी स्कूलों में गूंजती है। स्कूलों में महिला शौचालयों का निर्माण सिर्फ ईंट-पत्थर की बात नहीं, बल्कि उस बेटी की गरिमा की रक्षा भी है, जो पहले इन सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई छोड़ देती थी। सुकन्या समृद्धि योजना ने हर मां-बाप के दिल में एक सपना बोया कि अच्छी ब्याज दर के साथ बेटी की अच्छी शिक्षा और शादी संभव है। यही हाल रोजगार के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी है। ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं, जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। इसलिए, यह महिला दिवस नाउम्मीदी का नहीं, बल्कि उम्मीद बनाए रखने का दिन है।

**आर के जैन, शिक्षाविद**

**अनुलोम-विलोम**

**अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस**

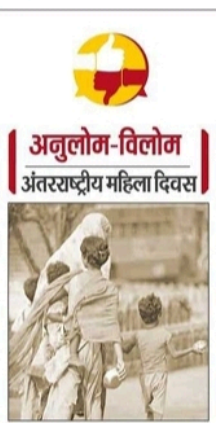

# अब भी कई क्षेत्रों में सुधार के काम बाकी

महिलाएं हर क्षेत्र में भले ही तरक्की की नई इबारत लिख रही हैं, लेकिन कुछ बातें आज भी खलती हैं। जैसे, लिंगानुपात के मामले में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। विडंबना है कि यह अनुपात उस समाज में ज्यादा असंतुलित है, जो अपेक्षाकृत दूसरों से विकसित है। जब पुरुष और महिला एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं, तब क्यों महिलाओं और पुरुषों का अनुपात असंतुलित है? आम महिलाओं की दशा आज भी दयनीय है और यह दशा तभी सुधरेगी, जब महिलाएं शिक्षा सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका में आएंगी। कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ कसर अभी बाकी है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सबसे अधिक जरूरी है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार होना। मगर यह पहल कौन करेगा? चूंकि इससे वोट नहीं मिलता, इसलिए हमारे नीति-नियंता इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसे में, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना तभी सार्थक होगा, जब महिलाओं को बराबर का महत्व देकर हर अधिकार सौंप दिए जाएंगे। पता नहीं, यह कब हो सकेगा?

**मुकेश कुमार मनन, टिप्पणीकार**

महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हमारे देश की महिलाओं को कमोबेश हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार हासिल हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वे अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहीं। जिन-जिन महिलाओं ने अपने अधिकारों का उपयोग किया, उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। फिर भी, कुछ मामलों में महिलाएं आज भी पीछे नजर आती हैं, जिनकी एक बड़ी वजह सामाजिक बुराई है। देखा जाए, तो सामाजिक बुराइयों के पोषण में महिलाएं भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि आज भी अपने आसपास हम रूढ़िवादी और अंधविश्वासी महिलाओं को देख सकते हैं। जब किसी घर में लड़के की शादी होती है, तब दहेज की और जब लड़की पैदा होती है, तब उसकी शादी में होने वाली कथित परेशानियों की चर्चा महिलाएं ही ज्यादा करती हैं। सामाजिक बुराइयों का अंत करने और भारत की संस्कृति को संभालने के लिए महिलाओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए। समय के साथ उन्हें अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। भारत तब तक विकसित देश में शामिल नहीं हो सकता, जब तक हर वर्ग में लड़के और लड़की के बीच भेदभाव की मानसिकता पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। सरकार इसके लिए बेशक प्रयास कर रही है, लेकिन इसे साकार करने में जो मुश्किलें आ रही हैं, उन पर अपेक्षानुरूप ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए।

**राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार**

## भारत-यूरोप संबंध

### प्रगति का मार्ग

**भारत-यूरोपीय संघ**-ईयू संबंधों की मजबूती स्थायित्व, समृद्धि तथा तकनीकी प्रगति का मार्ग है। यूरोपीय संघ के भारत के साथ संबंधों में काफी तेज गति आई है जिससे रणनीतिक संबंधों में नया अध्याय खुला है। वैश्विक उथलपुथल को देखते हुए भारत-ईयू संबंधों में मजबूती वैश्विक भू-राजनीति में स्थिरीकरण शक्ति के रूप में उभरी है। इनमें डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी दृष्टिकोण में परिवर्तन शामिल है जो टैरिफ बढ़ाने, यूक्रेन से समर्थन वापसी तथा गाजा मामले में तटस्थता से परिभाषित होता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेयेन की हालिया भारत यात्रा नई दिल्ली के साथ ईयू के गहरे होते संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करती है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक में वान डर लेयेन ने एक साझीदार के रूप में भारत के प्रति ईयू का अत्यधिक सम्मान प्रकट किया। उन्होंने जोर दिया कि दोनों रणनीतिक साझीदारी के तीसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं और 'सर्वोत्तम अभी आना बाकी है'। यह बयान भारत के प्रति ईयू का दृष्टिकोण प्रकट करता है जो वैश्विक आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्य को स्वरूप देने में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। उनकी चर्चा में प्रमुख स्थान भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे-आईएमईसी को मिला जो कनेक्टिविटी, व्यापार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की दिशा में लक्षित महत्वपूर्ण पहल है।

बदलती भू-राजनीतिक स्थितियों में यह गलियारा चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनीशियेटिव' को संतुलन करने वाला हो सकता है तथा ज्यादा विविधीकृत व मजबूत वैश्विक सप्लाई श्रृंखला सुनिश्चित करता है।

भारत-ईयू साझीदारी का एक महत्वपूर्ण बिंदु डिजिटल व तकनीकी क्षेत्रों में गहरा होता सहयोग है। भारत एक तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहा है और ईयू भी डिजिटल संप्रभुता की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में सहयोग उल्लेखनीय तालमेल पैदा कर सकता है। स्वच्छ ऊर्जा के प्रति ईयू का आकर्षण भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों से जुड़ता है। ऐसी पहलों से भारत और ईयू टिकाऊ भविष्य लाने में वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं। तकनीक और ऊर्जा के अलावा ईयू-भारत संबंधों में व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। दोनों पक्ष सक्रिय रूप से मुक्त व्यापार समझौता-एफटीए करने पर बातचीत कर रहे हैं जो आर्थिक संभावनाओं को खोल सकता है। ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है और दोनों के बीच समग्र व्यापार समझौते से न केवल निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खासकर आर्थिक अस्थिरता की शिकार दुनिया में सप्लाई श्रृंखला मजबूत होगी। ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां विश्व व्यापार में बाधा डाल रही हैं, ऐसे में ईयू-भारत व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि दोनों अर्थव्यवस्थायें प्रतियोगी तथा वैश्विक वाणिज्य के लिए खुली बनी रहें। सप्लाई श्रृंखला मजबूत करने में सहयोग खास बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम से निपटने में भी महत्वपूर्ण है। ट्रंप की नीतियां ट्रांस-एटलांटिक संबंधों में और विश्व व्यापार में अनिश्चितता पैदा कर रही हैं, ऐसे में भारत के प्रति ईयू का झुकाव एक रणनीतिक पुनर्निर्धारण है। ईयू ने वैश्विक मामलों में स्थिरीकरण शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका की पहचान की है। दोनों पक्ष तानाशाही सरकारों के मुकाबले एक लोकतांत्रिक शक्ति तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ईयू-भारत साझेदारी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। डिजिटल सहयोग, हरित ऊर्जा पहलों और जीवन्त व्यापार पर बातचीत को अग्रणी भूमिका मिलने से ये संबंध वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक ध्रुवीकरणों को पुन: बदल सकते हैं।

# ऑस्कर में भारतीय सिनेमा

**भारतीय कथायें पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती हैं। सही रणनीति के साथ यह क्षण भारतीय सिनेमा का भविष्य निर्धारित कर सकता है।**

**चैतन्य के. प्रसाद**
(लेखक, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं)

भारत के वसुधैव कुटुंबकम, यानी 'दुनिया एक परिवार है' के विचार को मजबूत करने में 'नमस्ते एट द आस्कर्स, 2025' ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस दृष्टिकोण ने सीमायें पार की हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सम्मान, परस्पर निर्भरता तथा रचनात्मकता की साझा भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। यह प्रतीकात्मक संकेत न केवल एक शुभकामना, बल्कि समावेशन का सशक्त क्षण है जो दुनिया भर के कलाकारों, दर्शकों और रचनाकारों को एकसाथ लाने की सिनेमा की विशिष्ट क्षमता को भी अभिव्यक्ति देता है। अकादमी पुरस्कारों का यह क्षण स्पष्ट करता है कि अब भावनात्मक शक्ति या साफ्ट पावर केवल राजनय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार अनेक आयोजनों, संस्थानों तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदानों तक हो गया है।

सिनेमा को अक्सर संबंधों को बढ़ावा देने का सटीक और व्यापक मंच माना जाता है और वह इस अवधारणा के केन्द्र में स्थित है। इस प्रकार 'नमस्ते एट द ऑस्कर्स, 2025' भारतीय कथावाचन की विरासत प्रदर्शित करने का माध्यम बन गया। इस कथावाचन को विविधतापूर्ण वैश्विक दर्शकों के समक्ष रखा गया जिससे सिनेमाई लेंस के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध स्थापित तथा मजबूत हुए। इस तात्कालिक प्रभाव से आगे जाते हुए इस आयोजन ने भविष्य में ऑस्कर्स तथा अन्य ऐसे ही वैश्विक मंचों की रूपरेखा परिभाषित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। इससे सांस्कृतिक भावना प्रसारित करने का क्षेत्र विस्तार हुआ।

इससे यह तय हुआ कि विभिन्न देश अपने रचनात्मक उद्योगों से किस प्रकार जुड़ते और सहयोग करते हैं। एक सरल व समयोचित 'नमस्ते' ने 'अतुलनीय भारत' को नई वैश्विक पहचान दिलाई तथा विश्व सिनेमा में इसकी सहभागिता को कभी-कभी पहचान से आगे बढ़ा कर रणनीतिक प्रभाव तक विस्तार दिया।

ऑस्कर्स की शुरुआत नमस्ते से करने का कोनन ओ ब्रायन का निर्णय केवल संयोग नहीं था। यह एक कथन और एक स्वीकारोक्ति थी कि भारतीय सिनेमा अब वैश्विक कथावाचन के हाशिए पर नहीं है। यह भारत का प्रतीकात्मक उल्लेख नहीं था और न इसमें एक बिलियन दर्शकों का सरसरी तौर पर हवाला दिया गया था। यह भारत की बढ़ती सिनेमाई विरासत और प्रभाव की स्वीकृति थी। भारत लंबे समय से ऑस्कर इतिहास का हिस्सा रहा है, पर अक्सर इसे बाहरी तत्व की तरह देखा जाता था। 1982 में गांधी ने व्यापक लोकप्रियता पाई, 2001 में लगान उसके निकट पहुंची तथा 2008 में स्लमडाग मिलीनियर्स अकादमी पुरस्कारों पर छा गई, लेकिन ये विमर्श ज्यादातर पश्चिमी फिल्मनिर्माताओं द्वारा पेश किए गए थे।

इस परिदृश्य में 2022 में आर से बदलाव शुरू हुआ जिसने न केवल नाटू नाटू के लिए ऑस्कर जीता, बल्कि वैश्विक दर्शकों को भारतीय फिल्मनिर्माताओं की स्पष्ट व उच्च ऊर्जा वाले कथावाचन को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। यह परिवर्तन 2024 में पायल कपाडिया की आल वी इमैजिन एज लाइट से मजबूत हुआ जिसने कैन्स में ग्रांड प्रिक्स जीता जो भारतीय सिनेमा को विरल सम्मान था। 2020 में आई चैतन्य तामहाने की द डिसिपिल, 2017 में रीमा दास की विलेज राकस्टार और 2018 में नंदिता दास की मंटो ने लगातार बाधायें तोड़ी थीं। उन्होंने सिद्ध किया था कि भारतीय सिनेमा अब स्टीरियोटाइप के बजाय विविधतापूर्ण व शक्तिशाली विमर्शों से संचालित है। इस नमस्ते की शक्ति को ऑस्कर्स से आगे ले जाना चाहिए। भारत इस समय कैन्स, 2025 की तैयारी कर रहा है।

ऐसे में यह क्षण हमारी स्थिति मजबूत करने के लिए एक अवसर की तरह देखा जाना चाहिए। वैश्विक फिल्म फेस्टिवलों में भारत का प्रतिनिधित्व रणनीतिक होने के साथ उससे यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इन प्लेटफार्मों पर भेजी जाने वाली फिल्में भारतीय कथावाचन की गहराई, विविधता और गतिशीलता को अभिव्यक्ति दें।

कैन्स फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है। 1946 में नीचा नगर ने पॉमे डी ओर जीता, जबकि 2015 में मसान को अनसरटेन रिगार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैन्स में भारत की विरासत दीर्घकालीन है। लेकिन अब समय आ गया है कि अलग-थलग विजयों को टिकाऊ प्रभाव में बदला जाए। सरकार और उद्योग को एकसाथ काम करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय सिनेमा न केवल सहभागी हो, बल्कि यह विमर्श को सक्रिय स्वरूप दे। 2012 में आई लाइफ आफ पी महत्वपूर्ण उदाहरण है कि ऐसे क्षण कैसे लहरें पैदा करते हैं। जब निर्देशक आंग ली को स्वर्वोत्तम निदेशक का आस्कर मिला तो उन्होंने दर्शकों का अभिवादन नमस्ते से किया जिससे फिल्म पर गहरा भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट हुआ। उस क्षण ने भारत की कथावाचन परंपराओं को मजबूत किया, लेकिन आस्कर्स, 2025 में नमस्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका संबंध केवल एक फिल्म से न होकर पूरे भारतीय सिनेमाई आंदोलन से था। भारत को अब इस गतिशीलता का लाभ 'वेव्स' जैसे मंचों से उठाना चाहिए जो देश में फिल्म निर्यात की पहल है।

वेव्स में भारतीय सिनेमा को नए बाजारों तक ले जाने की क्षमता है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि स्वतंत्र, क्षेत्रीय तथा मुख्यधारा रचनाकारों की फिल्में अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचें। नमस्ते क्षण की लहर पर सवार होकर वेव्स भारतीय सिनेमा को न केवल मनोरंजन, बल्कि महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शक्ति के रूप में पेश कर सकता है। रणनीतिक गठजोड़ों, अंतरराष्ट्रीय वितरण नेटवर्कों तथा प्रतिबद्ध ऑस्कर अभियानों को अब इस योजना का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि दक्षिण कोरिया 2019 में पैरासाइट को दुनिया भर में प्रोत्साहित कर ऑस्कर जीत सकता है तो भारत को भी अब व्यवस्थित रूप से अपनी सर्वोत्तम फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के दायरे में लाना चाहिए। इसका अर्थ केवल पहचान बनाने के बजाय विश्व सिनेमा में अपना अधिकार प्राप्त करना है।

आस्कर्स 2025 में नमस्ते हमारे लिए एक आह्वान होना चाहिए। यह एक चेतावनी होनी चाहिए कि भारतीय सिनेमा अब कल्पनालोक से उबर का कारंवाई वाला क्षेत्र बन गया है। अब यह सवाल नहीं है कि क्या भारतीय फिल्में आस्कर जीत सकती हैं, बल्कि इसका संबंध अब कब और कितनी बार से है। भारत अब विश्व फिल्म टेबल पर अतिथि न होकर आतिथेय, एक रचनाकार और एक इन्फ्लूएंसर बन गया है।

नमस्ते केवल एक अभिवादन न होकर दुनिया को आमंत्रण था कि वह भारतीय सिनेमा की सच्ची क्षमता स्वीकार करे। अब इस क्षण का लाभ उठाने का समय आ गया है। सही दृष्टिकोण और कार्रवाई से यह ऐसा महत्वपूर्ण दशक हो सकता है, जब भारतीय सिनेमा न केवल वैश्विक कथावाचन में शामिल हो, बल्कि उसका नेत्व्य करे। दुनिया ने अब भारत को स्वीकार कर लिया है। अब भारतीय सिनेमा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर फ्रेम, हर स्टोरी और हर फेस्टिवल नमस्ते की शक्ति प्रदर्शित करे। आस्कर्स, 2025 में नमस्ते अभिवादन से आगे बढ़ कर विश्व मंच पर भारतीय सिनेमा का पारिभाषिक क्षण था।

इसने कथावाचन में भारत के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए रणनीतिक उपस्थिति के रूप में उसे स्वीकार्यता दिलाई है। इस गतिशीलता को स्थाई बनाने के लिए भारत को वेव्स जैसे मंचों को स्वीकार करना चाहिए तथा वैश्विक गठजोड़ों को मजबूत करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फेस्टिवलों में हमारा प्रतिनिधित्व मजबूत हो। दुनिया ने भारत की सिनेमाई क्षमता स्वीकार कर ली है और अब समय आ गया है कि भारतीय सिनेमा इसका नेतृत्व करे। सही रणनीति से यह क्षण भविष्य को स्वरूप दे कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि भारतीय कथावाचन लगातार दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित और अभिभूत करता रहे।

# भारत-यूरोपीय संघ डिजिटल सहयोग

> यूरोपीय संघ और भारत अपने डिजिटल और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के अवसर का लाभ उठा रहे हैं।

**कुमारदीप बनर्जी**
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प दुनिया के सबसे लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर बनने में व्यस्त थे, तब वैश्विक ताकतें रणनीतिक पुनर्रेखण की दिशा में काम कर रही थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके उपाध्यक्ष जेडी वेंस द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को टेलीविजन पर फटकार लगाने के बाद, पूर्व को यूरोपीय संघ के कई नेताओं के साथ देखा गया।

जैसा भी मामला हो, यूरोपीय नेताओं के पास यूक्रेन को देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, सिवाय अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ शांति बनाने के एक सूक्ष्म संदेश के। यह समय की बात हो सकती है, इससे पहले कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को कीव में अपने बंकर कार्यालय को खाली करना पड़े और शायद वर्तमान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के विश्वदृष्टिकोण प्रतिनिधि के लिए रास्ता बनाना पड़े। दुनिया के लिए संदेश स्पष्ट था, अमेरिका अब उन अस्पष्ट राजनीतिक आख्यानों को वित्तपोषित करने में खुश नहीं होगा, जिन्हें संभावित रूप से एक मुक्त उदार विश्व व्यवस्था की पहचान माना जाता है। संयोग से, अमेरिका द्वारा विश्व युद्ध के बाद बनाई गई यह विश्व व्यवस्था, सभी की समृद्धि के लिए मुक्त, निष्पक्ष और खुले बाजारों को सुनिश्चित करती है।

पिछले कई दशकों में इस मुक्त विश्व व्यवस्था ने जो हासिल किया है, उस पर बहस की जा सकती है, हालांकि, इसने सुनिश्चित किया है कि अमेरिका आर्थिक समृद्धि सूचकांक में अपना वर्चस्व बनाए रखे और इसलिए भारत (1990 के दशक से) सहित कई सरिखित राष्ट्रों ने भी ऐसा किया है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच स्पष्ट टकराव से ठीक पहले, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने उच्च स्तरीय ईयू भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बातचीत को फिर से

स्थापित करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दिल्ली में किया। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक डिजिटल अर्थव्यवस्था और शासन था। यूरोपीय संघ (ईयू) और भारत ने रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी पर अपने कार्य समूह 1 के माध्यम से साझा मूल्यों पर जोर देते हुए डिजिटल सहयोग को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने मानक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने और अर्थव्यवस्थाओं और समाजों दोनों को लाभान्वित करने के लिए एआई, सेमीकंडक्टर, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग और 6 जी सहित प्रमुख प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दोनों पक्ष साइबर-सुरक्षित वैश्विक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक सुरक्षा में सुधार के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों पक्षों ने अपने-अपने डीपीआई के बीच अंतर-संचालन सुनिश्चित करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और व्यक्तिगत डेटा और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने सीमा पार डिजिटल लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-हस्ताक्षरों की पारस्परिक मान्यता पर भी चर्चा की।

सेमीकंडक्टर सहयोग पर, यूरोपीय संघ और भारत ने आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत करने और चिप डिजाइन और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों पक्षों ने एआई के जिम्मेदार विकास के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, संयुक्त परियोजनाओं और नैतिक एआई के लिए रूपरेखा के विकास के माध्यम से आगे के सहयोग पर सहमति व्यक्त की। वे जलवायु परिवर्तन और जैव सूचना विज्ञान जैसे क्षेत्रों में बड़े भाषा मॉडल और एआई अनुप्रयोगों पर सहयोग बढ़ाने की भी योजना बना रहे हैं। उन्होंने ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को लागू करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई, जिसे सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समर्थन दिया गया था, और सूचना समाज +20 पर आगामी विश्व शिखर सम्मेलन में बहु-हितधारक इंटरनेट शासन के लिए निरंतर वैश्विक समर्थन सुनिश्चित करना। यह यूरोपीय संघ और भारत दोनों के लिए सही क्लिक हो सकता है।

यूरोपीय संघ और भारत अपने डिजिटल और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। उनकी नई साझेदारी साझा मूल्यों और पारस्परिक आर्थिक हितों द्वारा समर्थित एक लचीले, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भविष्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का संकेत देती है। जैसे-जैसे पुराने गठबंधन बदलते हैं, नई साझेदारियां विकसित होती विश्व व्यवस्था की रूपरेखा को परिभाषित कर सकती हैं।

## आप की बात

### चुनाव आयोग की पहल

**चुनाव आयोग** मतदाताओं को विशिष्ट पहचान पत्र देने की पहल कर रहा है जिसमें एक जैसे एपिक नंबर होने की शिकायत खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग को कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सभी के लिए मतदान अनिवार्य करना चाहिए। विडंबना है कि लोग मुफ्त सुविधा लेने के लिए तो दौड़े चले आते हैं, पर मतदान के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। वे सरकारों को कोसते हैं मगर सरकार बनाते के लिए वोट नहीं देने जाते हैं। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए क्योंकि इसे एच्छिक करने के कोई अच्छे परिणाम नहीं आए हैं। आखिरकार विपक्षी दल इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? एक ही प्रत्याशी के दो स्थानों से चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए या फिर दोनों स्थानों से चुनाव जीतने पर छोड़ने वाली सीट पर फिर से चुनाव के बजाए दूसरे नंबर पर आए प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाना चाहिए। इससे जनता के धन की बचत होगी तथा अनावश्यक चुनाव से भी मुक्ति मिलेगी। हाल ही में सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने अनिवासी भारतीयों को मतदान अधिकार देने पर गंभीरता से विचार का आह्वान किया है। यह सुझाव स्वागत योग्य है और इसका जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती देगा।

**-सुभाष बुड्डावन वाला,** रतलाम

### यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका

**गुरुवार** 6 मार्च को ब्रसेल्स में 27 यूरोपीय देशों के बैठक के बाद लगता है कि यूरोप हर बार की तुलना में इस बार यूक्रेन को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब उन्हें भी लग रहा है डोनाल्ड ट्रम्प पर किसी का वस नहीं है। ट्रम्प किसी के नहीं हैं, वे एक व्यापारी हैं और हर काम के बदले उनको पैसा चाहिए। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वैलेरी जालुज्नी ने दावा किया है कि अमेरिका स्थापित विश्व व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। व्हाइट हाउस ने पश्चिमी दुनिया की एकता पर सवाल उठाया है और रूस की ओर अधिक से अधिक दोस्ताना कदम बढ़ा रहा है जिसने 2022 में यूक्रेन पर व्यापक आक्रमण शुरू कर दिया था। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के 27 देशों को ही नहीं, बल्कि यूरोप के तमाम 44 राष्ट्रों को यूक्रेन पर आक्रमण को खुद पर आक्रमण मान कर काम करना चाहिए। लगता है कि इनमें हंगरी, स्लोवाकिया और इटली इस समय व्हाइट हाउस तथा क्रेमलिन के डबल एजेंट हैं। यूरोप के देशों ने रूस को 217 अरब डॉलर की सम्पति जब्त की है। उसका इस्तेमाल भी यूक्रेन के बचाव एवं पुनर्निर्माण पर किया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि यूरोप अमेरिका का दबाव कहां तक बर्दाश्त कर सकता है।

**- जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

### महिलाओं से अभद्रता

**महिला दिवस** पर महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाएं भी उजागर हो रही हैं। महाराष्ट्र में मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ पर पूरे देश में नेताओं की व्यापक बयानबाजी हुई कि जब मंत्री की बेटी ही सुरक्षित नहीं हैं तब देश की आम बहन-बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? तमिलनाडु के कुन्नूर में हिंदी के विरोध में हुए आयोजन में महिलाओं से अभदता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे वीआईपी महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। महिला दिवस पर बड़े-बड़े कार्यक्रमों में महिला सशक्तीकरण पर भाषण और उपदेश दिए जाएंगे। लेकिन महिलाओं से बढ़ती अभद्रता और उनकी सुरक्षा को लेकर पैदा चिन्ताओं से ये सारी बातें केवल कल्पना की उड़ान बन कर रह जाएंगी। हाल ही में सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ना चाहिए। सबसे प्रमुख बात परिवार और समाज में लड़कों और पुरुषों को इसकी शिक्षा देना है कि वे हर हालत में महिलाओं को अपने बराबर तथा समान रूप से सक्षम समझें।

**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

### जैविक खेती का महत्व

**जैविक खेती** का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैविक खेत में गोमूत्र, गोबर, आदि का उपयोग खाद व पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है जिसके चलते बिना केमिकल के भी पर्याप्त उपज होती है। क्षेत्रतम बीजों का उपयोग करने से उपज की क्वालिटी भी अच्छी होती है। खेती में स्वदेशी बीजों का प्रयोग भी होना चाहिए क्योंकि विदेशों से आयातित बीजों के साथ विषैली गाजर घास जैसे खरपतवार भी आ गए हैं। परंपरागत भारतीय कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक शोध का समन्वय कर खाद व पेस्टिसाइड पर खर्च होने वाला पैसा बचाया जा सकता है। केमिकल के बिना उत्पादित फल, सब्जियां और अनाज अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। पेस्टिसाइड व रासायनिक खाद के उपयोग से जमीन में विषाक्तता बढ़ गई है, इसने भूजल को भी विषाक्त कर दिया है तथा इनसे धरती की उर्वरा क्षमता भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों तथा शहरों और कस्बों में छोटे-बड़े गमलों में लोग अपने उपभोग के लिए जैविक तरीके से फल और सब्जियां उगा सकते हैं जो हर प्रकार से लाभकारी होंगे।

**- विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
कुसंग का ज्वर अत्यंत घातक होता है

# ब्रिटेन की लीपापोती

इस पर आश्चर्य नहीं कि लंदन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के समक्ष खालिस्तान समर्थकों के उत्पात और भारतीय ध्वज के अपमान पर ब्रिटेन सरकार की सफाई भारतीय विदेश मंत्रालय को रास नहीं आई, लेकिन भारत को असंतोष प्रकट करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे ब्रिटेन को इसके लिए बाध्य करना चाहिए कि वह ऐसी भारत विरोधी हरकतों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और यह किसी से छिपा नहीं कि ब्रिटेन ने हर बार निंदा-आलोचना करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कारणों से अपने यहां सक्रिय खालिस्तान समर्थकों को भारत विरोधी गतिविधियों से मुंह मोड़े हुए है। इसी कारण उनका दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है। अतीत में वे भारतीय उच्चायोग पर धावा बोलने के साथ गुरुद्वारा पहुंचे भारतीय उच्चायुक्त पर हमले की कोशिश कर चुके हैं। इसके अलावा वे जब-तब सार्वजनिक रूप से भारतीय ध्वज का अपमान करते रहते हैं और अपनी दुष्टता के खिलाफ आवाज उठाने वाले ब्रिटिश सिखों को धमकाते भी रहते हैं। इसका कारण यही है कि ब्रिटेन उनसे कड़ाई से निपटने के लिए तैयार नहीं। भारत ने यह सही कहा कि खालिस्तान समर्थक तत्वों को यह पता है कि ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगी।

यदि ब्रिटेन खालिस्तान समर्थक तत्वों को मूक समर्थन देते रहता है तो भारत को मुक्त व्यापार समझौता संबंधी वार्ताओं को स्थगित करने की हद तक जाने से संकोच नहीं करना चाहिए। इसी के साथ उसे खालिस्तान समर्थक तत्वों को पहचान कर उनके ओसीआइ यानी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड रद्द कर उनके भारत आने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत में उनकी संपत्तियों को जब्त भी किया जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में रह रहे खालिस्तान समर्थकों के भी खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन की तरह वे इन देशों में भी बेलगाम हैं। वे कनाडा और आस्ट्रेलिया में अनेक हिंदू मंदिरों को निशाना बना चुके हैं। भारत को यह समझना होगा कि पश्चिमी देश उसकी नाराजगी को हल्के में लेते हैं और जानबूझकर खालिस्तान समर्थकों की अनदेखी करने में लगे हुए हैं। जब भारत अपनी कठोर कार्रवाई से इन देशों को यह संदेश देगा कि वह खालिस्तानी अतिवादियों की हरकतों को सहन करने के लिए तैयार नहीं, तभी वे अपने लीपापोती वाले रवैये का परित्याग करने के लिए तैयार होंगे। भारत को विदेश में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथियों को इसलिए गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि उनकी आक्रामकता बढ़ती जा रही है। वे खुद को संगठित करके अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने की फिराक में हैं। उनकी गतिविधियां भविष्य में भारत और विशेष रूप से पंजाब में माहौल खराब कर सकती हैं। इसके पहले स्थितियां बिगड़ें, भारत को सक्रिय होना होगा।

# सतर्कता जरूरी

तकनीकी सुविधाएं बढ़ने के साथ ही झारखंड में साइबर अपराध का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। एटीएम, क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पर, योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर, नौकरी एवं अन्य सुविधाएं देने के नाम पर और कभी निवेश तो कभी लाटरी के नाम पर लोगों को साइबर ठग बेवकूफ बनाकर उनकी गाढ़ी कमाई बैंक खाते से उड़ा रहे हैं। गूगल पर फर्जी नंबर डालकर भी साइबर ठग बैंकों, कंपनियों और संस्थानों के फोन काल अपने पास मंगाकर लोगों को ठग रहे हैं। जाहिर है गूगल जैसी बड़ी कंपनियों से लेकर पुलिस तक को इसपर रोक लगाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। वहीं आम आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरते और हड़बड़ी में या दबाव में या बिना सोचे-समझे फोन काल पर अथवा इंटरनेट पर कोई निर्णय लेकर उसे कार्यरूप नहीं दे। सीआइडी ने हाल ही में नालंदा के एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने गूगल पर एक सीमेंट कंपनी के फोन नंबर की जगह अपना नंबर डाल दिया था। उसके झांसे में फंसकर एक व्यक्ति ने उसे सीमेंट के आर्डर देते हुए 20 लाख रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया। कस्टमर केयर के नंबर बदल कर अपना नंबर डाल देने में अगर साइबर ठग सफल हो रहे हैं तो इसे पुलिस और संबंधित वेबसाइट की विफलता कहा जा सकता है। सभी को मिलकर ऐसी घटनाओं पर विराम लगाना होगा।

साइबर ठगी से बचने के लिए हर स्तर पर सतर्कता जरूरी है। इसके लिए सतत प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए

# परिसीमन में साधना होगा संतुलन

आदित्य सिन्हा

**नए परिसीमन में यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ती जनसंख्या से लेकर विकास के प्रति गंभीरता का भी बराबर ख्याल रखा जाए**

अवधेश राजपूत

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में प्रतिनिधित्व का पैमाना अभी तक 1971 की जनगणना पर ही अटका हुआ है। इसके पीछे यही तर्क रहा कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर संभावित नुकसान से बचाना। हालांकि यह समयसीमा 2026 में समाप्त हो रही है और अब नए सिरे से परिसीमन प्रस्तावित है। इसे लेकर बहस भी शुरू हो गई है। दक्षिणी राज्यों की आशंका सत्ता रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के उनके प्रयासों को नए परिसीमन की पलीता लग सकता है। इसी कारण इन राज्यों में विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक प्रकार से इस अभियान की कमान भी संभाल रखी है। दक्षिण के अन्य राज्य भी उत्तर भारत के वर्चस्व को लेकर सशंकित होने के कारण उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे स्वरों को शांत करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन भी दिया है कि परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के हितों पर कोई आघात नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय संविधान ने एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया की संकल्पना की थी, जिसमें प्रत्येक सांसद कमोबेश बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करे। संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170(3) में यही व्यवस्था की गई है कि समय-समय पर सीटों का नए सिरे से परिसीमन किया जाए जिसमें जनसंख्या परिवर्तन के रुझान को अपेक्षित रूप से समायोजित किया जा सके। इस समय भारत का चुनावी मानचित्र 1971 की जनगणना पर अटका हुआ है, जब उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की जनसंख्या में उतना अंतर नहीं था, जितना आज है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी 24 करोड़ से अधिक है जो तमिलनाडु से लगभग दोगुनी है, लेकिन उसकी लोकसभा सीटें अभी भी 1971 के स्तर पर ही हैं। क्या यह उचित है?

यदि परिसीमन के लिए मौजूदा जनसंख्या पैमाना बनी तो तय है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में लोकसभा सीटें खासी बढ़ेंगी। जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सीटें अपेक्षाकृत घटेंगी। स्वाभाविक है कि दक्षिणी राज्यों के लिए यह घाटे का सौदा होगा। उन्हें लगेगा कि बेहतर गवर्नेंस के बावजूद उन्हें दंडित किया जा रहा है? दशकों से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से जुड़े प्रयासों में भारी निवेश किया है, जिसने जनसंख्या वृद्धि को थामा है। इसी बीच कई उत्तरी राज्यों में जन्मदर ऊंची बनी हुई है। इसके बावजूद उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ जाएगी। फिर सवाल उठेगा कि क्या लोकतंत्र में अक्षमताओं को पुरस्कृत किया जाता है? वैसे भी क्षेत्रीय क्षत्रप परिसीमन के मुद्दे को संघीय ढांचे के लिए अपने संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तमिलनाडु और केरल की दलील है कि प्रतिनिधित्व की कसौटी केवल जनसंख्या न होकर विकास संबंधी उपलब्धियां और आर्थिक योगदान भी होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इस समय ऐसी आवाजें शांत हैं, जो रह-रहकर 'जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी' का राग अलापती रहती हैं।

उत्तर-दक्षिण विभाजन की बहस के अलावा संभावित परिसीमन की राह में और भी चुनौतियां हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है एससी-एसटी के लिए निर्धारित सीटों का समायोजन। उनके प्रतिनिधित्व में जनसांख्यिकीय बदलाव झलकना ही चाहिए, पर यह सुनिश्चित करना मुश्किल है। ध्यान रखना होगा कि इस कवायद में राजनीतिक समीकरण न बिगड़ें। एक और चुनौती शहरी-ग्रामीण असंतुलन के स्तर पर होगी। तेजी से हुए शहरीकरण से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं बदला है। क्या अपने आर्थिक महत्व के चलते शहरी केंद्रों को अधिक सीटें नहीं मिलनी चाहिए या ग्रामीण प्रतिनिधित्व को संरक्षण प्रदान कर सुनिश्चित किया जाए कि राजनीतिक गलियारों में उनकी आवाज कमजोर नहीं पड़ेगी? शहरों में भारी पैमाने पर हुए पलायन ने स्थिति और जटिल बना दी है। कई शहरों में विस्थापित श्रमिकों की बड़ी आबादी है। ये श्रमिक काम तो शहरों में करते हैं, मगर इनमें से अधिकांश के वोट मूल स्थानों पर होते हैं। ऐसे में परिसीमन कुल आबादी की संख्या पर, यह पहलू भी विभिन्न क्षेत्रों के बीच शक्ति संतुलन साधने में अहम भूमिका निभाएगा।

परिसीमन के परिदृश्य पर संभावित समाधानों एक सुझाव यही दिया जा रहा है कि अगले 30 वर्षों के लिए पुरानी व्यवस्था को ही यथावत कायम रखा जाए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्यों को कोई खामियाजा न भुगतना पड़े। हालांकि इससे वह बिसंगति कायम रह जाएगी, जहां कुछ सांसद अपने अन्य साथियों की तुलना में कहीं बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। एक समाधान यह भी हो सकता है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। इससे किसी क्षेत्र में सीटों की संख्या में कटौती किए बिना जनसंख्या को सही प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा। इससे किसी क्षेत्र में असंतोष भी नहीं भड़केगा। कुछ विशेषज्ञ जीडीपी योगदान, साक्षरता दर और गवर्नेंस सक्षमता जैसे कारकों को भी परिसीमन में महत्व देने की पैरवी कर रहे हैं। हालांकि यह काफी जटिल होगा और संभव है कि उत्तरी राज्यों में राजनीतिक वर्ग इसका विरोध करे।

परिसीमन संवेदनशील मुद्दा है, जिसे सुलझाने के लिए समग्र दृष्टिकोण चाहिए। इसमें सुनिश्चित करना होगा कि सभी राज्य और प्रमुख हितधारक सक्रिय सहभागिता के साथ किसी स्वीकार्य समझौते पर सहमत हों, जिसमें प्रतिनिधित्व, गवर्नेंस और क्षेत्रीय हितों का संतुलन साधा जा सके। ऐसा संतुलन, जिसमें बढ़ती आबादी से लेकर विकास के प्रति गंभीरता का बराबर ख्याल रखा जाए। उसमें कोई स्वयं को राजनीतिक हाशिये पर न देखे और समान लोकतांत्रिक सहभागिता संभव हो सके। इस मुद्दे को संजीदगी से संभालना होगा, क्योंकि परिसीमन लोकतांत्रिक शुचिता बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक मत के महत्व और संघीय सिद्धांतों के प्रति सम्मान का भी प्रतीक होगा।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

# आत्मनिर्भर बन रही आधी आबादी

अन्नपूर्णा देवी

**आज हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही महिलाएं अपने दायित्व पूरी कुशलता से निर्वहन कर रही हैं**

एक सम्मेलन में महिला शांति सैनिक। एएनआइ

आदिकाल से ही भारत में महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है। नारी पूजा का भाव, विचार और विश्वास भारतीय मानस में बसा हुआ है। 'शतपथ ब्राह्मण' में उल्लेख है कि श्रीराम के गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में संगीत शिक्षण उनकी विदुषी पत्नी अरुंधति ही करतीं थीं। ऋग्वेद में भी गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी अनेक ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। दुख का विषय है कि स्त्री शिक्षा की इतनी गौरवपूर्ण और स्वर्णिम परिपाटी परवर्ती काल में ख़ासतौर से मध्ययुग में आक्रांताओं के शासनकाल और उसके बाद फिरंगियों की गुलामी के दौरान छिन्न-भिन्न होती चली गई। आजादी के संघर्ष के दौरान और आजादी के बाद महिलाओं का समाज में पुनः कुछ सम्मान बढ़ा, लेकिन उनकी प्रगति की गति दशकों तक धीमी रही। गरीबी और निरक्षरता महिलाओं के सशक्तीकरण में गंभीर बाधा रही है। महात्मा गांधी ने 23 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में कहा था, 'जब महिला, जिसे हम अबला कहते हैं, सबला बन जाएगी तो वे सभी जो असहाय हैं, शक्तिशाली बन जाएंगे।' बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने भी सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा, 'सामाजिक न्याय के लिए महिला सशक्तीकरण जरूरी है, तभी समाज में महिला का उत्थान हो सकता है।' महिलाओं के उत्थान से ही स्वतंत्रता, सम्मानता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक विचारों के साथ समाज का पुनर्निर्माण संभव है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम का संदेश महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए ठोस और तेजी से कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देना है। मोदी सरकार इसी दिशा में सक्रिय है। हमारी सरकार ने विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण हेतु अनेक ठोस कदम उठाए हैं। ये नीतियां महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। पिछले दस वर्षों में महिला सशक्तीकरण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जमीन पर लाभ दिखना शुरू हो गया है। गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना हो, स्वास्थ्य और सुविधा में सुधार हेतु 'उज्ज्वला योजना' हो या बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सुकन्या समृद्धि योजना' हो, महिलाओं-बेटियों का हित भारत सरकार की प्राथमिकता है। मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन कर महिलाकर्मियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। मोदी सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों को मदद के लिए शुरू की गई मुद्रा लोन योजना में महिलाओं की भागीदारी 69 प्रतिशत है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा स्टैंडअप इंडिया के तहत खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ऋण दिया जाता है, जिसके तहत अब तक 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' और 'मिशन शक्ति' जैसे योजनाओं एवं 'सेल्फी विद डाटर' जैसी पहल ने बालिकाओं-युवतियों के लिए नया आसमान खोला है। महिला स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी सशक्तीकरण योजना द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी भागीदारी को बढ़ाने के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। आज भारत की नारी एक नए आर्थिक क्षितिज की ओर भी अग्रसर है। शिक्षा, सफलता की महत्वपूर्ण सीढ़ी मानी जाती है। मोदी सरकार के शासन में उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक रूप से बढ़ रही है। 2014-15 के बाद से उच्च शिक्षा में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिला नामांकन दर 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हो गई है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' द्वारा संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का अहितीय कार्य हो, तीन तलाक कानून द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए महिला बटालियनों का गठन हो अथवा शिक्षा और कौशल विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए संस्थान और ट्रेनिंग प्रोग्राम हों, मोदी सरकार महिलाओं की अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्पित है। कला, खेल, अभिनय, राजनीति से लेकर सरकारी नौकरियों और प्रोफेशनल जगत, सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाएं अपनी भागीदारी न सिर्फ सुनिश्चित कर रही हैं, बल्कि अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए अपनी धाक भी जमा रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी जब विकसित भारत के लिए अपने चार स्तंभों की बात करते हैं तो उसमें महिलाएं भी एक हैं। जब विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में महिलाओं की चतुर्दिक भूमिका होने वाली है, तब हमें महिलाओं की क्षमता समझने की जरूरत है। विकसित एवं सशक्त भारत की निर्माण यात्रा महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के जरिये ही संपन्न होगी।

(लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

## हंसना जरूरी है

हंसना शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत सहायक है। हंसी अनेक समस्याओं का समाधान है। हंसी दुखी दिल के घावों को भरने वाला मरहम है। हमारे चेहरे का व्यायाम है और मन का आराम। सेहत का एक मंत्र यह है कि आप खुलकर हंसें। बात-बेबात हंसते और हंसते रहना सफल एवं सार्थक जीवन का मंत्र है, पर कई बार पूरा दिन बिना हंसे निकल जाता है। उदासी और बेचैनियों के बादल छाए रहते हैं। हंसी के बिना बीता दिन, अंधेरे में रहने जैसा है। आप अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, पर उसे साफ-साफ नहीं देख पाते। हंसना एक ऐसा सकारात्मक भाव है, जो व्यक्ति के न केवल आंतरिक, बल्कि बाहरी स्वरूप को भी समृद्धशाली एवं प्रभावी बनाता है। हास्य एक शक्तिशाली भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और संसार को शांतिपूर्ण बनाने की क्षमता है। हास्य व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब व्यक्ति समूह में हंसता है तो उसकी हंसी से सकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण परिवेश में व्याप्त हो जाती है।

आज के अशांत, चिंतित एवं तनावपूर्ण परिवेश में व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट एवं हंसी को भूलता जा रहा है। फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, शुगर, माइग्रेन, हिस्टीरिया, पागलपन, अवसाद आदि की निमंत्रण दे रहा है। हंसने से शरीर में ऊर्जा और आक्सीजन का संचार अधिक होता है। शरीर से दूषित वायु बाहर निकल जाती है। जोर-जोर से हंसने से पूरे शरीर में प्रत्येक अंग को गति मिलती है, शरीर के सभी अवयव ताकतवर होते हैं और पाचन तंत्र अधिक कुशलता से कार्य करता है। हमें हंसाने वाले लोग हमारी स्मृतियों में बस जाते हैं। हंसना एक ऐसा उपहार है, जिससे जीवन समृद्ध होता है। हास्य एक सार्वभौमिक भाषा है। इसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग से परे रहकर मानवता के समन्वय की क्षमता है। यह मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने का उपक्रम है।

ललित गर्ग

# चंद्र अन्वेषण में निजी कंपनियों का बढ़ता दखल

प्रदीप

**चंद्र अन्वेषण अब केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी कंपनियां भी इसमें तेजी से आगे बढ़ रही हैं**

20वीं सदी के उत्तरार्ध तक चंद्र अभियानों की बागडोर पूरी तरह से सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के हाथों में थी। अमेरिका की नासा, रूस की रैस्कोस्मोस और भारत की इसरो जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां ही चंद्र अभियानों का संचालन करती थीं, लेकिन 21वीं सदी में यह परिदृश्य बदल रहा है। अब निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और चंद्र अन्वेषण में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। हाल में अमेरिकी निजी कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस ने अपने ब्लू घोस्ट लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारकर इतिहास रच दिया। यह मिशन नासा के कामर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज (सीएलपीएस) के तहत भेजा गया तीसरा मिशन था।

हाल के वर्षों में कई निजी कंपनियां चंद्र अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। स्पेसएक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, न केवल पृथ्वी की कक्षा में मिशन भेज रही है, बल्कि उसने नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए स्टारशिप राकेट भी विकसित किया है, जो भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लू ओरिजिन, जो जेफ बेजोस की कंपनी है, चंद्रमा के लिए नए लैंडर और अंतरिक्ष यान विकसित कर रही है। इंट्यूटिव मशीन भी नासा के सहयोग से चंद्रमा पर मिशन भेज रही है, जबकि जापान की आइस्पेस अगले वर्ष नए मिशन के साथ चंद्रमा पर उतरने की योजना बना रही है। फायरफ्लाई एयरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लैंडर एक महत्वपूर्ण मिशन है, जो चंद्र अन्वेषण में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह लैंडर जनवरी 2025 में फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया था। यह चार पैरों वाला एक छोटा रोबोटिक यान है, जिसकी ऊंचाई दो मीटर। इस लैंडर में एक विशेष वैक्यूम उपकरण और ड्रिल लगी है, जो चंद्रमा की सतह से 10 फीट गहराई तक खोदाई कर सकती है और वहां का तापमान रिकार्ड कर सकती है।

चंद्र अन्वेषण में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के पास सीमित बजट होता है, जबकि निजी कंपनियां अल्प लागत में अधिक प्रभावी समाधान देने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, नासा के अपोलो मिशन पर अरबों डालर खर्च हुए थे, जबकि निजी कंपनियां अपने मिशनों को कम बजट में संचालित कर रही हैं। तकनीकी नवाचार भी एक बड़ा कारण है। निजी कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही हैं, जिससे अंतरिक्ष अभियानों की लागत कम हो रही है और मिशनों की सफलता दर बढ़ रही है। इसके अलावा, चंद्रमा पर संसाधनों के दोहन की संभावना भी निजी कंपनियों को आकर्षित कर रही है। भविष्य में चंद्रमा पर हीलियम-3, पानी और अन्य खनिजों का खनन किया जा सकता है, जिससे इन कंपनियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

## मेलबाक्स

### हिंदू विरोधी मानसिकता

भारत में प्रताड़ित हिंदू जनमानस के कुछ सेक्युलर प्रतिनिधि मुगल आक्रांताओं के प्रेम में डूबे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को समझ होती कि उनके औरंगजेब की प्रशंसा से भारत के संपूर्ण हिंदू आहत और उद्वेलित हो जाएंगे तो उनका साहस भी नहीं होता कि वह ऐसा अनर्गल वक्तव्य देते, परंतु वास्तविकता यह है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विरोधी अब सामूहिक रूप से हिंदू विरोधी हो गए हैं। अबू आजमी अकेले नहीं हैं, बल्कि कई अन्य नेता हिंदुओं और सनातन को टारगेट किए हुए हैं। ये सभी प्रमुखतः से हिंदू ही हैं, परंतु लगता है कि अपने अपमान, दमन, प्रताड़ना और उपहास से संतुष्ट हैं। दूसरा पक्ष यह है कि भारत में सभी ईसाई और मूलतः सभी मुस्लिम हिंदुओं से धर्मांतरित हुए हैं। पिछले दशक में ऐसे घृणा की राजनीति करने वाले नेता और दल दिवालिया हो रहे हैं और महाकुंभ में संपूर्ण भारत के प्रत्येक क्षेत्र से करोड़ों हिंदुओं ने उनको एकता का संदेश दे दिया है। बालीवुड की नई फिल्म छावा ने भी वह जनजागरण किया है, जैसे कि कश्मीर फाइल्स ने किया था, परंतु जो 75 वर्षों से जहर की खेती करते आए हों, उन खेतों को बंजर होने में समय लगेगा और वह नफरत के सौदागर शहद तो नहीं बेच सकते। आत्मग्लानि से भरे सेक्युलर हिंदुओं को अभी एक और महाकुंभ की प्रतीक्षा है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

### पुलिस तंत्र में सुधार का इंतजार

'पुलिस का कर्म' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में पुलिस तंत्र में सुधार पर बेहद गंभीरता से चिंतन किया गया है। देश में पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का यह हस्तक्षेप प्रशंसनीय है। वर्तमान में हमारे देश में जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों का न होना चिंताजनक है। रिक्तियों को लंबे समय तक न भरना या उसमें अनावश्यक विलंब करना देश के नागरिकों के साथ अन्याय है, क्योंकि इससे सीमित पुलिसकर्मियों पर कार्य का शारीरिक-मानसिक दबाव तो बनता ही है, साथ ही जनता को गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवा भी नहीं मिल पाती। राष्ट्र के निवासियों की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटक पुलिस है, जिसकी छवि तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण धूमिल हो रही है। इसे सुधारने की कवायद के प्रति हमारी राज्य सरकारें गंभीर प्रतीत नहीं होतीं। पुलिस पर कार्य के अतिरिक्त बोझ को कम कर, उनकी संख्या बढ़ाकर और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर कानून के सिपाहियों की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। यह विडंबना ही है कि सरकारों की उदासीनता के कारण लगभग हर मुद्दे का निराकरण करने की पहल सर्वोच्च न्यायालय को करनी पड़ रही है। यह विचारणीय है कि स्वयं न्यायपालिका भी जनशक्ति के इस अभाव से जूझ रही है। देश में कार्य करने वालों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उन्हें सही समय पर मौका दिया जाए। पुलिस तंत्र में सुधार से कानून व्यवस्था में भी अपेक्षित सुधार आएगा।

मोहित सोनी, कुल्ही, मध्य प्रदेश

### अमेरिका किसी का सगा नहीं

ट्रंप का अमेरिका में शोहरा आना विश्व के लिए चिंताजनक है। अमेरिका फर्स्ट या अमरीका थेक ग्रेट अगेन का मतलब ये तो नहीं कि दूसरों को अहमियत देना ही बंद कर दो। एक तरफ तो रूस-यूक्रेन युद्ध बंद कराने की कोशिश करते हैं, जेलेंस्की को अपने बातें युद्ध बुलाते हैं फिर उनहें जलेंस्की करके भगा देते हैं। वह कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक युद्धरत राष्ट्र के प्रमुख हैं। युद्ध बंदी के लिए उनके खनिज उद्योग पर कब्जा करने की बात करते हैं। उनकी सारी सहायता रोक देते हैं। ट्रंप मानों गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। आते ही चीन, कनाडा और मेक्सिको के साथ व्यापार युद्ध शुरू कर दिए। अब भारत को भी धमका रहे हैं कि दो अप्रैल से भारत पर भी टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। उनके साथ समझौते करना भी किसी जोखिम से कम नहीं है, पता नहीं कब मुकर जाएं। मुकरने की तो ट्रंप की पुरानी आदत है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई नहीं जिसे डराने डगा नहीं।

चंद्र प्रकाश शर्मा, गनी बाग, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेंद्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेंद्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

**700** अरब डालर तक की वृद्धि होने की उम्मीद है भारत की जीडीपी में इसवर्ष के अंत तक, श्रम बल भागीदारी और उत्पादकता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की दशा में, मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार।

विजया रहाटकर
अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

# विकसित भारत में स्त्रीशक्ति की भूमिका

**महिलाएं आज लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ऐसे में जब 2047 तक भारत ने विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया, तो हम सबको मिलकर इस दिशा में नए सिरे से प्रयास करना होगा। महिलाओं को यदि उनके कार्यक्षेत्र में समान अवसर और वेतन के साथ ही समुचित सम्मान मिले तो विकसित राष्ट्र बनने का हमारा स्वप्न समय से साकार हो सकेगा। इसके लिए सरकार की नीतियों के साथ ही सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं के प्रति सोच एवं मानसिकता में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है**

पिछले एक दशक से हमारा देश निरंतर तीव्र गति से विकास पथ पर अग्रसर है। इसमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं का भी योगदान है। परंतु कई क्षेत्रों में यह देखने में आ रहा है कि महिलाओं का योगदान अपेक्षित रूप में देश के विकास की धारा में शामिल नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके अनेक कारण हैं, जिन्हें समझते हुए उन्हें दूर किया जाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जब तक नारी जागरूक होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं देगी, तब तक विकसित भारत का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। नारी मात्र गृहस्थी की शोभा ही नहीं, अपितु समाज की आधारशिला भी है। अनेक बाधाओं के बावजूद, वह अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से कार्यक्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, परंतु यह प्रश्न आज भी वैश्विक विचार-विमर्श का विषय है कि क्या यह प्रगति पर्याप्त है? नारी केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्राण शक्ति भी है। यदि भारत को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है तो नारी को सहभागिता अनिवार्य है। विश्व बैंक के अनुसार, यदि भारत में नारी श्रम शक्ति की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो अर्थव्यवस्था में 700 अरब डालर की वृद्धि संभव है। इससे यह भी पता चलता है कि नारी शक्ति का उत्थान हुए बिना कोई भी राष्ट्र समग्र विकास का स्वप्न नहीं देख सकता।

**सरकारी नीतियां और प्रविधान** : नारी को श्रम क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं और कानून लागू किए हैं। आज महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है, ताकि वे मातृत्व और अपने करियर के बीच में संतुलन बना सकें। समान वेतन अधिनियम, 1976 स्त्री और पुरुष को समान कार्य हेतु समान वेतन देने की गारंटी देता है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के दस वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह मात्र एक नारा नहीं, बल्कि यह बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन है, जिसने बेटियों के प्रति समाज का नजरिया बदला। इसकी एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि इससे देश में लिंग अनुपात में सुधार हुआ तथा बालिकाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई।

इसके अतिरिक्त, महिला श्रमिक सुरक्षा योजना महिला श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। स्टैंड-अप इंडिया योजना महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करती है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 एक महत्वपूर्ण कदम है जो कार्यस्थल पर उनके अधिकारों की रक्षा करता है।

**समाज की भूमिका** : कोई भी कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब समाज भी उस बदलाव का पक्षधर हो। इस लिहाज से केवल सरकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं हैं, समाज को भी नारी के श्रम और योगदान को उचित सम्मान देने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। भारतीय समाज में अब भी पुरुष प्रधान मानसिकता मौजूद है जो नारी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इस स्थिति को बदलने में परिवार का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि घर का वातावरण सहयोगी होगा तो नारी आत्मनिर्भर बन सकती है। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण महिलाओं को कार्यक्षेत्र में अधिक सक्षम बनाते हैं।

नारी को समान वेतन देने का मुद्दा वैश्विक चिंतन का विषय है। संयुक्त राष्ट्र बार-बार वेतन समानता का आह्वान करता रहा है और सतत विकास लक्ष्यों में लैंगिक समानता को एक प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला (यूएन वूमेन) एवं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे विश्व में महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 20 प्रतिशत कम वेतन पाती हैं। यह अपनेआप में एक बड़ी विडंबना है। इस समस्या के समाधान के लिए यूएन वूमेन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 'समान वेतन अंतरराष्ट्रीय गठबंधन' की शुरुआत की है जिससे पूरे विश्व में समान वेतन की नीति बनाई जा सके। जी-7 और जी-20 समिट में भी यह विषय चर्चा का प्रमुख बिंदु रहा है और भारत भी इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

**नारी वेतन विषमता के कारण** : विश्व के अनेक देशों में आज भी महिलाएं समान वेतन पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसके कई कारण हैं जिनमें सामाजिक दृष्टिकोण प्रमुख है। कई स्थानों पर महिलाओं को 'द्वितीयक कमाने वाली' माना जाता है जिससे उनको कम वेतन दिया जाता है। कार्यस्थल में शीर्ष पदों पर पुरुषों का वर्चस्व भी वेतन असमानता का मुख्य कारण है, क्योंकि निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की कम उपस्थिति उनके वेतन और पदोन्नति को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, महिलाएं कार्यस्थल और परिवार के बीच संतुलन बनाने के प्रयास में पदोन्नति और वेतन वृद्धि से वंचित रह जाती हैं। महिलाएं प्रायः वेतन बढ़ाने की मांग करने से हिचकिचाती हैं जिससे वे आर्थिक रूप से पिछड़ जाती हैं।

यदि नारी को कार्यक्षेत्र में समान अवसर, वेतन और सम्मान मिले तो विकसित भारत का स्वप्न शीघ्र ही साकार हो सकेगा। सरकार की नीतियों और वैश्विक विचार-विमर्श के साथ यदि सामाजिक मानसिकता भी परिवर्तित हो तो यह समस्या दूर हो सकती है। जब नारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी निभाएगी, तब ही भारत पूर्णतः विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। किसी समाज के प्रभावशाली विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण जैसा कोई साधन नहीं, क्योंकि कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता, जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिला कर न चलें।

शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। फाइल

## महिलाओं को सशक्त बनाना बड़ा आर्थिक निर्णय

प्रिया अग्रवाल रेवार
नान-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वेदांता

भारत के गांवों और नगरों में एक मूक किंतु शक्तिशाली बदलाव नजर आ रहा है। महिलाएं उद्यमी और बदलावकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह बदलाव आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने से भी जुड़ा है। आर्थिक सशक्तीकरण रोजगार तक सीमित नहीं है, इसका अर्थ है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाना। लोगों के सोच में बदलाव आने लगा है, लेकिन सिस्टम की चुनौतियां कायम हैं।

वस्तुतः एक शिक्षित महिला आर्थिक संपत्ति होती है। एक बालिका को एक साल की अतिरिक्त शिक्षा मिलने से भविष्य में उसकी कमाई की संभावना 10-20 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित में लिंग अंतराल को दूर करने के लिए सराहनीय कदम बढ़ाए हैं। शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, शिक्षा के लिए वह कौशल भी मायने रखता है जो छात्रों को रोजगार और उद्यमिता के लिए सक्षम बनाए। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, जब महिला कमाती है, तब वह अपनी आय का 90 प्रतिशत हिस्सा तक अपने परिवार के कल्याण में निवेश कर देती है, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा 30-40 प्रतिशत है। इन आंकड़ों को देखते हुए नीति निर्माताओं को महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों में अवश्य निवेश करना चाहिए।

कई ऐसे संगठन हैं, जिन्होंने देश में बड़ी संख्या में महिलाओं को सशक्त बनाया है, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिकी को गति प्रदान की है। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्ट-अप्स निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सही सहयोग मिलने पर महिलाएं न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, बल्कि इसका नेतृत्व भी करने लगती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रहे इस बदलाव को हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार देश में उद्यमिता में सक्रिय महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच अर्द्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या 60 प्रतिशत बढ़ गई है। ये आंकड़े देश में बढ़ते वित्तीय समावेशन और लघु उद्यमों के विकास की ओर इशारा करते हैं। वर्ष 2019 के बाद से बिजनेस लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी भी 14 प्रतिशत बढ़ गई है। दिसंबर 2024 तक बिजनेस के लिए लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या 35 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे स्पष्ट है कि भारत की उद्यमिता की कहानी में महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। ये आंकड़े महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और देश के आर्थिक विकास में उनके सक्रिय योगदान को दर्शाते हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाने से न केवल उनके जीवन में बदलाव आता है, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों भी बदल जाती हैं। अध्ययनों से यह भी साफ हो चुका है कि एक पढ़ी-लिखी महिला के द्वारा अपने बच्चे को स्कूल भेजने की संभावना दोगुना बढ़ जाती है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तब वे पूरे समाज के कल्याण को सुनिश्चित करती हैं। इस तरह बाल विवाह की दर में कमी आती है, बच्चों की शिक्षा में सुधार होता है और साथ ही गरीबी का चक्र भी टूटता है। भारत के गांवों में महिलाएं अपना भाग्य स्वयं लिख रही हैं, वे अपनी आजीविका चलाने के दायरे से बढ़कर सफलता की ओर अग्रसर हो रही हैं। महिलाओं के विकास में निवेश अर्थव्यवस्था को स्मार्ट बनाने का सही तरीका है। आर्थिक विकास सिर्फ बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों या विदेशी निवेश तक ही सीमित नहीं है। यह लोगों के साथ जुड़ा है। भारत का सबसे बड़ा संसाधन महिलाएं ही हैं, जिनका सदुपयोग अर्थव्यवस्था की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

खरी-खरी

## प्रेम, युद्ध और पालिटिक्स

विनोद कुमार विक्की

'प्रेम और युद्ध में सब जायज है।' एक दौर था जब यह कहावत प्रचलित थी। इन दिनों यह जुमला पालिटिक्स में भी घुसरैठ कर गया है। देश में बड़े बैनर की दो ऐसी पार्टियां है, जहां कभी भी, कुछ भी संभव है और जायज भी है। पहली वह पार्टी है, जहां कद्दावर नेता को भी कटू की तरह किनारे कर दिया जाता है और सामान्य कार्यकर्ता की प्रदेश का सिरमौर बना दिया जाता है। सत्ता की प्रधान कुर्सी तक पहुंचने के लिए आलाकमान द्वारा कब कौन सी रेखा खींच दी जाए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। अपनी जादूगरी से प्रदेश के प्रधान पद पर किसा साधु या महात्मा को पदासीन कर दें तथा बाजीगरी से अल्पमत में रहने के बावजूद कब कहां अपनी सरकार बना डालें, इसका पूर्वानुमान ज्योतिषी भी नहीं कर पाते हैं।

वहीं एक दूसरी पार्टी पुरानी है, लेकिन पारिवारिक है। एक समय था, जब संपूर्ण राष्ट्र के सिर पर इसी पार्टी का हाथ हुआ करता था, लेकिन इन दिनों अंतर्नी, चचेरी पार्टियों से भी हाथ मिला रही है। हालांकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इनके गठबंधन का रिमोट एक ही परिवार के हाथों से संचालित हो रहा है। इस पार्टी को यह खासियत है कि यदि चुनावों में इनकी जीत होती है या इनके गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, तो ईवीएम के सतीत्व को स्वीकार कर आनंदित हो स्वयं की पीठ थपथपाते हैं। यदि चुनाव में हार हो जाए तो ईवीएम को दोष देते हैं।

शेष अन्य पार्टियां चुनाव के दौरान इन्हीं दो राजनीतिक कंपनियों के ईर्द-गिर्द घूमती रहती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि इन पार्टियों के अपने-अपने धोंधू (चैनल) और दरबारी कवि (साहित्यकार) भी हैं, जो उनकी करतूतों का यशोगान और विरोधी पार्टी की भर्त्सना करते अघाते नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर, इंटरनेट मीडिया पर राजनीतिक बहस में ऐसे उपभोक्ता एक-दूसरे से असहमत होने पर गरियाते हुए भी देखे-सुने-पढ़े जाते हैं।

बहरहाल, इनमें से एक राजनीतिक दल का समर्थक अंधभक्त, तो दूसरे का समर्थक चमचा के उपनाम से लोक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है।

X पोस्ट

आक्रांताओं के नाम पर देश में जहां भी शहर, जिला, गांव, रेलवे स्टेशन, सड़कों और सार्वजनिक भवनों के नाम हैं, उन्हें एक केंद्रीय कानून बनाकर एक साथ एक झटके में बदल दिया जाना चाहिए। राष्ट्र के मन की टीस दूर होनी ही चाहिए।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक पी तो उनके खिलाफ फतवे जारी होने लगे। अरे जानते है फतवों की हकीकत। अगर नहीं तो गूगल कीजिए। आपको पता चलेगा कि 2006 में देश के बड़े-बड़े मुफ्तियों से दो दर्जन फतवे खरीदे गए थे। इसलिए लो ड मत लीजिए।

अनुरंजन झा@anuranjanj

पुलिसकर्मियों के कामकाज के घंटों का सीधा संबंध पुलिस बल की संख्यात्मक क्षमता से है। कभी-कभी सार्वजनिक अव्यवस्था की स्थिति बनने में देर नहीं लगती, तब उपलब्ध पुलिस बल से कहीं ज्यादा पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ती है। इसमें दो राय नहीं कि कार्य के घंटे निश्चित होने चाहिए, परंतु कठोर नियम बनाने में व्यावहारिक और सैद्धांतिक मुश्किलें हैं।

आर के विज@ipsvijrk

जागरण जनमत — कल का परिणाम

**क्या औरंगजेब का महिमामंडन करने वाले देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं?**

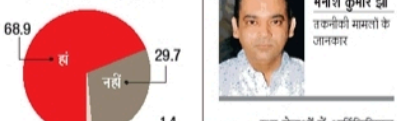


सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**

क्या आक्रांताओं के नामकरण वाले सभी स्थानों का नाम बदला जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मोदी जी की ढिबिया बता रहे थे प्रेमेंद्र,
मणिशंकरने खोल दी अब उनकी ही पोल।
अब उनकी ही पोल फेल थे उनके अब्बा,
इसीलिए तो युवही रहा सर्वाधिक डब्बा।
पीएम बनना चाह रहे थे दुःख की गोदी,
गड़ैउन्हीं की आख बने कांटा श्री मोदी।

- ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

# अकारण नहीं चुनावी जीत का आत्मविश्वास

पांच साल पहले विधानसभा चुनाव में हारी हुई बाजी जीतने के बाद एनडीए इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर अधिक आश्वस्त है। विपक्षी महागठबंधन की आश्वस्ति भी कम नहीं है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भविष्यवाणी की है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। उनके इस विश्वास का आधार 2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम है। 2020 के चुनाव में हुए वोटों के विभाजन को देखें तो पता चलेगा कि सामग्रता में केवल खड़े 11 हजार अधिक वोट लेकर एनडीए सत्ता में आ गया था। इतने ही वोटों की कमी के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद से वंचित रह गए थे। उस समय एनडीए के चार घटक दलों को एक करोड़, 57 लाख, दो हजार 650 वोट मिले थे। प्रतिशत में यह 37.26 था। दूसरी तरफ महागठबंधन (अब आइएनडीआइए) के पांच दलों को एक करोड़, 56 लाख, 91 हजार, पांच सौ (37.23 प्रतिशत) वोट मिला था। कोई सामान्य ढंग से सोच सकता है कि वोटों की इस कमी को राजद की अगुआई वाला आइएनडीआइए आसानी से पाट देगा। तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। मामूली वोटों की भरपाई की कामना सत्ता विरोधी रुझान के भरोसे की जा रही है।

राजद का आकलन है कि सुगठित चुनावी रणनीति से वोटों का अंतर बढ़ाया जा सकता है। आत्मबल इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि इन वर्षों में एनडीए ने वोटों का दायरा बढ़ाने का जितना प्रयास किया हो, उसने राजद के आधार वोट माय समीकरण के एक मजबूत हितधारक यादवों को अपने से दूर कर लिया। बल्कि कई अवसरों पर यादव को यह विश्वास दिलाया गया कि उन्हें एनडीए अपने खाते में नहीं रखता है। एनडीए की यह रणनीति यादव विरोधी वोटरों की गोलबंदी अपने पक्ष में करने के लक्ष्य के साथ निर्धारित की गई लगती है। यह उसके पक्ष में जाता भी है। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। वोट देने की प्रवृत्ति यही बताती है कि कोई भी जाति या समूह शत प्रतिशत किसी एक दल के पक्ष में मतदान नहीं करता है। स्थानीय कारणों से वोट करने की प्रवृत्ति में बदलाव होता है।

दो चुनावों के बीच राजनीतिक समीकरण में हुए बदलावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक बदलाव तो दो नैनों गठबंधन रणनीतिक स्तर पर कर सकते हैं। वह है कि पिछले चुनाव की गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। जदयू को पिछली परजय के आकलन के समय इस गलती का पता चला कि उससे उम्मीदवार चयन में बड़ी भूल हुई थी। जदयू की करीब दो दर्जन सीटों पर हार अलोकप्रिय या निष्क्रिय उम्मीदवारों के कारण हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के 16 में से 15 उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। जदयू को भ्रम हुआ कि विधानसभा चुनाव में कुछ इसी तरह का परिणाम आएगा। इस भ्रम के चलते उम्मीदवारों के पत्ता को जीत के प्रमाण-पत्र की तरह बांट दिय गया।

नीतीश कुमार। फाइल

तेजस्वी यादव। फाइल

दो चुनावों के बीच एक बड़ा बदलाव गठबंधन से दलों के जुड़ने-अलग होने के मोर्चे पर हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी ने राजद के साथ नया संश्रय बनाया है। पांच साल पहले वह एनडीए के साथ थी। उसे 0.89 प्रतिशत वोट आया था। यह वोट अगर पूरी तरह हस्तांतरित हो जाता है, तब भी राजद के वोट प्रतिशत में साधारण वृद्धि होगी। दूसरी तरफ लोजपा (रा) के शामिल होने से एनडीए के वोट में 5.66 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। पिछले चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तीसरे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। उसे 1.77 प्रतिशत वोट आया था। शालीसपा अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनकर एनडीए से जुड़ गया है।

अब अगर पांच साल के भीतर हुए इन बदलावों को देखें तो एनडीए के वोट बैंक में 7.43 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। एनडीए की आश्वस्ति इन्हीं आंकड़ों पर आश्रित है। यह आंकड़ा जदयू को भी उत्साहित कर रहा है। 115 सीटों पर लड़कर 43 सीट जीतने के दिन से ही जदयू का आत्मविश्वास डगमग चलने लगता था। उस समय की लोजपा 135 सीटों पर लड़ी। एक पर जीती। नौ सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन, उसने जदयू को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। बुरी हार के बावजूद चिराग पासवान इसे उपलब्धि से प्रसन्न थे। जदयू ने अपनी हार के लिए चिराग से अधिक भाजपा को उत्तरदायी ठहराया। क्योंकि लोजपा को अच्छे उम्मीदवारों की आपूर्ति भाजपा ने ही की थी। चुनाव हारने के बाद ये उम्मीदवार मामूली सजा झेलकर पुनः भाजपा में शामिल हो गए।

राजनीति से जुड़े किसी भी व्यक्ति के अगले कदम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी यह माना जा रहा है कि चिराग अभी जहां हैं, वहीं रहेंगे। यह स्थिति एनडीए के लिए बहुत अच्छी मानी जा सकती है। हां, जनसुराज वाले पीके यानी प्रशांत किशोर को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव का चिराग पासवान श्रेणित किया गया है। यह चुनाव परिणाम ही बताएगा कि वह किसके लिए चिराग प्रमाणित होते हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं

# एआइ के उपयोग में विसंगतियां

मनीश कुमार झा
तकनीकी मामलों के जानकार

**स्वास्थ्य सेवाओं में एआइ का उपयोग बढ़ रहा है, परंतु इसकी राह में विसंगतियां भी कम नहीं हैं। इस समस्या को समझते हुए अभी से ही इसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए**

स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की आजकल खूब चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि एआइ से स्वास्थ्य सेवा में खर्च कम होगा और कई सेवाएं बेहतर होंगी। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिन एआइ सिस्टम का उपयोग होता है, उन्हें चलाने और बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है, जिससे लागत बहुत बढ़ जाती है।

उदाहरण के तौर पर, कैंसर के मरीजों को उनके इलाज के बारे में कठिन निर्णय लेने में मदद करना ऑकोलाजिस्ट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अक्सर वे इसमें चूक जाते हैं। यूनिवर्सिटी आफ पेनसिल्वेनिया हेल्थ सिस्टम में एक एआइ एल्गोरिद्म डाक्टरों को मरीजों के इलाज के साथ-साथ उनके जीवन के अंतिम समय की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। यह एल्गोरिद्म मरीज की मृत्यु की आशंका का अनुमान लगाता है। लेकिन 2022 के एक अध्ययन ने इस एआइ तकनीक की एक बड़ी खामी उजागर कर दी, जब कोविड के दौरान इस एल्गोरिद्म की सटीकता सत प्रतिशत तक गिर गई। इस चूक के चलते यह उपकरण सैकड़ों बार डाक्टरों को मरीजों के साथ जरूरी बातचीत शुरू कराने में नाकाम रहा, जिससे संभवतः कई मरीजों को बेवजह कीमोथेरेपी (कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाली दवाओं का उपयोग) से गुजरना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि कई संस्थान अपने एआइ उपकरणों की नियमित जांच तक नहीं करते, जिससे मरीजों के लिए जोखिम और बढ़ जाता है।

**बढ़ता खर्च** : एल्गोरिद्म में कमियां एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कंप्यूटर विज्ञानी और डाक्टर बहुत समय से जानते हैं। एआइ पर बने सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए निरंतर निगरानी और प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि इन नए उपकरणों को बिना गलती के चलाने के लिए मनुष्य और मशीन दोनों पर बहुत रकम खर्च करना पड़ता है। जबकि सोचा यह गया था कि एआइ से स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कम होगा और लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा, परंतु असल में अभी इसके इस्तेमाल से इलाज का खर्च लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।

संबंधित विशेषज्ञों का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में एआइ का उपयोग बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। इस बात का सबूत यह है कि एक निवेश फर्म ने लगभग 20 ऐसे एआइ स्टार्टअप का अनुमान लगाया है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एक साल में लगभग 82 करोड़ रुपये प्रति स्टार्टअप कमाएंगे। ऐसे में यह जांच करना कि एआइ पर आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने वाले ये उत्पाद सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, स्वयं में एक बड़ी चुनौती है।

स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने एक बड़ी चुनौती है, अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा एआइ एल्गोरिद्म चुनना। न तो हर अस्पताल या डाक्टर के पास सुपरकंप्यूटर होता है, और न ही एआइ के लिए कोई कंप्यूमर रिपोर्ट जो अलग-अलग एआइ एल्गोरिद्म की तुलना करके बताए कि कौन सा बेहतर है। आज हमारे पास कोई ऐसा सुनिश्चित तरीका नहीं है जिससे यह पता चल सके कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले एआइ एल्गोरिद्म की जांच कैसे करें, उनकी देखभाल कैसे करें, और यह कैसे देखें कि वे सही काम कर रहे हैं या नहीं।

प्रतीकात्मक

आजकल कुछ डाक्टरों के कार्यालयों में एक नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है जिसे "एंबिएंट डाक्यूमेंटेशन" कहा जाता है। यह एआइ पर आधारित एक ऐसा सहायक है जो डाक्टर और मरीजों की मुलाकातों का एक संक्षिप्त विवरण तैयार करता है। यह तकनीक मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई है। इस तकनीक में काफी निवेश भी हो रहा है। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य में निवेश करने वाली प्रमुख फर्म "राक हेल्थ" के निवेशकों ने इन कंपनियों में लगभग 29 अरब रुपये लगाए थे। लेकिन एक बड़ी चुनौती यह है कि इन उपकरणों के आउटपुट की जांच के लिए कोई मानक नहीं है। जरा सोचिए, अगर ये उपकरण मरीज की जानकारी को गलत तरीके से रिकार्ड कर लें, तो इससे मरीज के इलाज पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह देखने के लिए कि क्या "चैटजीपीटी" और दूसरे "लार्ज लैंग्वेज माडल्स" मरीजों के मेडिकल इतिहास का सही संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं, एक अध्ययन किया। उन्होंने इन माडल्स द्वारा तैयार किए गए विवरणों की तुलना डाक्टरों द्वारा लिखे गए विवरणों से की। परिणाम यह निकला कि सबसे अच्छे नतीजों में भी माडल्स द्वारा दी गई जानकारी में 35 प्रतिशत तक गलतियां थीं, जो बहुत चिंताजनक बात है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में एआइ के उपयोग की दिशा में हमें बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा परिणाम घातक भी हो सकते हैं।

संवाद

# नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 8 मार्च 2025

## पंचपति का रोग

### निर्वाचित महिलाओं को कर दिया पीछे

**छत्तीसगढ़ के** कबीरधाम जिले से आई नवनिर्वाचित महिला पंचों की जगह उनके पतियों द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने की खबर चिंताजनक इस मायने में भी है कि यह किसी तरह का आश्चर्य या विस्मय नहीं पैदा करती। आम तौर पर इसे इस रूप में लिया जा रहा है कि यह तो होता ही है। मामला खास इसलिए बना क्योंकि इसका विडियो वायरल हो गया।

**धूमधाम से हुआ कार्यक्रम** | यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि 3 मार्च को कबीरधाम जिले के परसवारा गांव में हुए इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी संबंधित व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। किसी ने कुछ छुपाने की जरूरत नहीं महसूस की। धूमधाम से गुलाल लगाए माला पहने इन पंच पतियों को शपथ दिलाई गई। पूरे कार्यक्रम का न केवल विडियो बनाया गया बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया। यह तो जब विडियो वायरल हुआ और मीडिया की पूछताछ शुरू हो गई, तब स्पष्टीकरण लिए-दिए जाने लगे।

शपथ ग्रहण का विडियो वायरल

**सामाजिक पिछड़ापन** | अगर इस गांव की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति पर गौर करें तो यह सब अस्वाभाविक भी नहीं लगता। 2011 की जनगणना के मुताबिक 320 परिवारों और 1545 की जनसंख्या वाले इस गांव में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात प्रति हजार पर 936 है, जो राज्य के लिंगानुपात (969) के मुकाबले काफी कम है। साक्षरता दर जहां पुरुषों में 82.86% है वहीं महिलाओं में यह महज 51.19% है।

**जुर्माने की सिफारिश** | 50% आरक्षण के प्रावधान की बदौलत पंचायतों में महिलाओं को नुमाइंदगी तो मिल रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अभी पंचायत स्तर पर कुल 32.29 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें 15.03 लाख महिलाएं हैं। 46.6% के इस अनुपात को बुरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन व्यवहार में पितृसत्ता का साया इसे निरर्थक बना देता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंचायतों में महिलाओं की जगह उनके पति या अन्य रिश्तेदारों की भूमिका समाप्त करने के लिए समिति भी गठित की गई थी। इस समिति की पिछले महीने आई रिपोर्ट में ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई।

**जागरूकता की जरूरत** | लेकिन यह मामला जटिल और संवेदनशील है। कड़ी सजा पर जोर का उलटा असर हो सकता है। विडियो वायरल होने की वजह से परसवारा गांव की सुर्खियों में आ गया हो, यह ऐसा इकलौता गांव नहीं है। अन्य इलाकों से भी इस तरह की खबरें जब-तब सामने आती रहती हैं। ऐसे में कड़ी से कड़ी सजा के बजाय जागरूकता फैलाने पर जोर होना चाहिए। पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की भागीदारी और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में प्रशासन की रचनात्मक भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

## दो दूनी चार

### निवेश का छोटा पैक

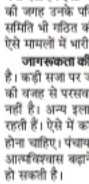

रमेश तिवारी

**जब देश** में म्युचुअल फंडों की शुरुआत हुई, तब कोशिश यह थी कि आम लोग इससे जुड़ें। फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रॉपर्टी, गोल्ड से आगे भी सोचें। लेकिन वर्ष 1995 से 2020 तक का इसका सफर बहुत कामयाब नहीं रहा। घरों की कुल जमा का बहुत कम हिस्सा ही फंडों के हाथ आया। लेकिन इसके बाद समय का चक्र तेजी से बदला। 2024 में ये चिंता जताई जाने लगी कि आम लोग घरों की बचत को शेयर बाजार में क्यों लगा रहे हैं? इससे बैंकों को पैसे की दिक्कत हो सकती है।

निश्चित रूप से शेयर बाजार में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन अब भी समाज का एक बड़ा तबका इससे दूर है। इसे घर-घर पहुंचाने के लिए मार्केटिंग की दुनिया का पुराना तरीका आजमाया जा रहा है। जब भी किसी प्रॉडक्ट को पुश करने की जरूरत होती है, तब उसके छोटे पैक का आइडिया पेश किया जाता है। इसी तरह से म्युचुअल फंडों में निवेश के लिए भी अब छोटे पैक की शुरुआत की गई है। हाल ही में जन निवेश SIP के नाम से ये पहल की गई। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो नियमित रूप से निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बड़ी राशि नहीं है। इसमें नए निवेशकों को 250 रुपये का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP का मौका मिलेगा। अभी यह योजना एक म्युचुअल फंड में शुरू हुई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और म्युचुअल फंड कंपनियां भी इस योजना को अपनाएंगी।

वैसे आज भी कुछ म्युचुअल फंड हैं, जिनकी मौजूदा SIP 100 रुपये से शुरू होती है। फंड चलाने वाली एक असेट मैनेजमेंट कंपनी तो 10 रुपये में भी ये सुविधा देती है। कम रकम की SIP की सुविधा देने में एक बड़ी बाधा इसका खर्च है। असेट मैनेजमेंट कंपनियों का कहना है कि उन्हें कई सेवाओं पर शुल्क देना पड़ता है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि जिस उद्योग का आकार लाखों करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, वह नए ग्राहक को जोड़ने का खर्च क्यों नहीं उठा सकता। सेबी ने लागत कम करने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। अकाउंट स्टेटमेंट और जानकारी केवल ईमेल या SMS के जरिए भेजी जाएगी। लेकिन बहुत से छोटे निवेशकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं होती। हर नए निवेशक के लिए SIP की संख्या तीन तक सीमित होगी। केवल चुनिंदा फंड कैटिगरी में ही निवेश की इजाजत होगी। ज्यादा जोखिम भरे फंडों को इस स्कीम से बाहर कर दिया गया है। लेकिन इससे निवेशक अपने निवेश में ज्यादा विविधता नहीं ला सकते। उनके पास निवेश के विकल्प सीमित रहते हैं।

बहुत से आम लोग, खासकर छोटे निवेशक, म्युचुअल फंड और SIP के बारे में ज्यादा नहीं जानते। उन्हें यह समझने में दिक्कत होती है कि यह कैसे काम करता है। बाजार में उतार-चढ़ाव का उनके निवेश पर क्या असर होगा। सही कदम के लिए वित्तीय सलाहकार से संपर्क करना भी जरूरी है। जब पिछले रिटर्न अच्छे दिख रहे हों, तो नए निवेशक जोड़ना आसान हो सकता है। असली चुनौती यह होगी कि बाजार गिरने के दौरान निवेशक को रोका जाए। बाजार में उतार-चढ़ाव के समय उन्हें हिम्मत देने की भी जरूरत होगी, ताकि वे SIP जारी रखें। मुख्यधारा के ज्यादातर SIP निवेशक भी पांच साल से कम ही निवेश रखते हैं। म्युचुअल फंड में छोटे निवेशकों को जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने के लिए भी लगातार मदद चाहिए।

## ऑफ़ दि ट्रैक

### AI की बढ़ती भूख

दिलीप लाल

**आर्टिफिशल इंटेलिजेंस** (AI) के बढ़ते उपयोग ने दुनिया में तकनीकी क्रांति ला दी है। चैटबॉट्स हों, इमेज जेनरेशन मॉडल या फिर डेटा विश्लेषण के लिए एडवांस्ड एल्गोरिदम - AI का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन, इसके साथ यह चिंता भी जुड़ी है कि AI को चलाने में इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी! Hugging Face नाम की संस्था ने इस बारे में एक स्टडी की है। रिपोर्ट बताती है कि अगर हम 1000 बार इमेज जेनरेशन पर काम करते हैं, तो 519wh (वाट-घंटा) एनर्जी चाहिए होगी। इसी तरह, टेक्स्ट जेनरेशन पर 288wh, चैटिंग करने पर 23wh और ऑडियो से टेक्स्ट कन्वर्जन पर 22wh बिजली खर्च होती है। इन आंकड़ों को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए लगभग 22wh बिजली चाहिए होती है। यहीं, 1000wh की एक बैटरी से लैपटॉप को 20 घंटे तक चलाया जा सकता है। इस समय पूरी दुनिया में ऊर्जा संरक्षण पर बात हो रही है, ऐसे में एआई ने नई टेंशन दे दी है। शायद यही वजह है कि टेक कंपनियां बिजली खपत से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं कराती। ऐसे में अभी हमारे पास कोई ग्लोबल डेटा भी नहीं है, जिससे पता चले कि कितनी बिजली AI को चलाने में लग रही। वैसे शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में पारदर्शिता बढ़ेगी और AI मॉडल्स की ऊर्जा खपत कम करने की नई राह मिलेगी।

जॉब इंटरव्यू में लड़कियों से शादी और बच्चे के बारे में पूछा जाता है

# बेटे कब बेटियों की तरह बड़े होंगे

प्रत्यक्षा

**यह बदलाव** का समय है। महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा। समझना होगा कि स्त्री और पुरुष का खांचा बाद में आता है और जिस तरह का हक एक पुरुष का है, वही हक एक स्त्री का भी होना चाहिए। वह एक पुरुष की तुलना में अधिक बुद्धिमान, अधिक रचनात्मक या अधिक जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह, वह कभी उनसे कम भी नहीं है। स्त्री और पुरुष, हो सकता है भिन्न स्किल सेट से लैस हों, लेकिन एक-दूसरे की तुलना में अपने-अपने मनोविज्ञान, शारीरिक क्षमताओं और संवेदनशीलता में पूरक हैं, कम या ज्यादा नहीं। यह बात पुरुष और स्त्री, दोनों को समझानी होगी। हमें स्त्रियों का सम्मान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे किसी की बेटी, बहन या मां हैं, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वे भी इंसान हैं।

**परवरिश और सुरक्षा** | यह सच है कि महिलाएं पहले से अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त हो रही हैं। टेक्नॉलजी, शिक्षा और करियर के क्षेत्र में नए अवसर उनके लिए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी असमानता और संघर्ष मौजूद है। सुरक्षा का मुद्दा आज भी महिलाओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। हम लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए उनके पहनावे या समय की पाबंदी की बात करने लगते हैं। जबकि जरूरी यह है कि समाज की पितृसत्तात्मक सोच बदली जाए। हम अपनी बेटियों की परवरिश तो बेटों की तरह करने लगे हैं, लेकिन अफसोस कि अब भी बेटों को बेटियों की तरह बड़ा नहीं करते।

**करियर में भेदभाव** | करियर में जेंडर बायस और भेदभाव का भी सामना महिलाओं को करना पड़ता है। हालांकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कई बार उन्हें पुरुषों की तुलना में कम अवसर और वेतन मिलता है। STEM (साइंस, टेक्नॉलजी, इंजिनियरिंग, मैथमेटिक्स) और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है। अब भी नौकरी के पहले उनसे इंटरव्यू में शादी और बच्चे के बारे में पूछा जाता है। आज भी कई जगहों पर लड़कियों की शिक्षा, करियर और जीवन से जुड़े फैसलों पर परिवार और समाज का नियंत्रण है।

**अवसरों की खिड़कियां** | बावजूद इसके उनके सामने नए अवसरों की खिड़कियां भी खुल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण, हमें लैंगिक रूढ़ियों के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव की जरूरत है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपने सुविधाजनक क्षेत्र से बाहर कदम रखने और विश्लेषण करने की जरूरत है कि कैसे ये गलत धारणाएं अवचेतन स्तर पर हमारे फैसले को प्रभावित कर रही हैं। आज की लड़कियां पहले से ज्यादा शिक्षित हो रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से ही वे समानता का अधिकार पा सकेंगी।

**तोड़ने होंगे गढ़-मठ सब**

- औरत को भी समझा जाए इंसान
- पहनाया नहीं, पितृसत्ता की सोच बदले
- तुरंत खत्म हो पुरानी कंडिशनिंग

**नई आवाज** | इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लड़कियों को एक नई आवाज दी है। वे अब ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर काम कर सकती हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं, और खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। कई महिलाएं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ब्लॉग्स के जरिए लाखों रुपये कमा रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और फ्रीलांसिंग उनके लिए नए करियर विकल्प बन रहे हैं। पहले की तुलना में अब महिलाएं, कॉरपोरेट दुनिया में, नौकरियों में, बिजनेस और नेतृत्व के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वे अपनी कंपनियां चला रही हैं और समाज में बदलाव ला रही हैं।

**जरूरत की बात** | हमें ऐसी बहुत सी पहल की जरूरत है, जहां महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थल बन सके, उनके लिए लचीली कार्य व्यवस्था की पेशकश, जेंडर न्यूट्रल जॉब उपलब्ध हो सकें। उत्पीड़न-विरोधी नीतियों को लागू करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को नेतृत्व की पोजिशन में बढ़ावा देना जरूरी है, जहां वे निर्णय लेने के अधिकारों को सही तरीके से समझ सकें, बिना पूर्वाग्रह के फैसले ले सकें।

**पिंजरा तोड़ो** | लड़कियों के लिए आज का समय अवसरों और चुनौतियों से भरा हुआ है। उनके लिए सबसे जरूरी है खुद के लिए स्पेस बनाना। अपनी पुरानी कंडीशनिंग से निकलना। समानता का अधिकार सुनिश्चित अधिकार है और इसे पहले उन्हें अपने लिए आत्मसात करना होगा, फिर परिवार में, और तब समाज में यह बात लानी होगी।

**संस्कृति निर्माण** | मशहूर लेखिका चिमामंदा अदीचे कहती हैं, 'संस्कृति लोगों को नहीं बनाती है। लोग संस्कृति बनाते हैं। अगर यह सच है कि महिलाओं की पूर्ण मानवता हमारी संस्कृति नहीं है, तो हमें इसे अपनी संस्कृति अवश्य बनानी चाहिए'। लड़कियां सीमाएं नहीं, ऊंचाइयां तय करने के लिए बनी हैं। यह बात सबसे पहले उन्हें खुद समझनी होगी, इसे अपने जीवन में लागू करना होगा फिर दूसरों को समझाना होगा। जैसा महात्मा गांधी ने कहा, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड।

*(लेखिका वरिष्ठ साहित्यकार हैं)*

## डरे हुए हैं दोस्त

**डॉनल्ड ट्रंप का अमेरिका अपने पुराने साथियों से दूर जाने और पुराने वादों को तोड़ने में बिजी है। यूक्रेन और यूरोप का हाल देख एशिया में भी चिंता है। अमेरिका के करीबी देशों के सामने सवाल है कि क्या ट्रंप उनके साथ भी वैसा ही सलूक कर सकते हैं?**

**ताइवान की चिंता**

ट्रंप ने ताइवान पर अमेरिकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हड़पने का आरोप लगाया है। उनका रुख इस पर भी साफ नहीं है कि क्या चीन के हमला करने की सूरत में वह ताइवान की रक्षा करेंगे। इस बीच, ताइवान पर चीन का रुख ज्यादा आक्रामक हो गया है।

**दक्षिण कोरिया को धमकी**

अमेरिका अपने दोस्तों को भी धमकाने से नहीं हिचक रहा। ट्रंप ने कहा है कि दक्षिण कोरिया से अमेरिकी फौजें हटाई जा सकती हैं। ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा।

**5 पॉइंट**

**चीन पर कन्फ्यूजन**

अमेरिका के एशियाई सहयोगी इसलिए भी चिंता में हैं, क्योंकि चीन को लेकर ट्रंप की नीति स्पष्ट नहीं है। वह टैरिफ वॉर चला रहे, पर सुलह की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने रूस और चीन के साथ वार्ता करने और परमाणु हथियारों व रक्षा बजट में कटौती की पेशकश की है। हालांकि उनकी टीम में चीन विरोधी माइक वॉल्ट्ज और माइक पॉम्पेओ जैसे चेहरे शामिल हैं।

**नया वर्ल्ड ऑर्डर**

कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप एक नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें रूस और चीन से टकराव नहीं चाहिए। तीनों महाशक्तियां अपने-अपने इलाकों में प्रभुत्व कायम करेंगी और एक-दूसरे के यहां कोई दखल नहीं देंगी। यानी, आखिरकार ट्रंप एशियाई सहयोगियों से दूरी बनाएंगे।

**मजबूरी की दोस्ती**

सब असमंजस में हैं और US के पुराने सहयोगी ट्रंप को अपने हिसाब से खुश करने में लगे हैं। जापान ने अमेरिका में निवेश बढ़ाकर एक ट्रिलियन डॉलर तक करने का वादा किया है। ताइवान की चिप कंपनी TSMC ने भी निवेश बढ़ाने की बात कही है।

*प्रस्तुति: शैलेंद्र पांडेय*

www.nbt.in

# काश, कैमरामैन भी लड़की होता

**सुबह से** ही घर में चहल-पहल थी। सभी या तो काम में व्यस्त थे, या एक-दूसरे से मिलने में। इस दिन का इंतजार मेरे साथ-साथ मेरे घर वालों को भी बहुत दिनों से था। मेरी शादी जो थी। सभी लोग आकर मुझे बधाई दे रहे थे। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही पीड़ा चल रही थी। शादी के दो दिन पहले से ही नमक खाना बंद करा दिया गया। फिर शादी से एक दिन पहले शाम को घर वालों ने मुझे पास के पोखर के ठंडे पानी से नहला दिया। शादी वाले दिन मांग में सिंदूर डलने के बाद ही मुझे खाना खाना था। मेरी शारीरिक हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत देर तक खड़ी भी नहीं होना चाहती थी। मेरे लिए मेरी शादी में बजने वाले बाजे, टेंट, सगाबट और स्वादिष्ट पकवान के कोई मायने नहीं थे।

जिस दिन मेरी शादी होनी थी, सुबह 11 बजे से ही मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैंने अपनी सहेली को अपनी पीड़ा बताई। उसने मुझे समझाते हुए कहा कि शादी के दिन पीरियड का आना शुभ होता है। मैं चुप हो गई। मैंने सोचा सभी लोग शुभ-अशुभ के चक्कर में पड़े हैं और यहां मेरी जान जा रही है। मैंने अपनी व्यथा अपनी बड़ी बहन को बताई और कहा कि रात में स्टेज पर जयमाल वाली रस्म रुकवा दे। उसने मुझे डांटते हुए कहा कि स्टेज सज चुका है। जयमाल के लिए लहंगा और बाकी सामानों में कितना खर्च हुआ है तुम्हें मालूम भी है? और ये सब ऐसी यादें होती हैं जो जिंदगी भर बनी रहती हैं। इस रस्म को किसी भी सूरत में नहीं रुकवाया जा सकता। उसकी बात सुनकर मैं चुप सी हो गई। मैं उससे यह भी नहीं बता पाई कि मेरा मन खड़ा होने का बिलकुल भी नहीं कर रहा है।

**खुद अपनी आंख से**

मोनी कुमारी

मैं अपने दर्द को अपने अंदर छुपाए घर के एक कोने में बैठी थी। शादी में शामिल होने वाले रिश्तेदार मेरा चेहरा देखकर पूछ रहे थे कि इसका चेहरा इतना उतरा हुआ और उदास क्यों है? मैं कुछ बोलती, इससे पहले ही बगल में खड़ा कोई ना कोई बोल देता कि मां-बाप से बिछड़ने का गम है। मेरे मन में बस यही सवाल चल रहा था कि जयमाल के वक्त मैं स्टेज पर खड़ी कैसे रह पाऊंगी? कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए! मुझे सभी लोगों की खुशियों की खातिर दर्द सहते हुए अपनी हिम्मत को बनाए रखना था। मुझे खूबसूरत कपड़ों और गहनों से सजाया जा रहा था। जिन कपड़ों और गहनों को मैंने ही बड़े शौक से खरीदा था, अब उन्हीं को मैं उतारकर फेंक देना चाहती थी। दर्द के साथ साथ मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि इन कपड़ों को उतारकर फेंक दूं और जोर से चिल्लाकर बोलूं कि आज मेरे पीरियड का पहला दिन है, मुझसे इन कपड़ों और गहनों का भार नहीं झेला जा रहा।

बारात के आने की खबर सुनकर मेरे मन में खुशी की जगह घबराहट भर गई। मैं इस चिंता में थी कि खुद को संभालूंगी कैसे! धीमे-धीमे चलते हुए मैं जयमाल के लिए स्टेज पर गई। कैमरामैन फोटो खींचता हुआ बार-बार स्माइल प्लीज बोल रहा था। लहंगे और खूबसूरत गहनों से लदी मैं अपने ही मन सोच रही थी कि काश कैमरामैन लड़की होता, और आज उसके पीरियड का पहला दिन होता।

### चलते-चलते...

**डायबिटीज और** मोटापे से पीड़ित लोग अगर खाने में अधिक वसा लेते हैं, तो उनकी याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। हाल ही में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह दावा किया गया है। रिसर्च में युवा और वृद्धों पर प्रयोग किया गया, जिसमें चौंकाने वाले परिणाम आए। उनके मुताबिक, बुजुर्ग अगर लगातार तीन दिनों तक इस तरह का भोजन करते हैं, तो उनकी मेमोरी पर असर पड़ने की आशंका है।

# लेखक हैं तो ज़िंदगी के दायरे से बाहर निकलिए

*मीरा जौहरी प्रकाशन संस्थान Rajpal & Sons की मुखिया हैं। 113 साल पुराने इस संस्थान में और इससे बाहर भी उन्होंने एक युग को बदलते और बनते देखा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उनसे बात की शोभा अक्षर ने। पेश हैं बातचीत के अहम अंश :*

मीरा जौहरी

**■ प्रकाशन उद्योग की दुनिया में आप स्त्री प्रकाशकों की भूमिका को कैसे देखती हैं?**

मेरे दादाजी के समय तो संभव ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसी भूमिका निभा सकूं। असंभव था क्योंकि वह जमाना ही और था। तब 99% महिलाएं घर में ही रहती थीं और बहुत कम महिलाओं को शिक्षा का अवसर मिलता था। स्वतंत्रता के बाद जबसे संविधान आया और बराबरी के अधिकार मिले, तो बहुत फर्क पड़ा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं और आप भी हैं कि हम इस युग में पैदा हुए और हमको शिक्षा मिली, जिसका हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो हर क्षेत्र में महिला दिखती है। अगर हम अपना भी पार्लियामेंट देखें तो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है। अगर हम देखें कि कहां से शुरुआत की थी, जैसे मेरी दादी-नानी ने, तब समझ आता है कि हमने बहुत तरक्की की है। लेकिन यह भी लगता है कि बहुत आगे जाने की जरूरत है और हमारे आसपास जो महिलाएं हैं उनको भी हाथ देने की जरूरत है कि वह आगे बढ़ें, सशक्त हों।

**■ भारतीय बाजार में हमेशा से पुरुष आधिपत्य रहा है। आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा?**

चूंकि यह हमारा पारिवारिक बिजनेस है, तो मुझे उस तरीके की चुनौतियां का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन एक चीज है कि अपनी संस्था में आपको स्वीकार यूं ही नहीं किया जाता कि आपके पिताजी चलाते थे, अब आप चला रहे हैं। आपको अपने आप को रोज प्रूव करना पड़ता है, रोज कठिन निर्णय लेने होते हैं, कठिन चुनौतियां होती हैं। एक उदाहरण है कि 25-30 साल पहले महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर केवल साड़ी ही एक पोशाक थी, जो स्वीकार्य थी। शुरुआती दौर में मैं भी केवल साड़ी ही पहनती थी क्योंकि और कुछ आप सोच नहीं सकते थे। वहां से लेकर आज जींस-पैंट, स्कर्ट या जो मन में आए पहन सकते हैं। प्रकाशन जगत में कोई इस पर सवाल नहीं उठाता कि अरे ये क्या पहन लिया? तो बहुत बदलाव आया है। मुझे लगता है प्रकाशन की दुनिया में जेंडर का इतना डिसएडवांटिज नहीं है, क्योंकि शायद जो फ्रिंट्रिंग पीरुड है, उसमें हो सकता है महिलाएं ज्यादा सेंसिटिव हैं इसलिए उनको एक एडवांटिज है। अगर हम गौर करें, जैसे अपने देश में उर्वशी बुटालिया जिन्होंने 'जुबान बुक्स' की स्थापना की, उन्होंने बिल्कुल नई जमीन तैयार की। देखिए, एक लेवल पर सोसाइटी में सब जगह चुनौतियां हैं। चाहे आप सड़क पर ही जा रही हों तो वहां भी ईव टीजिंग से लेकर बहुत तरह के खतरे होते हैं।

**■ आपके अनुभव से महिला साहित्यकारों की किताबों को लेकर पाठकों का रुझान कैसा रहता है?**

पाठक लेखक के जेंडर से नहीं, लेखन से प्रभावित होता है। बौद्धिकता किसी-किसी फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे रोमिला थापर। उनसे बड़ी आज कोई इतिहासकार नहीं है। या जैसे जे.के. राउलिंग को देखें तो शुरू में उनको इतना रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। वह शायद उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने एक रिस्क लिया था। और जो रिस्क लेते हैं, वही उसका फायदा भी उठाते हैं।

**■ साहित्य का एक मूल काम समानता और विविधता को लेकर काम करना भी है। समानता और विविधता को लेकर प्रकाशन उद्योग में वर्तमान स्थिति क्या है और इसका भविष्य आप कैसे देखती हैं?**

मैं दो चीजें कहूंगी। एक, प्रकाशन जगत को हम अपने समाज के दायरे में ही देखें, क्योंकि हम उसी का हिस्सा हैं। बाकी जगह महिलाओं की प्रगति कम है या ज्यादा है तो वह भी एक संकेत है कि यहां पर स्थिति कोई उससे बहुत विपरीत नहीं होने वाली। दूसरे, यहां भी

> 25-30 साल पहले महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर केवल साड़ी ही एक पोशाक थी, जो स्वीकार्य थी। उस स्थिति के मुकाबले देखें तो आज जींस-पैंट, स्कर्ट या जो मन में आए पहन सकते हैं। प्रकाशन जगत में कोई इस पर सवाल नहीं उठाता कि अरे ये क्या पहन लिया? तो बहुत बदलाव आया है

सेम काम पर सेम मजदूरी है। अगर इसके विपरीत हम देखें फिजिकल लेबर, जहां पर महिला मजदूर को कम पैसे मिलते हैं और पुरुष को ज्यादा। जबकि दोनों काम उतना ही करते हैं। दूसरी बात है विविधता, जो नए लेखकों को जोड़कर आती है। आपको किसी की कोई चीज पसंद आई। आप सोचते हो कि चलो इसको मौका देते हैं। ऐसे नए लेखक सामने आते हैं और विविधता होती है। कई प्रकाशन हैं जो केवल एक ही विधा की किताबें करते हैं, विज्ञान, चिकित्सा या टेक्नॉलजी। जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स करते हैं वह एक अलग क्षेत्र है। मगर हमारा एक जनरल प्रकाशन संस्थान है तो विविधता तो होगी। उसमें पुरुष लेखक भी हैं, स्त्री लेखक भी हैं। हां, यह जरूर है कि जो भी चीज आप सामने प्रस्तुत करें, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए।

**■ प्रकाशन जगत में काम करने या लेखक बनने की आकांक्षा रखने वाली लड़कियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगी?**

मेरा तो यही सुझाव है कि आपकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बिना भाषा के आप लेखक नहीं बन सकते। इसलिए अभ्यास कीजिए। जितना लिखोगे उतना भाषा में निखार आएगा। दूसरे, पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा में पढ़िए क्योंकि विषय तो हर भाषा में होते हैं। पढ़ने से आपके अंदर जो रिचनेस आएगी, कल आप उसी को यूज करके लिखेंगे। तीसरे, आपके अपने ओरिजिनल आइडियाज जब तक नहीं होंगे, भाषा कितनी भी अच्छी हो, बेहतर लेखन नहीं होगा। आप किसी और की कहानी को दोबारा मत लिखिए। नए-नए अनुभव कीजिए। जिंदगी में अपने दायरे से थोड़ा निकलिए। कभी दूसरे रास्ते पर चल पड़िए। शायद उसी में कोई आपकी कहानी या प्लॉट मिल जाए। हर एक का अपना स्टाइल होता है। जो आपके लेखन का स्टाइल है वह आप ही का है। आप अपनी स्टाइल को पहचानें, किसी और की तरह लिखने की कोशिश करना ठीक नहीं है।

## रीडर्स मेल

### ▸ उद्योगों को मजबूत बनाना होगा

**7 मार्च** का संपादकीय 'भारत करे रीसैंबाजी' पढ़ा। हमारे देश के साथ दोस्ती की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत ने हमसे टैरिफ ज्यादा वसूला है। इसी को आधार बनाते हुए अमेरिका 2 अप्रैल से टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका अन्य देशों के साथ भी यही नीति अपना रहा है। चीन और अन्य कुछ देशों ने अमेरिका पर भी ऐसा ही टैरिफ लगाने की बात कही है। भारत को इन हालात में कैसा रुख अपनाना चाहिए, इस पर लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आज की दुनिया में सबसे कट कर नहीं रहा जा सकता। घरेलू मार्केट और अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा जरूर दिया जाना चाहिए लेकिन ग्लोबल मार्केट से मुंह मोड़ना ठीक नहीं होगा। अगर कुछ समय के लिए अमेरिका से ट्रेड प्रभावित भी हो, तो अन्य देशों में नई संभावनाएं तलाश कर उसकी भरपाई के प्रयास किए जाने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, ईमेल से

### ▸ महिलाओं की चुनौतियां समझें

**यह पत्र** 6 मार्च को 'आधी दुनिया' कॉलम में प्रकाशित लेख 'ऐसे दिखता है जादू' से संबंधित है। लेख में सिंधु गंगाधरन की कहानी के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव को दर्शाया गया है। पहले इस क्षेत्र में महिलाएं कम होती थीं। लेकिन समय के साथ चीजें बदलीं। अब कंपनियां महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं और उन्हें नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने के अधिक अवसर मिल रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई महिलाओं की मेहनत, काबिलियत और संकल्प की अहम भूमिका है। लेख पढ़कर यही लगा कि महिलाओं के हित में सिस्टम डिवेलप किया जाए और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दी जाए तो निश्चित ही लीडरशिप के क्षेत्र में महिलाएं भी आगे आएंगी। इसके लिए महिलाओं की परेशानियों को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने होंगे। अगर उन्हें थोड़ा समर्थन और फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए तो उसका लाभ कंपनियों को भी होगा।

गुरिंदर पाल सिंह, ईमेल से

नवभारत टाइम्स : 4, 11,12,13 राजेंद्रमल्लिक एस्टेट। रिंग रोड़ अशोक विहार के बिच रोड़ के अतिरिक्त पुलकेशन पूर्व। प्रोप्रीटर: नवभारत टाइम्स लिमिटेड, प्रोप्रीटर तथा प्रकाशक विनोद के लिए राजेंद्र माथुर द्वारा। 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से मुद्रित तथा **राइट्स एंड पब्लिशिंग हाउस**, बहादुर ग्रुप, **औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद**, जी मार्ग नंबर 2-4, सेक्टर 24-25, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल क्षेत्र फरीदाबाद, हरियाणा से मुद्रित। फोन: 2102222222 चेयरमैन: रमेश चंद्र तिवारी। एडिटर: राजेश चंद्र मिश्र, एडिटोरियल ऑफिस: नवभारत टाइम्स, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002। ईमेल: ई-मेल एडिटर: नवभारत टाइम्स। एडिटर: रमेश चंद्र। ब्यूरो प्रमुख: नवभारत टाइम्स। ब्यूरो प्रमुख: नवभारत टाइम्स। ब्यूरो प्रमुख: नवभारत टाइम्स। (रिजर्वी नवंबर): अंग्रेजी पोर्ट (इस अंक में समाचार जनता कलकत्ता के साथ पूर्व संस्करण हेतु पी.आर. बी. एक्ट के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ।

कल्पमेधा

*जो लोग आजादी भोग रहे हैं, वे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो लोग स्वतंत्र नहीं हैं, उनके लिए स्वतंत्रता की आशा करना कितना सुखदायी है।*

*- पर्ल एस बक*

# आशंकाओं के बरक्स

जब से अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है, तबसे दुनिया भर में आशंकाओं के बादल गहराने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो देश जितना शुल्क हमसे वसूलता है, उतना ही शुल्क हम भी उससे वसूल करेंगे। माना जा रहा है कि इससे व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा। चीन ने तो इसे विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के खिलाफ बताया। फिर उसने यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, तो वह इसके लिए तैयार है। अमेरिकी संसद में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन देशों का नाम लिया, उनमें भारत का भी विशेष रूप से उल्लेख किया कि वह कुछ मामलों में सौ फीसद से भी अधिक शुल्क वसूलता है। मगर भारत की तरफ से तुरंत इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। स्वाभाविक ही सबकी नजरें भारत की तरफ लगी हुई थीं। अब विदेशमंत्री ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की शुल्क संबंधी नीतियों का भारत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में कोई बाधा आएगी। विदेशमंत्री ने ट्रंप के कदम को बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ने वाला बताया।

अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं और माना जा रहा है कि वे द्विपक्षीय व्यापार के मसले पर कुछ सकारात्मक समझौते कर पाएंगे। पिछले महीने प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। जिन वस्तुओं पर अमेरिका को लगता है कि भारत अधिक शुल्क वसूलता है, उन पर धीरे-धीरे शुल्क कम भी किया जा रहा है। इससे जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार गतिविधियों में वैसी बाधा शायद न आए, जैसी चीन आदि देशों के साथ आने की आशंका जताई जा रही है। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे भारत के कई क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ सकता है। पहले ही भारत आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर चिंताजनक दौर से गुजर रही है। ऐसे में जिन वस्तुओं के लिए अमेरिका में बड़ा बाजार था और उन पर भारत को न्यूनतम शुल्क देना पड़ता था, उन क्षेत्रों की रफ्तार कैसी रह पाएगी, दावा करना मुश्किल है।

वस्तुओं पर शुल्क निर्धारण के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियम तय हैं। गरीब देश अमीर देशों पर इसलिए ऊंचा शुल्क लगा सकते हैं कि उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अमीर देशों से इसीलिए ऊंचा शुल्क देने की अपेक्षा की गई कि वे गरीब मुल्कों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में मददगार होंगे। माना गया था कि इस तरह दुनिया में तेजी से आर्थिक विकास हो सकेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उस नियम को नजरअंदाज कर दिया। इससे विश्व व्यापार संगठन की स्थिति भी अजीब हो गई है। मगर ऐसा नहीं कि पारस्परिक शुल्क नीति से अमेरिका को कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। अमेरिका खुद महंगाई से पार पाने की चुनौती से जूझ रहा है। उसमें अगले महीने से पारस्परिक शुल्क लगने से जब दूसरे देशों से वस्तुएं महंगी दरों पर वहां पहुंचेंगी, तो महंगाई और बढ़ेगी ही। अमेरिका दवा और बहुत सारी चीजों के कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इसलिए माना जा रहा है कि वह अपने इस फैसले पर ज्यादा समय तक टिका नहीं रह पाएगा। भारत भी इसीलिए फूंक-फूंक कर कदम उठा रहा है।

# भाषा पर राजनीति

भाषा पर राजनीति इन दिनों बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य में हिंदी थोपने और प्रादेशिक भाषा को नष्ट करने का आरोप केंद्र पर लगाया था। यह विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब मराठी को लेकर सियासत गरमा गई है। संघ के नेता सुरेश भैया जी जोशी का यह बयान सुर्खियों में है कि मराठी मुंबई की भाषा है और बाहरी लोगों और अन्य भाषाएं बोलने वालों को भी इसे समझना और सीखना चाहिए। जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं। कोई दो मत नहीं कि महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी को राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। यहां की राजनीतिक अस्मिता इसी से तय होती है। मगर यह किसी को नहीं भूलना चाहिए कि भारत विविध संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है। लोग एक से दूसरे राज्य में रोजी-रोटी के लिए जाते हैं, तो अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा-बोली भी साथ लेकर जाते हैं। हर राज्य में भाषा का सौंदर्य इसी से समृद्ध होता है। इसका उदाहरण हम मुंबई में देख सकते हैं।

सवाल है कि संघीय ढांचे में रहते हुए हम यह कैसे कह सकते हैं कि दूसरे राज्य से आया व्यक्ति अनिवार्य रूप से संबंधित प्रदेश की भाषा बोले और सीखे? निस्संदेह मराठी महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। वहीं मुंबई कई संस्कृतियों और विविध पहचान वाला शहर है। यहां प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है। क्या यह राजनीति इसी वजह से है? भैया जी जोशी ने बेशक सफाई दे दी हो, लेकिन उनके बयान पर विवाद थमा नहीं। वे अपने ही बयान को लेकर जिस तरह दोहरी स्थिति में हैं, उससे लगता है कि मराठी बनाम गैर-मराठी की राजनीति को हवा दी जा रही है। स्वाभाविक रूप से विपक्ष ने बांटने की राजनीति करने का आरोप लगा कर उन्हें घेरा है। महाविकास अघाड़ी के सभी दल एकजुट हो गए हैं। एक भाषा को संरक्षण तभी मिलता है, जब हम दूसरे लोगों की भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। भाषा की जड़ें सामाजिक व्यवहार और सद्भाव से ही निर्धारित होती है, विवाद से नहीं।

# सशक्त महिलाएं, प्रगतिशील कदम

**आज जब पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, राजस्थान महिला समानता और सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, राजस्थान सरकार ने राज्य में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।**

**भजनलाल शर्मा**

हमारी सनातन संस्कृति में नारी शक्ति को सर्वोच्च माना गया है और वे समाज को प्रगतिशील बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय परंपरा में स्त्री सदैव प्रथम और पूजनीय रही है। नारी को शक्ति, ममता, और त्याग का प्रतीक माना गया है। सभी के लिए दृष्टिकोण, उनका ममता और सेवा का भाव, उनकी सहनशक्ति और हर स्थिति के प्रति उनका दृष्टिकोण, इस सबसे महिलाओं को केवल एक दिन नहीं, हर दिन सम्मान मिलना चाहिए।

आज जब पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, राजस्थान महिला समानता और सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, राजस्थान सरकार ने राज्य में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई 'लाडो प्रोत्साहन योजना' के तहत गरीब परिवारों में लड़कियों के जन्म पर एक लाख रुपए के बांड दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में दस फीसद की वृद्धि की गई है, जबकि 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के तहत दी जाने वाली सहायता को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े छह रुपए कर दिया गया है। राजस्थान के पांच लाख स्वयं सहायता समूहों को 'राज सखी' पोर्टल के जरिए जोड़ा जा रहा है।

महिला सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख पहलू इसका वित्तीय प्रावधान है। 2025-26 के बजट में महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। 2025-26 के बजट में प्रदेश में चार नए देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, सोलह नए सावित्री बाई फुले छात्रावास, सत्रह नए महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, वंचित वर्गों, महिलाओं, चुनुर्गों और दिव्यांगों के लिए संचालित समस्त राजकीय, अनुदानित और निजी आवासीय संस्थानों में मेस के भत्ते को बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रति माह किया गया है। इसके साथ ही सभी संभागीय मुख्यालयों पर पचास बेड के 'सरस्वती हाफ्ते होम्स' की स्थापना, दस जिला मुख्यालयों पर 'गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स' की स्थापना, प्रत्येक ब्लाक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केंद्र की स्थापना, बालिकाओं को 35,000 स्कूटी वितरण योजना की घोषणा की गई है।

इसके साथ ही प्रदेश में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर बीस लाख महिलाओं तक किया जा रहा है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को नान-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में उन्नत किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के लिए एक लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज दर, 2.5 फीसद से घटाकर 1.5 फीसद कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान में तीन लाख लखपति दीदियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रि-

किट योजना लागू की है जिससे प्रदेश की लगभग 2.35 लाख महिलाओं को लाभ होगा। छोटे बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में पांच दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर अलग से लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए नई छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवा महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने और पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से की गई हैं।

> **राज्य सरकार की महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता इसकी नीतियों, बजटीय आवंटनों और जमीनी स्तर की पहलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और शासन में विशेष करके, राजस्थान एक मजबूत और सामाजिक समता की दिशा में प्रगति कर रहा है। वास्तविक सशक्तीकरण केवल नीतियों से नहीं होता, यह समाज, सरकार और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से संभव होता है, जो महिलाओं और लड़कियों को बिना किसी बंधन के फलने-फूलने का अवसर प्रदान करता है। इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, राजस्थान सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराती है कि महिलाएं केवल सपने न देखें, बल्कि उन्हें पूरा भी करें और नेतृत्व करें।**

राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिला थाना विस्तार, महिला पुलिसकर्मियों की बढ़ती तैनाती और महिलाओं को अपराधों की रपट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम, बच्चियों और महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन के लिए एक हजार कांस्टेबल के पद स्वीकृत किए गए हैं। महिलाओं को आपात स्थिति में चौबीस घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एक एप तथा आरएसआरटीसी के सुरक्षा कमांड सेंटर तथा पैनिक बटन परियोजना शुरू की गई है।

राज्य सरकार ने निर्भया फंड के तहत स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी निगरानी और शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दलों में निवेश किया है। 'शक्ति रक्षक' कार्यक्रम को भी मजबूत किया गया है, जिसमें युवा लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं की रक्षा कर सकें। नीतियों में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। नए बजट में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिल सके। 'राजश्री योजना' का विस्तार किया गया है, जिसके तहत बालिकाओं को विभिन्न शैक्षिक चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता और स्वस्थ परवरिश सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त सेनेटरी पैनिकन वितरण कार्यक्रम के लिए धनराशि बढ़ाई गई है, जिससे किशोरियों में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि वे राजनीति एवं शासन में नए लोगों को लाना चाहते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार जमीनी स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पंचायती राज संस्थानों में पचास फीसद आरक्षण बनाए रखते हुए सरकार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा, राज्य प्रशासन महिलाओं की सरकारी नौकरियों और राजनीतिक पदों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और नेतृत्व पहल लागू कर रहा है। सरकार ने प्रदेश में महिला आरक्षण को लेकर संशोधन करते हुए पुलिस विभाग में भी सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान किया है। महिला सशक्तीकरण की एक महत्त्वपूर्ण पहचान उनकी निर्णय-निर्माण भूमिकाओं में बढ़ती भागीदारी है।

राज्य सरकार की महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता इसकी नीतियों, बजटीय आवंटनों और जमीनी स्तर की पहलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और शासन में निवेश करके, राजस्थान एक मजबूत और सामाजिक समता की दिशा में प्रगति कर रहा है। वास्तविक सशक्तीकरण केवल नीतियों से नहीं होता, यह समाज, सरकार और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से संभव होता है, जो महिलाओं और लड़कियों को बिना किसी बंधन के फलने-फूलने का अवसर प्रदान करता है। इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, राजस्थान सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के संकल्प को दोहराती है कि महिलाएं केवल सपने न देखें, बल्कि उन्हें पूरा भी करें और नेतृत्व करें।

*(लेखक राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं।)*

# शिक्षा खड़ी बाजार में

**रितुप्रिया शर्मा**

शिक्षा अपने आप में एक अत्यंत पवित्र शब्द है, जिसके आगे सारी विशेषताएं और दावे अधूरे नजर आते हैं। शिक्षा का प्रभाव हमारे वर्तमान ही नहीं, अतीत पर भी पूरी तरह छाया हुआ था। सच यह है कि शिक्षा को अगर हम किताबी ज्ञान तक सीमित करें, तो यह ठीक नहीं है। इसका स्वरूप किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा है। वर्तमान में शिक्षा बाजार उन्मुख हो गई है। चाहे शिक्षा देने वाले हों या शिक्षा लेने वाले, सभी शिक्षा को धन अर्जित करने का साधन मानकर चलते हैं। आज के दौर में शिक्षा अर्जन का उद्देश्य धनार्जन है। दसवीं, बारहवीं जैसी कक्षाओं के परिणाम तय करते हैं कि बच्चा किस जगह जाना चाहता है। मगर उसकी आंतरिक इच्छा भले ही कुछ और करने की हो, फिर भी उसको जबरदस्ती भेड़चाल में धकेलने की पूरी व्यवस्था समाज में मौजूद है।

ऐसी स्थिति के लिए स्कूल-कालेज के साथ-साथ बच्चों के माता-पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बड़े-बड़े कोचिंग केंद्र लोगों को डाक्टर, इंजीनियर, आएएएस आदि बनाने में जुटे हैं, जबकि बच्चे की मर्जी जाने या उसके मन को टटोले बिना कोचिंग केंद्रों में उनके दाखिले करा दिए जाते हैं, भले ही बच्चा दबाव झेलने में सक्षम हो या न हो। समझने की बात यह है कि क्या पढ़-लिखकर केवल अपने उत्थान के लिए कुछ करना हमारे देश के लिए काफी होगा। मूलतः यह सोच ही बाजारीकरण की द्योतक है। पढ़ाई के नाम पर जिस तरह से फीस वसूली जाती है, उससे निर्धन बच्चों का भविष्य आमतौर पर अधर में रह जाता है। हालांकि ऋण सुविधाओं और सरकारी योजनाएं कुछ हद तक इसमें राहत पहुंचाती हैं, लेकिन कुछ लोगों तक ही इनकी पहुंच होती है, बाकी के सभी इस तंत्र का शिकार बनते हैं। उन्हें छोटी-छोटी नौकरियों के लिए भी काबिल नहीं समझा जाता। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के मुकाबले अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी इसलिए योग्य समझा जाता है, क्योंकि उसका अंग्रेजी का ज्ञान कहीं ज्यादा है।

प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को पता है कि कहां कैसा माहौल है। मगर सब और यही स्थिति है कि जहां जैसा चल रहा है, वैसा चलने दो। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी समस्याएं हैं, किस-किस पर ध्यान दिया जाए? ऐसी सोच लेकर सभी लोग अपने जीवन को चलाने में विश्वास रख रहे हैं और फिर आज के इस युग में 'मैं क्यों बोलूं' वाली धारणा का प्रचार अधिक ही असर दिखा रहा है। सड़क पर चलते हुए हम बहुत से गरीब बच्चों को देखते हैं। न जाने किसके अंदर कैसी प्रतिभा छिपी है। हमने शिक्षा कि सारी बुनियादी बातों को दरकिनार कर दिया है। सरकारी व्यवस्था सबके लिए समान शिक्षा, अनिवार्य, निशुल्क और शिक्षा की व्यवस्था करती है, लेकिन क्या इन स्कूलों से पढ़े बच्चे उन बच्चों के साथ प्रतियोगिता में खरे उतर सकते हैं जो महंगे स्कूल में पढ़ते हैं? इस व्यवस्था को बदलना आसान काम नहीं है।

शिक्षा श्रेष्ठि वर्ग के लिए प्रतिष्ठा और मान-सम्मान का विषय हो गई है। ऐसे संस्थानों में गरीब प्रवेश ही नहीं कर सकता, जहां कुलीनता ही पहचान है। शिक्षा और आर्थिक जीवन के बीच यह टकराव खतरनाक है। आज नहीं तो कल, कोई ऐसा वक्त भी आ सकता है जब यह बाजारीकृत व्यवस्था अपना एक वर्ग खड़ा कर ले, या फिर ऐसा हो कि उपेक्षित वर्ग इसके खिलाफ खड़ा हो जाए। दोनों ही स्वरूप उचित नहीं है। समाज में संतुलन समाज की आधारभूत आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी परिवर्तन को शामिल किया गया है। जब-जब शिक्षा की नीति में परिवर्तन हुआ है, तब-तब रोजगार का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। 1986 की शिक्षा नीति में तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। इससे कई रोजगार क्षेत्रों में तेजी दर्ज की गई, तो कहीं भारी गिरावट भी आई। अब एक बार फिर नई शिक्षा नीति प्रस्तावों के मुताबिक कला, विज्ञान, व्यावसायिक विषयों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होने और इसे बच्चों के लिए शिक्षा को सहज बनाने में सक्षम होने की संभावना जताई जा रही है। इसके तहत, राष्ट्रीय नवाचार अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इससे हमारी व्यवस्था में सकारात्मक सुधार की अपेक्षा है।

## दुनिया मेरे आगे

> **शिक्षा एक मानवाधिकार है। इस अधिकार की पूर्णता तभी हो सकती है, जब इसे सभी तक बराबर के साथ पहुंचाया जाए। शिक्षा को सरकारों के आने-जाने के क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह आर्थिक मुद्दों से प्रभावित न हो और न ही किसी अन्य भावना से प्रभावित हो, बल्कि यह उन्मुक्त और सर्वसुलभ और सस्ती होनी चाहिए।**

उच्च शिक्षा की तरफ देखा जाए तो पता चलता है कि उच्च शिक्षा के लिए जो व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य है, उसमें एक विषय भारत में विदेशी विश्वविद्यालय का भारत में प्रवेश करने का है। सवाल है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा को बेहतर करेंगे या महंगी व्यवस्था को स्थापित करेंगे। यह भविष्य ही बताएगा कि वर्तमान शिक्षा नीति पिछली अव्यवस्थाओं को दूर करने में सक्षम होती है या नहीं। फिर भी इसमें मातृभाषा में शिक्षा को अच्छी पहल कहा जा सकता है। हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा सर्व समाज के लिए उपलब्ध हो और सस्ती हो। महंगी पढ़ाई केवल कुछ लोगों तक ही पहुंच सकती है।

शिक्षा एक मानवाधिकार है। इस अधिकार की पूर्णता तभी हो सकती है, जब इसे सभी तक बराबर के साथ पहुंचाया जाए। शिक्षा को सरकारों के आने-जाने के क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह आर्थिक मुद्दों से प्रभावित न हो और न ही किसी अन्य भावना से प्रभावित हो, बल्कि यह उन्मुक्त और सर्वसुलभ और सस्ती होनी चाहिए। बाजारीकरण की संस्कृति से अप्रभावित शिक्षा ही समाज को सुसंस्कृत और समय स्वरूप देने का माद्दा रखती है। हम सभी एक समान शिक्षा की तरफ जाएं और शिक्षा को व्यवस्थाय न मानकर देश की व्यवस्था का मूल मानें तो जिस तरह से देश के सैनिक सीमा पर डटे रहते हैं, वैसे ही शिक्षक समाज को मिलेंगे और वैसे ही विद्यार्थी भी देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाएंगे।

## भारत का नवाचार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तेज लहर ने जब दुनिया को घेरा, तब भारत मात्र दर्शक नहीं, बल्कि एक सशक्त भागीदार बन कर उभरा। कृत्रिम मेधा (एआइ) की क्रांति ने केवल डिजिटल भारत की अवधारणा को नया आयाम दे रही है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, औद्योगिक परिदृश्यों और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की नई इबारत लिख रही है। आज एआइ केवल रोबोटिक्स या स्वचालित प्रणालियों तक सीमित नहीं, बल्कि यह स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन ला रही है। भारत का 'डिजिटल इंडिया' अभियान, जो डेटा-संचालित अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए शुरू हुआ, अब 'एआइ-समर्थ भारत' के रूप में वैश्विक क्षितिज पर अपनी पहचान बना रहा है। भारत में नवाचार का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दस हजार से अधिक नवउद्यमों, जिनमें अनेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। संस्कृति और परंपरा से समृद्ध भारत अब एआइ के माध्यम से वैश्विक मंच पर नई संभावनाओं को आकार दे रहा है।

*- अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश*

## बिगड़ती जीवनशैली

आजकल खानपान और मोटापे को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। युवाओं की जीवन शैली पर चिंता जताई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री भी खानपान और मोटापे को लेकर अपनी चिंता जता चुके हैं। कहा गया है कि रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी जागना चाहिए, इससे सेहत तंदुरुस्त रहेगी और पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। मगर युवाओं का इस बात से दूर-दूर तक का नाता नहीं है। आज का युवा देर रात तक जागता है और दोपहर तक सोता है। सूर्योदय तो शायद उसने कभी देखा ही नहीं। डिब्बाबंद खाना या बर्गर-पिज्जा आदि खाना पसंद करता है जोकि मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण है। पुराने लोग कहा करते थे कि खाना निश्चित समय पर ही खाना चाहिए, लेकिन आज के युवाओं का खाने का कोई भी समय निश्चित नहीं है। हम अपने घरों में बच्चों को आधी रात को भी खाते हुए देख सकते हैं। जिंदगी में अनुशासन की कमी की वजह से ही वे बीमार हो रहे हैं।

*- धरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली*

## बढ़ती भागीदारी

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल आठ मार्च को महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का सम्मान करने और स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1908 में न्यूयार्क में महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए विरोध प्रदर्शन से हुई थी। वर्ष 1910 में क्लारा जेटकिन ने इसे अंतरराष्ट्रीय रूप देने का प्रस्ताव रखा और 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। मगर अफसोस कि कई देशों में महिलाएं अभी भी शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसरों में पीछे हैं। यह दिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। हिंसा और भेदभाव के खिलाफ जागरूकता आई है। घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर भेदभाव के मुद्दों पर ध्यान दिया जाने लगा है। विज्ञान, राजनीति और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिला दिवस समानता और न्याय की दिशा में कदम है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है।

*- वंदना कुमार नाथ, बरपेटा, असम*

## संस्कृति और स्वच्छता

हमारी संस्कृति में स्वच्छता का विशेष महत्त्व है। मगर आमतौर पर हमारी साफ-सफाई घरों तक ही सीमित रहती है। बाहर की साफ-सफाई पर हम ध्यान नहीं देते हैं। आज बसों और रेलगाड़ियों में, सड़कों तथा पर्यटन स्थलों पर गंदगी दिखाई दे रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पारिवारिक और सामाजिक उत्सव के दौरान सड़कों पर कचरे का अंबार लग जाता है। गंदगी के कारण ही बीमारियां फैलती हैं। कोई दो राय नहीं कि स्वच्छता के प्रसार से शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी आई है। इसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि स्वच्छता अभियान निरंतर चलता रहे। हमें कचरे के निपटान की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अब सभी शहरों में कूड़े का पहाड़ दिखाई देने लगा है। स्वच्छता को हमें अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।

*- हिमांशु शेखर, गया*

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

जब तक एक भी महिला परतंत्र है, तब तक मैं आजाद नहीं हूं। भले ही उसका बंधन, मेरे बंधन से बहुत अलग हो। -आंद्रे लॉर्ड

## टर्म इंश्योरेंस और महिलाएं

पॉलिसी बाजार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने वाली 44 फीसदी महिलाएं अब एक करोड़ रुपये या उससे अधिक का कवर ले रही हैं, जो बीमा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती जागरूकता और वित्तीय सुरक्षा की ओर उनके झुकाव को दर्शाता है। दरअसल, आज महिलाएं केवल गृहस्थी चलाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अधिक मूल्य के टर्म इंश्योरेंस को अपनाकर अब दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं। यह उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तो है ही, परिवारों के लिए भी एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। आंकड़े बताते हैं कि टियर-1 शहरों में यह प्रवृत्ति मजबूत हो रही है, लेकिन छोटे शहरों में इसका प्रभाव सीमित है, तो इसके पीछे छोटे शहरों की महिलाओं में बीमा उत्पादों को सीमित जानकारी, परंपरागत सोच और आर्थिक प्राथमिकताओं में अंतर जैसी वजहें हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में टर्म इंश्योरेंस खरीदने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 18 फीसदी हो गई है, जिसमें वेतनभोगी और स्वरोजगार वाली महिलाएं स्वाभाविक ही सबसे आगे हैं, लेकिन ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह है कि इस मामले में गृहणियां भी पीछे नहीं हैं, जिनकी टर्म इंश्योरेंस की खरीद में करीब 39 फीसदी की हिस्सेदारी है, जिससे यह भी पता चलता है कि वित्तीय नियोजन अब केवल कामकाजी वर्ग की रुचि व जरूरत का विषय नहीं रह गया है। यह संकीर्ण सोच ही है, जिसके तहत समाज में महिलाओं की भूमिका को घर संभालने तक ही सीमित माना जाता है, बल्कि अब स्वास्थ्य बीमा में भी महिलाओं की भागीदारी का पिछले दो वर्षों में 15 से 22 फीसदी होना और इसमें भी उच्च कवरेज वाली योजनाओं की तरफ रुझान बताता है कि महिलाएं अब अपने स्वास्थ्य खर्चों को लेकर भी सजग हो रही हैं। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए नागरिकों का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। इस लिहाज से भी देखें, तो महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बढ़ती प्रवृत्ति आश्वस्त करने वाली है। हालांकि, यह भी सच है कि महिलाओं के एक बड़े वर्ग को बीमा योजनाओं के लाभ और उनके महत्व की पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसे में इस बदलाव को गति देने के लिए जरूरी है कि सरकार और बीमा कंपनियां इस रुझान को प्रोत्साहन दें और अधिक समावेशी योजनाएं भी लाएं।

## वे अर्थव्यवस्था की सूरत बदल रही हैं

**देश भर में महिला उद्यमी बाधाओं को तोड़ रही हैं और उद्योगों को नए ढंग से परिभाषित कर रही हैं। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का शोध भी कहता है कि भारत में महिला समानता को बढ़ावा देने से 2025 के अंत तक अर्थव्यवस्था में 770 अरब डॉलर की वृद्धि हो सकती है।**

**लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेशन**
*पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण की पुत्री*

अपनी आर्थिक यात्रा में भारत एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां इसके समावेशी और टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने की क्षमता है। आबादी में 48 फीसदी की हिस्सेदारी के बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महिलाओं का योगदान मात्र 18 फीसदी है, जो आर्थिक भागीदारी में लैंगिक खाई को रेखांकित करता है। हालांकि, महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों का उदय इस अंतर को पाटने, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का एक प्रभावशाली अवसर प्रदान करता है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के शक्तिशाली इंजन साबित हुए हैं। ये न केवल रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, बल्कि क्षेत्रीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करके स्थानीय आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, उद्यम पंजीकरण पोर्टल की रिपोर्ट है कि अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित एमएसएमई 20.39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश भर में महिला उद्यमी बाधाओं को तोड़ रही हैं और उद्योगों को नए ढंग से परिभाषित कर रही हैं। सांगली में रहने वाली एक इंजीनियरिंग स्नातक युवती ने बैंक से चार लाख रुपये का ऋण लेकर फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न व्यवसाय शुरू किया और लगभग 20 श्रमिकों के लिए रोजगार सृजित किए हैं। आज उसका टर्नओवर 40 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में महिला समानता को बढ़ावा देने से 2025 के अंत तक अर्थव्यवस्था में 770 अरब डॉलर की वृद्धि हो सकती है। महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम इसके प्रमुख चालक हो सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां वे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं, बुनियादी ढांचे में सुधार

कर सकते हैं और सामाजिक पूंजी को बढ़ा सकते हैं। महिला उद्यमियों में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें कई ऐसी व्यवस्थागत अड़चनों का सामना करना पड़ता है, जो उनके विकास को बाधित करती हैं। वित्तीय उपेक्षा बहुत गंभीर है, क्योंकि दुनिया भर में 65 फीसदी महिलाओं की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। भारत में यह स्थिति लालफीताशाही और सरकारी सहायता योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी के कारण और भी बदतर हो गई है। इसके अलावा, उद्योगों में 88 फीसदी महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिससे उनके सामने नौकरी की असुरक्षा तो रहती ही है, सामाजिक लाभों से भी वे वंचित रहती हैं।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं के बीच उद्यमशीलता सीमित है। भारत में केवल 10 फीसदी स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिसका मुख्य कारण ऋण तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त मार्गदर्शन और औपचारिक वित्तपोषण विकल्पों की कमी है। ये चुनौतियां सामूहिक रूप से महिला उद्यमियों की प्रगति और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बाधित करती हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने कई पहल और नीतियां शुरू की हैं। पिछले कुछ वर्षों में, जेंडर बजट में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो कुल केंद्रीय बजट का 8.86 फीसदी है, हालांकि 100 फीसदी महिला-केंद्रित योजनाएं स्थिर हो गई हैं, जो कार्यान्वयन अंतराल को उजागर करती हैं। मुद्रा योजना जैसी प्रमुख पहलों ने किफायती ऋण प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया है। हालांकि, मुद्रा योजना के तहत मौजूदा ऋण राशि अक्सर स्थायी व्यवसाय शुरू करने के लिए अपर्याप्त होती है, जिसके लिए उच्च आवंटन और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। महिला उद्यमियों के लिए अवसरों का परिदृश्य बहुत व्यापक है, जिसमें वित्तीय समावेशन से लेकर डिजिटल एकीकरण और नीतिगत सुधार तक के क्षेत्र शामिल हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 ने एक नई ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत पांच साल में पांच लाख महिला उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, जीईएम और ओएनडीसी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने से महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच में काफी सुधार हो सकता है। डिजिटल साक्षरता और डिजिटल भुगतान में प्रशिक्षण बढ़ाने से परिचालन को सुव्यवस्थित, नकदी पर निर्भरता में कमी, वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सकता है और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। परामर्श और कौशल विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संरचना संबंधी कार्यक्रम महत्वपूर्ण व्यावसायिक अंतर्दृष्टि, अनुपालन ज्ञान और प्रबंधन कौशल प्रदान कर सकते हैं। महिला उद्यमिता मंच और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी पहल पारंपरिक शिल्प और क्षेत्रों में महिलाओं का समर्थन करने के लिए तैयार की गई हैं, जिससे स्थायी विकास हो सकता है।

नीतिगत सुधार, जैसे कि वंचित क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए एक अलग कर छूट व्यवस्था करना तथा स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को मजबूत करना, वित्तीय समावेशन व आर्थिक सशक्तीकरण को और अधिक बढ़ावा दे सकता है, जिससे अधिक समावेशी आर्थिक परिदृश्य का निर्माण हो सकता है। भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए, मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना और सहयोगी वातावरण बनाना अनिवार्य है। इसमें महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं को अधिक संसाधन आवंटित करके प्रत्यक्ष वित्तपोषण बढ़ाना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना शामिल है। महिला उद्यमियों पर प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए अनुपालन, लाइसेंस और कर दाखिल करने पर स्पष्ट मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम न केवल आर्थिक विकास के उपकरण हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक भी हैं। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने का यही वक्त है, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध होती हैं।

edit@amarujala.com

## नारी

## मुझे इस जिंदगी से सब कुछ चाहिए

**जिस दिन औरत अपनी कमजोरियों से नहीं, बल्कि अपनी ताकतों से प्यार करना सीख जाएगी, उसी दिन से प्यार उसके लिए खतरा नहीं, बल्कि जीवन बन जाएगा।**

**सिमोन द बोउआ**

महिला को रसोई या शयनकक्ष में बंद कर दिया जाता है, और इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है कि उसका क्षितिज सीमित है। उसके पंख काट दिए जाते हैं, और यह इल्जाम लगाया जाता है कि वह उड़ना नहीं जानती या उड़ ही नहीं सकती। चूंकि उसके लिए भविष्य का द्वार खोल दिया जाए, तो वह वर्तमान में रहने के लिए मजबूर नहीं होगी।

स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि उसे बना दिया जाता है। औरत को औरत होना सिखाया जाता है। औरत बनी रहने के लिए उसे अनुकूल किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण से यह समझ में आएगा कि प्रत्येक मादा मानव जीव अनिवार्यतः एक औरत नहीं है। जब पुरुष ने औरत को अन्यता प्रदान की, तो औरत भी सहअपराधी हो गई। बहुधा तो औरतें खुद ही अपनी इस नगण्यता में संतुष्ट रहती हैं। मर्दों को इन्सान समझा गया और औरतों को मादा। जब-जब यह मादा इन्सानों की तरह बर्ताव करती, तब-तब इसके सिर पर मर्दों की नकल करने के इल्जाम लगा दिए जाते। वह इस ब्रह्मांड और यहां तक कि समय के अस्तित्व को भी नकार सकती थी, लेकिन किसी भी कीमत पर यह नहीं मान सकती थी कि प्यार शाश्वत नहीं होता।

मर्द, औरत से इसलिए नहीं बंधता कि वह औरत को खुशियां दे सके, असल में, वह अपने लिए खुशी की तलाश में औरत के पास तक जाता है। दो अलग-अलग प्राणी, अलग-अलग परिस्थितियों और स्वतंत्रता में आमने-सामने होते हैं तथा एक-दूसरे के माध्यम से एक-दूसरे के अस्तित्व के औचित्य की तलाशने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा जेंडरिम और संभावनाओं से भरा एक साहसिक जीवन जीते हैं। औरत के प्रति जो पुरुष जितना आक्रामक और घृणापूर्ण होता है, वह उतना ही अपनी हीनग्रंथि का शिकार है। दरअसल, जो पुरुष औरत का जितना अधिक अपमान करता है, वह मानसिक रूप से उतना ही स्वयं में अपमानित होने की आशंका से ग्रस्त रहता है।

जिस दिन औरत अपनी कमजोरियों से नहीं, बल्कि अपनी ताकतों से प्यार करना सीख जाएगी, जिस दिन वह खुद से भागना छोड़कर और खुद की तलाश में निकल जाएगी, साथ ही अपना मान करना तथा पूरे दावे के साथ अपनी बात रखना जान पाएगी, उस दिन से प्यार पर उसका भी उतना ही हक होगा, जितना किसी मर्द का और उसी दिन से प्यार उसके लिए खतरा नहीं, बल्कि जीवन बन जाएगा। यों तो उसने खुद को इतना साधा है कि यह कभी न बदले, लेकिन किसी दिन अंगुलियों की एक छुअन भर से वह पिघल उठेगी।

मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी जरूरतें और तमाम जिम्मेदारियां को उठाने में पूरी तरह सक्षम होना-ये कुछ ऐसी बातें हैं कि कभी भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। न तो कोई मुझे पूरी तरह समझ सकता है और न ही प्यार कर सकता है। वह सिर्फ मैं हूं, जिसने खुद को जाना और खुद को चाहा भी है। मुझे इस जिंदगी से सब कुछ चाहिए। मैं औरत भी होना चाहती हूं और मर्द भी। मुझे अनगिन दोस्त चाहिए और मेरा अपना अकेलापन भी। ढेरों काम करने हैं मुझे और बेहतरीन किताबें लिखनी हैं। खुद की खुशी के लिए यात्राओं पर निकल जाना है। मुझे खुदगर्ज होना है और खुदगर्जी से दूर भी रहना है। मैं जानती हूं कि ये सारी चीजें एक साथ पा लेना बेहद मुश्किल है और इस मुश्किल को सोचना भी मुझे गुस्से से पागल कर देता है।

मुझे एआई के इन्सानों पर हावी होने के 10 से 20 फीसदी ही आसार लगते हैं। -पॉल क्रिस्टियानो

एआई न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह हमारे उपयोग के लिए एक तकनीकी टूल है। -ओरेन एटज़ियोनी

## प्रेम का चुंबक सबको खींचता है

**जो सबसे प्रेम करता है, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता। यह दूसरे के दिल में ऊंची भावना पैदा कर देता है। कौरवों ने कहा था कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन विनोबा के प्रेम ने लाखों एकड़-भूमि इकट्ठी करा दी।**

**यशपाल**

जीवन धारा

सेवा के लिए पहली शर्त प्रेम है अर्थात जिसके दिल में प्रेम है, वही सेवा कर सकता है। टॉल्स्टॉय ने कहा है, 'प्रेम स्वर्ग का रास्ता है।' बुद्ध का कथन है, 'प्रेम इन्सानियत का एक फूल है।' रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, 'प्रेम संसार की ज्योति है और प्रेम अमरता का समंदर है।' विक्टर ह्यूगो का कहना है, 'जीवन एक फल है और प्रेम उसका मधु।'

अलग-अलग शब्दों में सभी महापुरुषों ने प्रेम का बखान किया है। वास्तव में प्रेम मानव-जाति की बुनियाद है। प्रेम ऐसा चुंबक है, जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। जिसके हृदय में प्रेम है, उसके लिए सब अपने हैं। जो सबसे प्रेम करता है, उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता। आप जानते हैं, आदमी को भूमि से कितना मोह होता है। कौरवों ने कहा था कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन विनोबा के प्रेम ने लाखों एकड़-भूमि इकट्ठी करा दी। उन्होंने लोगों से यह नहीं कहा कि मुझे जमीन दो। नहीं दोगे, तो कानून से या जोर-जबर्दस्ती से छिनवा दूंगा, जिसका हृदय प्रेम से सराबोर हो, वह ऐसी भाषा कैसे बोल सकता था। उन्होंने कहा, 'मेरे प्यारे भाइयो, मैं तुम्हारे घर पर आया हूं। तुम्हारे पांच बेटे हैं, छठा होता, तो उसका भी लालन-पालन करते न। मुझे अपना छठा बेटा मान लो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो।' विनोबा का यह प्रेम ही था, जिसने लोगों के दिलों को मोम बना दिया। किसी-किसी ने तो अपनी सारी-की-सारी जमीन उनके चरणों में रख दी। प्रेम के इतने बड़े चमत्कार की घटनाएं हम किताबों में पढ़ते हैं, पर आज के युग में विनोबा ने उसे सामने करके दिखा दिया। इसलिए जिसका हृदय निर्मल है, उसी में ऐसे महान प्रेम का निवास रहता है। प्रेम तो हम अपने बच्चों और सगे-संबंधियों से भी करते हैं, लेकिन उसमें उनसे भी बदले में कुछ न कुछ लेने का भाव रहता है। लेकिन असली प्रेम तो वह है, जिसमें किसी प्रकार की बदले की भावना न हो। इतना ही नहीं, उसमें विरोधी के लिए भी जगह हो। गर्मी से व्याकुल होकर हम जाने कितनी बार सूरज को कोसते हैं, पर सूरज कभी हम पर नाराजगी दिखाता है? हम धरती को रोज पैरों से दबाते हुए चलते हैं, पर वह कभी गुस्सा होती है? यदि गुस्सा होकर सूरज धूप और रोशनी न दे, धरती अन्न न दे, हवा प्राण न दे, तो सोचिए, हम लोगों की क्या हालत होगी! दरअसल, वे प्रेम इसलिए देते हैं, कि बिना दिए रह नहीं सकते। यही है वास्तविक प्रेम।

## चैटजीपीटी और बीस साल पुराना उपन्यास

*द न्यूयॉर्कर के स्तंभकार जे कैंसियन कांग के पुराने उपन्यास को पूरा करने में चैटजीपीटी ने मदद तो की, लेकिन इससे उसकी सीमाओं का भी पता चला।*

AI समय

यह करीब बीस साल पहले की बात है। एक युवा उपन्यासकार के रूप में वह मेरे शुरुआती दिन थे। तब मैंने सोचना शुरू ही किया था कि मुझे अपनी कहानियां लिखनी चाहिए। मुझे पता था कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानता था कि अगर मुझे साहित्य में कामयाब होना है, तो मुझे कुछ तो ऐसा गढ़ना होगा, जो कहानी-सा लगे, जिसमें एक शुरुआत हो, मध्य हो और फिर अंत हो।

उस वक्त *पोस्टमॉडर्निज्म* नामक एक वेबसाइट थी, जो मजेदार ढंग से कंटेंट तैयार करती थी। मेरे ग्रेजुएट स्कूल के दोस्त और मैं इस वेबसाइट के खासे दीवाने थे। मैंने सोचा कि सामान्य-सी कोडिंग से तैयार की गई वेबसाइट अगर इतना कुछ कर सकती है, तो यह कहानी लिखने में भी मेरी मदद कर सकती है। मुझे पता था कि कहानी के प्लॉट के कुछ सरल नियम होते हैं, मेरे दिमाग में कहानी को लेकर विचार भी थे, मुझे बस यह समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें जोड़कर मैं कहानी का रूप कैसे दूं। मैंने कंप्यूटर-विज्ञान के कुछ स्नातक छात्रों के साथ एक बॉट बनाने की संभावनाओं पर बात भी की थी, जो मुझे अपनी कल्पना से बस यह बता सके कि मेरी कहानी की शुरुआत के बाद कौन-कौन से घटनाक्रम संभावित हो सकते हैं। मुझे पता था कि विचार के स्तर पर मुझे थोड़ी भी मदद मिल गई, तो कहानी तैयार करने लायक जोड़-तोड़ तो मैं कर ही लूंगा।

कुछ महीनों की खोजबीन के बाद ही मुझे स्पष्ट हो गया कि अपनी योजना के लिए मुझे बहुत अधिक सहयोग नहीं मिलने वाला। मुझे याद है कि कंप्यूटर विज्ञान के एक छात्र ने मुझसे कहा था कि बॉट्स केवल नकल कर सकते हैं, लेकिन वे कभी यह नहीं बता सकते कि जब आपको देखकर कोई मुस्कराता है, तो आप असल में कैसा महसूस करते हैं। मैं इससे सहमत भी था, लेकिन मेरे मन में यह सवाल हमेशा रहा कि आखिर बॉट संवेदनाओं के क्षेत्र में कमजोर क्यों पड़ जाते हैं।

चैटजीपीटी आज सबके सामने है, लेकिन जिस भाषा मॉडल पर यह आधारित है, उन पर पिछली आधी सदी से भी ज्यादा समय से काम हो रहा है। भाषा मॉडल से जब आप कुछ पूछते हैं, तो वह आपके पूछे गए शब्दों पर गौर करता है, उनकी तुलना इंटरनेट पर मौजूद संबंधित सामग्री से करता है और फिर आगे का अनुमान लगाता है।

बहरहाल, मुझे तो सिर्फ एक उपन्यास लिखना था, तो मैंने चैटजीपीटी से पूछा, 'मुझे पहचान के संकट से जूझ रहे एक 27 वर्षीय व्यक्ति के बारे में कहानी लिखनी है, मैं शुरुआत कैसे करूं?' चैटजीपीटी ने कुछ सुझाव दिए, जो मुझे बेहद सामान्य लगे।

मुझे लगा कि शायद मेरे सवाल में ही कुछ समस्या हो, तो मैंने दूसरी तरह से पूछा, 'एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी?' चैटजीपीटी ने मुझे सलाह दी कि एक मर्डर मिस्ट्री उपन्यास की शुरुआत एक लाश से होनी चाहिए। जब मैंने उससे पूछा कि हत्या का हथियार कौन-सा होना चाहिए, तो उसने दार्शनिक अंदाज में मुझे मशविरा दिया, 'यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कहानी की घटनाओं और पात्रों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा।' मैंने उपन्यास की कहानी और इसके पात्रों को लेकर चैटजीपीटी से कई विकल्प मांगे, जो उसने दिए भी, लेकिन उसकी हर कहानी में एक बासीपन दिखा। वह जो कर रहा है, यकीनन प्रभावशाली है, लेकिन ये उसकी कहानियां नहीं हैं। मैंने चैटजीपीटी के साथ घंटों बातें कीं, लेकिन फिर मुझे तेज झुंझलाहट महसूस हुई। वह जो बोल रहा है, सुखद है, लेकिन वह एक ऐसा साथी है, जो आपको वही बताता है, जो आप सुनना चाहते हैं। रेचट, जिसने अपना पूरा कॅरियर मशीन लर्निंग में बिताया है, से मैंने पूछा कि क्या उन्हें चैटजीपीटी द्वारा रचित साहित्य, कला व संगीत की दुनिया में रुचि है। रेचट ने पते की बात कही कि ये एआई तंत्र दरअसल सामूहिक इंटरनेट का प्रतिबिंब है। हम पूछते हैं, ये इंटरनेट की दुनिया को खंगालती है, और फिर औसत लौटाती है, जाहिर है कि यह उबाऊ ही होगा। हां, अगर गुणवत्ता से कोई सरोकार ही न हो, तो फिर तो चैटजीपीटी लाजवाब है।

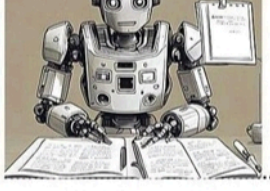

### जीरो-शॉट लर्निंग

*यह मशीन लर्निंग की वह तकनीक है, जिसमें एआई मॉडल को उन चीजों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता प्रदान की जाती है, जिनके बारे में मॉडल को पहले से प्रशिक्षण या उदाहरण नहीं दिया गया। मॉडल के सामने बिल्कुल नई चीज आए और उसे पहले से संबंधित चीज के बारे में न तो कोई जानकारी हो और न ही उसके पास उससे मिलता-जुलता कोई उदाहरण हो, तब वह पहले से प्रशिक्षित किसी सहायक सामग्री की सहायता लेगा। जैसे किसी बच्चे को सेब, अंगूर, अनार आदि फलों की जानकारी है, यदि उसके सामने अभ्यास कोबी फल दे दिया जाए, तो बच्चा उसके आकार और स्वाद के आधार पर अनुमान लगाएगा कि यह भी कोई फल ही होगा। इसका उपयोग तस्वीर पहचानने, रोबोट द्वारा नई वस्तुएं संभालने आदि में किया जाता है।*

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 8 मार्च • 2025
www.rashtriyasahara.com



अनमोल वचन

*दुनिया को सपने देखने वाले चाहिए और दुनिया को काम करने वाले चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया को ऐसे सपने देखने वाले चाहिए जो काम करते हों।*
-सारा वैन ब्रैथनैच

# वापसी समस्या का अंतिम हल

गुलाम कश्मीर

प्रमोद भार्गव

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर के हालात और भारत सरकार की तरफ से उठाए गए संवैधानिक कदमों के बारे में लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में 'विश्व में भारत का उदय और भूमिका' विषय पर बोलते हुए कहा, 'कश्मीर विवाद का समाधान कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद संभव हो जाएगा। यह हिस्सा अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। वैसे हमने कश्मीर के सिलसिले में ज्यादातर मुद्दों का हल निकाल लिया है। इस वाक्त कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद-370 का समापन पहला कदम था। कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बढ़ाल करना दूसरा कदम था। तीसरा कदम कश्मीर में भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराना था। इसमें मत प्रतिशत का अच्छा होना इस बात की तस्दीक है कि जम्मू-कश्मीर की जनता भारतीय लोकतंत्र का समर्थन कर रही है। अब इस हिस्से के कश्मीर में आते ही इस समस्या का समाधान पूरी तरह हो जाएगा।'

गुलाम कश्मीर के हिस्से में गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आते हैं। भारत की आजादी के पहले कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। यहां डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह शासक थे। कश्मीर में मुसलमानों की आबादी अधिक थी। इसलिए पाकिस्तान का मानना था कि कश्मीर उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। इस मानसिकता के चलते पाक ने कश्मीर राज्य पर पाकिस्तान में विलय का नाजायज दबाव बनाया लेकिन हरि सिंह इस दवाब में नहीं आए। तब 1948 में पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के वेश में कश्मीर पर हमला कर दिया था किंतु हरि सिंह की समय पर भारतीय सेना ने मदद की और पाक सेना को न केवल खदेड़ दिया, बल्कि संपूर्ण कश्मीर के एक तिहाई हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा और 5 जनवरी, 1949 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। युद्ध विराम के वक्त जो सेनाएं जिस भूमि पर थीं, उसे ही युद्ध विराम की रेखा मान लिया गया। यही आज नियंत्रण रेखा (एलओसी) है। इस कारण पीओके, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान के हिस्से में है और श्रीनगर समेत शेष कश्मीर भारत के हिस्से में है।

जिस आतंकवाद का जनक पाकिस्तान रहा है, वही आतंकवाद उसके लिए पीओके में चुनौती बन कर उभर रहा है। आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बलूचिस्तान प्रांत के तुरबाद नगर में नौसैनिक अड्डे पर

आतंकवादियों ने गोली बरसाते हुए हमला किया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इलाके में चीनी नागरिकों के काफिले पर हमला बोल दिया। इसमें पांच चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। ये इंजीनियर दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में लगे थे। इन हमलों की जुम्मेबारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की मजीद ब्रिगेड ने ली है। इस्लामाबाद से 200 किमी. दूर स्थित दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण चीनी कंपनी कर रही है। ग्वादर बंदरगाह पर भी आतंकी हमला हो चुका है।

दरअसल, बलूचिस्तान प्रांत के नागरिक मानते हैं कि पाकिस्तान सरकार उनके प्रांत के हितों की लंबे समय से अनदेखी कर रही है। यहां लोग इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार धन के लालच में चीन के सुरसामुख में फंस चुकी है। देश में चल रही आर्थिक बदहाली के कारण भी वह चीन का दामन नहीं छोड़ पा रही है। चीन से उसकी मित्रता का कारण धन का लालच तो है ही भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते भी हैं। पीओके में आतंकी शक्तियां इतनी मजबूत हो गई हैं कि पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान से भी मधुर संबंध बनाए रखना मुश्किल हो रहा है।

गिलगिट-बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों ने अपने क्षेत्र पर पाकिस्तान के बलात कब्जे को कभी नहीं स्वीकारा। यहां राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाजें उठ रही हैं, सरकार इन लोगों पर दमन का सिलसिला जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की कुल भूमि का 40 फीसद हिस्सा यहीं है लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच हैं। इसलिए इसे गिलगिट-बलूचिस्तान भी कहा जाता है। 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और संघर्ष और तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आए। इनमें प्रमुख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है।

निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद यहां की विधानसभा को अपने बूते कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सारे फैसले एक परिषद लेती है, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। लिहाजा, यहां के अस्तोर, दियामिर और हुनजा समेत उन सब इलाकों में विद्रोह की आग सुलगी रहती है, जो शिया बहुल हैं। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में शिया और अहमदिया मुस्लिमों समेत सभी धार्मिक अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में चीन बड़ा निवेश कर रहा है। ग्वादर में वहां सा बंदरगाह बनाया है। चीन की एक और बड़ी योजना है, 'चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' जिसकी लागत 3 लाख 51 हजार करोड़ है। यह गलियारा गिलगिट-बाल्टिस्तान से गुजर रहा है। इस गलियारे के निर्माण में लगे चीनी नागरिकों की आतंकी संगठन बीएलए हत्याएं कर रहा है। चूंकि यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से भारत का है, इसलिए भारत भी इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है। पाकिस्तान रणनीतिक रूप से गिलगिट-बाल्टिस्तान को पंचवा प्रांत बना लेने की फिराक में है। चूंकि यह क्षेत्र आधिकारिक रूप से भारत के जम्मू-कश्मीर प्रांत का हिस्सा है, इसलिए यहां कोई भी बदलाव कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन होगा। पाकिस्तान यहां सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ा कर इस पूरे क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बदलने के प्रयास में भी लगा है। इन कारणों के चलते यहां के मूल बलूचों की पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त नाराजगी है और वे निर्णायक लड़ाई लड़के भारत में विलय होने की कोशिश में लगे हैं।

*(लेख में विचार निजी हैं)*

> गिलगिट-बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों ने अपने क्षेत्र पर पाकिस्तान के बलात कब्जे को कभी नहीं स्वीकारा। यहां राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाजें उठ रही हैं, सरकार इन लोगों पर दमन का सिलसिला जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की कुल भूमि का 40 फीसद हिस्सा यहीं है लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच हैं

## पीओके के लिए वैश्विक समर्थन

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान जम्मू-कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद होगा जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। यह याद रखना चाहिए कि 22 फरवरी, 1994 को भारत की संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें दोहराया गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, और रहेगा। पाकिस्तान को वह हिस्सा छोड़ना होगा जिस पर उसने कब्जा जमा रखा है। वास्तव में जयशंकर की टिप्पणी संसद के इसी प्रस्ताव की प्रतिध्वनि है। जयशंकर ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत का पहला प्राथमिक कदम था। सूबे में विकास, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय की बहाली दूसरा कदम और

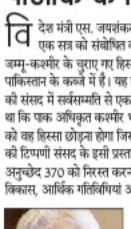

यहां निष्पक्ष चुनाव कराना तीसरा कदम था। वास्तव में भारत अच्छी तरह से जानता है कि पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर उसके लंबे समय से चले आ रहे दावे के अलावा पाकिस्तान का भी दावा है और स्वयं उन कश्मीरियों का अपना दावा है जो उस हिस्से की आजादी की मांग कर रहे हैं या भारत में विलय के लिए मांग कर रहे हैं। चौथा दावा चीन का भी है जिसने वहां भारी निवेश किया है। इस अर्थ में जयशंकर का कहना जायज है कि पीओके भारत के नियंत्रण में आ जाए तो वह भी भारतीय जम्मू-कश्मीर की तरह विकास के रास्ते पर बढ़ सकता है। परंतु व्यवहार में यह काम इतना आसान नहीं है। हाल-फिलहाल यह हो सकता है कि पीओके में पाकिस्तानी सरकार के जो जुल्म बढ़ रहे हैं और जिनसे वहां के निवासी आक्रांत रहे हैं, उनके लिए वैश्विक समर्थन जुटाया जाए और स्वयं भारत भी उन्हें स्पष्टतः आश्वासन दे कि वह उनकी जायज मांगों का समर्थक है। गिलगिट-बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों ने अपने क्षेत्र पर पाकिस्तान के बलात कब्जे को कभी स्वीकारा नहीं है। यहां राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान की कुल भूमि का 40 फीसद हिस्सा वहीं है, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब एक करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस इलाके में सर्वाधिक बलूच हैं। इसलिए इसे गिलगिट-बलूचिस्तान भी कहा जाता है। भारत को पीओके के निवासियों की पूरी चिंता है। लेकिन भारत का यह पक्ष केवल बातों में ही नहीं, व्यवहार में भी सामने आना चाहिए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के इस हिस्से को भारत में वापस लाने का एक रास्ता यह हो सकता है।

## भाषाई सियासत

महाराष्ट्र को महाराष्ट्र और मुंबई की भाषा है, यहां रहने वाले व्यक्ति को इसे सीखना और बोलना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संघ के वरिष्ठ नेता भैयाजी के बयान के बाद उठे विवाद पर कहा। जोशी ने कहा था, मुंबई की एक भाषा नहीं है, मुंबई में कई भाषाएं हैं। अलग-अलग इलाकों की अलग-अलग भाषाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई आने वालों को मराठी सीखने की कोई जरूरत नहीं। इस पर विपक्षी महाअघाड़ी में शामिल राजनीतिक दल इस विवाद में एकजुट हो गए और जोशी के बयान की आलोचना की। हालांकि बाद में जोशी ने बयान से पलटते हुए अपनी टिप्पणी को गलत तरीके से देखे जाने की बात की और मराठी को महाराष्ट्र व मुंबई की भाषा बताया। शिवसेना (उद्धव) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जोशी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज

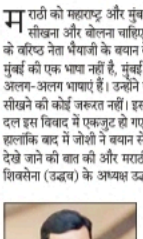

किया जाए। देश के संविधान में 22 भारतीय भाषा को मान्यता दी गई है, जबकि आधिकारिक भाषाएं आज भी हिन्दी व अंग्रेजी ही हैं। राजनीति के चलते 2018 में इसमें असमिया व मणिपुरी को भी इसमें शामिल किया गया। विभिन्न राज्यों के लोग अपनी-अपनी भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाते रहते हैं। स्थानीय स्तर पर इन भाषाओं का महत्त्व होने के बावजूद आम जनता के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दक्षिणी राज्यों में भी हिन्दी का जो विरोध होता है, उसके पीछे शुद्ध राजनीतिक कारण हैं। व्यावहारिक स्तर पर जोशी की बात सटीक होने के बावजूद भाषाई विवाद को तूल देने वाले भी अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। यह सही है कि मुंबई में मराठी बोलने वालों से गुजराती बोलने वाले भी कम नहीं हैं। दूसरे मुंबई हिन्दी फिल्मों का गढ़ है। जो दुनिया भर में देश की पहचान ही नहीं कायम करते हैं। भाषा के झगड़े को तूल देने की जरूरत तो नहीं है मगर भैयाजी को भी अपना बयान सिर्फ इसीलिए वापस लेना पड़ा क्योंकि इससे मराठी भाषियों की भावनाएं आहत होने की आशंकाएं बढ़ रही थीं। मातृभाषाओं से प्रेम करने वाले भारतीय अपने देश की अखंडता और सहिष्णुता को भाषाई विभेद से बहुत ऊपर आंकते हैं। यही कारण है कि हम इतनी सारी बोलियों व भाषाओं को साथ लेकर चलते रहे हैं।

कटाक्ष/ कबीरदास

## विश्व गुरु का ताज

अब विश्व गुरु के आसन पर मोदी जी के इंडिया की इससे बढ़कर ताजपोशी क्या होगी? अब तो विश्व आर्थिक फोरम तक कह रहा है कि भारत नंबर वन है। और ऐसे-वैसे मामले में नहीं, इन्फार्मेशन के मामले नंबर वन है। बताइए, जिस युग को ही सूचना का युग माना जाता है, उस युग में भी सूचना के मामले में नंबर वन। न सही सिंपल इन्फार्मेशन, मिसइन्फार्मेशन और डिसइन्फार्मेशन ही सही, हुआ तो इन्फार्मेशन का ही मामला। जब बदनाम होने में नाम हुआ माना जा सकता है, तो क्या मिस या डिस इन्फार्मेशन में अक्खा वर्ल्ड में नंबर वन होने को, विश्व गुरु का ताज नहीं माना जा सकता है। और यह भी विश्व गुरु वाले ही लक्षण हैं बल्कि सार्टिफिकेट ही कहिए कि गुजर जाने के तीन सौ साल बाद भी औरंगजेब, मुंबई से लेकर लखनऊ तक, विधानसभाओं में छाया हुआ है।

मुंबई में उसे न कम न ज्यादा, बस बाकी बादशाहों जैसा ही बादशाह बताने वालों को, पानी पी-पीकर कोसा ही नहीं जा रहा है बल्कि विधानसभा से सस्पेंड भी किया जा रहा है, तो लखनऊ में ऐसे लोगों को दुरुस्त करने का ठेका खोला जा रहा है। गली के खलीफा की बोली में कहा जा रहा है कि यहां भेज दो, हमें अच्छी तरह ठीक करना आता है। वाह भई औरंगजेब जीते जी तूने जो किया न किया, पर भूत बनकर भगवा सरकारों के खूब काम आ रहा है। मुंबई में मंत्रिमंडल से धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद भी, सतीश देशमुख की हत्या के मामले को दबाने के काम आ रहा है। और लखनऊ में योगी जी के इसके रहस्योद्घाटन से ध्यान हटाने के काम आ रहा है कि कुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई थी, एक से ज्यादा जगह भगदड़ हुई थी, भगदड़ में मौतें हुई थीं, पर मौतें दिन भर छिपाई गई थीं, कि कहीं भगदड़ न हो जाए। औरंगजेब तू तो वाकई बड़े काम की चीज है।

बस जरा मोदी जी के भी काम आकर और दिखा दे; नौजवानों के बेरोजगारी, महंगाई टाइप के गम भुला दे। विश्व गुरु का ताज तो तभी हमारा हो गया था, जब फेक न्यूज में हमें दुनिया में नंबर वन घोषित किया गया था। अब तो मिस-डिस इन्फोर्मेशन में भी नंबर वन घोषित हो लिए। ताजपोशी के लिए विश्व गुरु से और कितना इंतजार कराएगी, ओ दुनिया!

- एक आनुवंशिक अध्ययन से पता चला है कि अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से जीन प्रभावित हो सकते हैं, और अधेड़ लोगों को बुढ़ापा ज्यादा रफ्तार से गिरफ्त में ले सकता है
- अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रोफेसर एवं शोध की वरिष्ठ लेखिका जेनिफर आइजनशायर का यह अध्ययन पत्रिका 'साइंस एडवांसेस' में प्रकाशित हुआ है
- अध्ययन में 2010-16 के बीच छह साल की अवधि में 56 वर्ष और अधिक आयु के 3,600 से अधिक वयस्कों के रक्त के नमूनों का विश्लेषण किया गया था

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

ट्रंप व्यवसायी हैं। शांति चाहते हैं क्योंकि जानते हैं कि कारोबार के फलने-फूलने के लिए शांति अनिवार्य है। चारों ओर गोलियों की बौछार के बीच व्यापार नहीं हो सकता। यही कारण है कि ट्रंप चाहते हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म हो। लेकिन यूरोप चाहता है कि युद्ध जारी रहे और जेलेंस्की की भी यही इच्छा है।

पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू
@mkatju

महिला दिवस | संदीप भूषण

# ललक से पदक तक पहुंचीं बेटियां

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2004-05 में बिहार की ग्रामीण महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया कि राज्य में ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा के लिए प्रवेश लेने का अनुपात मात्र 1.21 प्रतिशत (पूरे देश में सबसे निचला स्थान) था। शहरों में भी कमोबेश स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।

यह रिपोर्ट उस दौर के शासनकाल के उस स्याह पक्ष की तरफ इशारा करती है जब लड़कियों के लिए घर की दहलीज लांघना असंभव था। पहाड़ के सपने जंगलराज के आतंक के आगे चकनाचूर हो जाते थे। खेलों में भाग लेने की चाहत मन के किसी कोने में दम तोड़ देती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद नीतीश कुमार ने आधी आबादी के आर्थिक, सामाजिक मजबूती सुनिश्चित की। नीतीश सरकार ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए जिससे न केवल शिक्षा में भागीदारी बढ़ी, बल्कि खेलों में भी दमखम दिखाया। आमिर खान की फिल्म दंगल का मशहूर संवाद है... 'म्हारी छोरियां छोरों से कम है कै' आज बिहार पूरे गर्व के साथ कह सकता है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं। थाईलैंड में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर नालंदा समेत पूरे बिहार को गर्व से भर देने वाली गोल्ही कुमारी हो या सीनियर नेशनल स्वीमिंग चैंपियनशिप में तीन गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की सर्वश्रेष्ठ तैराक पटना की माही श्वेता राज, या कि भारत की जूनियर महिला फुटबाल टीम में चयनित सिवान की खुशी कुमारी....ऐसी महिला खिलाड़ियों की लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवाया है। बहुत अधिक दिन नहीं गुजरे हैं। चार महीने पहले नवम्बर महीने की राजगीर की खूबसूरत वादों को ही टटोल लीजिए, जब बिहार वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर रहा था। स्टेडियम में उमड़ी दर्शकों की भीड़ यह बताने के लिए काफी थी कि बिहार की हवा अब बदल चुकी है। इस प्रतियोगिता में भारत समेत चीन, जापान, कोरिया, मलेशियेशिया जैसी टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के ठीक पहले आयोजित गौरव यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इस गौरव यात्रा का मकसद खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से जागरूकता फैलाना था। सरकारी स्तर पर इस तरह की

गंभीरता की जितनी सराहना की जाए कम है। नीतीश सरकार के इस तरह के गंभीर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पिछले ही साल उत्तराखंड में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की बेटियों ने लान बॉल की ट्रिपल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने बिहार की बेटियों की जीत की जमकर सराहना की थी। उन्होंने कहा कि मजबूत खेल राज्य के रूप में उभर रहा है। दरअसल, सरकार के प्रयासों में बिहार में एक तरफ खेलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ तो वहीं विभिन्न योजनाओं के जरिए महिला खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यहां 'प्रेरणा योजना' और 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' का जिक्र आवश्यक है। 'प्रेरणा योजना' के तहत सरकार खेल प्रतियोगिताओं द्वारा चयनित खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर बेहतर खिलाड़ी बनाने में जुटी है। खेल प्रतियोगिता दरअसल बिहार की महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसके जरिए नीतीश सरकार राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। सरकार खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिलाने पर ध्यान दे दे रही है ताकि राज्य 2032 और 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में पदक जीत सके। मेडल लाओ-नौकरी पाओ ने खिलाड़ियों में जोश का संचार किया है। पटना की माही श्वेतराज को नीतीश सरकार ने मेडल लाओ, नौकरी पाओ के तहत ही दरोगा नियुक्त किया है।

राजनीतिक रूप से काफी अहम प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर, जमुई समेत विभिन्न जिलों में एक दर्जन स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वेतिया और सुपौल में स्टेडियम के आधुनिकीकरण, कटिहार में राजेंद्र स्टेडियम को स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने का भी ऐलान किया है। बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में 2024-25 बजट पेश किया। बजट पर खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के नीतीश कुमार के विजन की छाप साफ दिखती है। बिहार में खेलों के लिहाज से अगले कुछ महीने महत्त्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जून में बिहार में महिला विश्वकप कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें भारत समेत 15 देशों की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। इसके अलावा सेपक टकराव भी पहली बार बिहार में आयोजित होने वाला है। नीतीश सरकार जिस तरह खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर कार्य कर रही है, उम्मीद है कि भविष्य में बिहार से कई धाकड़ खिलाड़ी निकलेंगी, जिन पर पूरे देश को गर्व होगा।

प्यार भरे संबंध | संत राजिन्दर

आधुनिक समाज में अधिकांश तनाव इतना अधिक शारीरिक नहीं होता जितना मानसिक होता है। हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, वे

ज्यादातर दिमाग के स्तर पर होती हैं। अक्सर दफ्तरों में या अन्य काम की स्थितियों में हमें उन लोगों के साथ समझौता करना पड़ता है, जिनकी राय और विचार हमसे अलग होते हैं। दुनिया को देखने के हम सभी के अलग-अलग तरीके हैं। हमें हर दिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। हमें देखना है कि क्या हम ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जो लोगों को अलग करते हैं या ऐसे कार्य जो लोगों को एक साथ लाते हैं? हमें अपने शब्दों पर नजर रखने की जरूरत है, ऐसा न हो कि हम किसी का दिल दुखाएं। क्या हमारे शब्द विभाजन का कारण बनते हैं या वे लोगों को एक साथ लाते हैं? प्यार भरे, सहानुभूति भरे शब्द लोगों को सहज महसूस कराते हैं, लोगों एक साथ लाते हैं; लेकिन हम शायद ही कभी अपने कहे हुए शब्दों या अपने किए हुए कार्यों के बारे में सोचते हैं। हमें हर उस व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करने के महत्त्व को समझने की आवश्यकता है। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली हैं और लंबे समय तक प्रभाव रखते हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि हम अपने शब्दों पर ध्यान दें और यह कि हम वास्तव में दूसरों को सुनने का प्रयास करें ताकि हमारे आस-पास के वातावरण में शांति और शांति लाने वाले प्रेमपूर्ण व्यवहार हो सकें। अपनी नौकरियों में हमें अक्सर समूहों में काम करना पड़ता है और बनाए गए नियमों पर निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या हमारे कार्य उन नियमों को बढ़ावा देते हैं जो लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं या क्या वे अधिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और कट्टरता को बढ़ावा देते हैं? एक बार बोले गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता है और यही कारण है कि हमें कुछ भी कहने से पहले दो बार सोचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब हम अपने शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो हम उनके जिंदगी जीने के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं और यह बदले में उन लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है जिनके साथ वे बातचीत करते हैं। हमारे शब्द, भले ही मजाक में बोले गए हों, पर वे किसी के जख्म भरने या नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं।

## रीडर्स मेल

### संभल कर आगे बढ़े भारत

भारत 2047 तक उच्च आय वाला राष्ट्र बनने के लिए काम कर रहा है, लेकिन देश के सामने कई चुनौतियां भी हैं जिसका हल निकालने की दरकार है। हालांकि विकास की राह पर देश चल चुका है, लेकिन देश अभी भी निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उच्च आय वाला राष्ट्र माने जाने के लिए भारत को प्रति वर्ष 7.8 फीसद की दर से विकास करना होगा, जो कि देश की पिछली विकास दर को देखते हुए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्या भारत मध्यम आय के जाल से बच पाएगा, जिसने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को जकड़ रखा है? क्या सुधार गति पकड़ेंगे और विकास सुनिश्चित करने के लिए निवेश में पर्याप्त वृद्धि होगी?

अंशु भारती, बेगूसराय, बिहार

### प्रोक्सी पावर खत्म होना जरूरी

भारत में पंचायत राज को मजबूत करने के लिए संविधान में सन 1992 में संविधान संशोधन किया गया था। जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई थी। पहले यह 33 फीसद थी, अब अधिकांश राज्यों में यह 50 फीसद हो गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी पंचायत राज के प्रभावी क्रियान्वयन के पक्षधर थे। इस व्यवस्था का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह भी रहा कि यदि महिला का निर्वाचन प्रधान या पंचायत समिति या जिला पंचायत परिषद में होता है तो अधिकांशतः पत्नी के एवज में उनके पति अथवा परिवार के पुरुष ही कार्यभार संभालते हैं। यहां तक की स्वतंत्रता दिवस पर झंडा रोहण कार्यक्रम में भी प्रधान पतियों की भूमिका देखी गई है। अब केंद्र सरकार का पंचायत राज मंत्रालय इस संदर्भ में कड़े कानून बनाने जा रहा है। वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा एक समिति की सिफारिश के अनुरूप दंड का प्रावधान किया जाएगा। इन सभी संस्थाओं के कार्यक्रमों का वीडियोग्राफी कराई जाएगी एवं अनेक ऐसे उपाय किए जाएंगे ताकि प्रोक्सी पावर की परंपरा को पूरी तरह समाप्त किया जाए।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

### विकास की राह पर जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जब से पदभार संभाला है तब से उनके व्यक्तित्व में गंभीरता और परिपक्वता दिखाई दे रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे विकास के ऊपर भी उनकी सोच सराहनीय है और तथ्यों की ओर ही इशारा करता है। सर्वविदित है कि चीन द्वारा किए जा रहे इस विकास के पीछे उसकी विस्तारवादी विचारधारा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सैफुल्लाह मीर को यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 4-5 वर्षों में घाटी में भी विकास धीरे-धीरे ही सही होने लगा है। साथ ही पर्यटकों की बढ़ती संख्या भी एक सकारात्मक संकेत देती है। यह समय भाजपा से लड़ने का नहीं बल्कि साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर की प्रगति के लिए काम करने का है। राज्य का युवा बड़ी उम्मीद के साथ इन नेताओं की ओर देख रहा है। उसे भरोसा है कि रोजगार के नये अवसर मिलेंगे और वह भी मुख्यधारा के साथ जुड़ कर विकास के पथ पर चल सकेगा।

बाल गोविंद, नोएडा
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, कारखाने वाला, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
: समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्रा*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23362368, 23362369, 23362371, 23362372, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा ऐरा 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 201
भा.रा.मा.मी. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी सामग्री के लिए उत्तरदायी

## चिंतन

# महज एक परंपरा नहीं है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

पूरी दुनिया में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह महज एक परंपरा या औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज की उन्नति और विकास की सबसे अहम बुनियाद है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि नारी शक्ति के संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव है, लेकिन हम इस उत्सव को किस रूप में लेते हैं, ये हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। एक समय था जब महिलाओं को न तो शिक्षा का अधिकार था, न ही वोट देने का और न ही उन्हें पुरुषों से बराबरी करने का। इस असमानता के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई और 1908 में न्यूयॉर्क शहर में करीब 15,000 महिलाओं ने एक विशाल प्रदर्शन किया। वे कम वेतन, बेहतर काम करने की परिस्थितियां और वोटिंग के अधिकार की मांग कर रही थीं। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में पहला अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जर्मनी की समाजवादी नेता क्लारा जेटकिन ने यह प्रस्ताव रखा कि हर साल एक दिन महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। इस विचार को कई देशों ने अपनाया और 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब हालात वैसे नहीं हैं। महिलाएं बराबरी पर खड़ी हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया को नई रफ्तार दे रही हैं, लेकिन फिर भी लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद आज भी हमारे ही बीच ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महिला अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बीते दिनों ही महाराष्ट्र के जलगांव से आई भाजपा नेत्री की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की खबर न केवल हैरान करती है बल्कि महिलाओं की स्थिति पर सवाल भी खड़े करती है।देश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। ध्यान देने की बात है कि बेटी के साथ कथित छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने केंद्रीय मंत्री खुद थाने पहुंचीं। हालांकि उन्होंने कहा कि वह थाने में मंत्री या सांसद की हैसियत से नहीं बल्कि एक मां के रूप में आई हैं। लेकिन उन्होंने यह सवाल भी किया कि जब एक केंद्रीय मंत्री और सांसद की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम घरों की लड़कियों की क्या दशा होगी। ध्यान रहे यह इकलौती घटना नहीं है। हर दिनों समाचार पत्रों में ऐसी खबरों की भरमार रहती है। आनिवार्य है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, समाज की संवेदनशीलता का भी है। परिवार में लड़कों के पालन-पोषण के तौर-तरीकों का भी है। देश के कोने-कोने से ऐसी छेड़छाड़ की खबरें आती रहती हैं और उससे कहीं ज्यादा के बारे में तो पता भी नहीं चलता। ऐसे मामलों को रोकने के लिए कानूनी सख्ती के साथ घर के अंदर भी पहल करनी होगी। लड़कों को कम उम्र से ही बताना होगा कि लड़कियों-स्त्रियों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। उन्हें अपनी संस्कृति संस्कारों से जोड़ना होगा। हम उस देश के वासी हैं जहां महिला शक्ति को माता का दर्जा प्राप्त है। साल में दो बार नवरात्रें मनाकर महिला शक्ति को पूजते हैं। इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो हमें तुरंत सजग होना होगा। युवा पीढ़ी को भी सुसंस्कारी बनाना होगा, तभी महिलाओं को सही सम्मान मिल सकेगा।

महिला दिवस
प्रो. नीलिमा गुप्ता

महिला शिक्षा व सशक्तिकरण एक दूसरे से गहरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों, अवसरों और जिम्मेदारियों को समझ सकती हैं। शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानित और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। महिला शिक्षा व सशक्तिकरण की प्रक्रिया केवल महिलाओं के व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित महिला ही सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकती है, अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करती कर सकती है व पूरे परिवार और समाज को भी प्रगति की दिशा में ले जा सकती है।

# शैक्षिक सशक्तिकरण के अवसर मिले

एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी सहायक है। आज आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। शिक्षा को आत्मनिर्भरता की नींव कहा जा सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति या समाज को उचित शिक्षा मिलती है, तो वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करता है, बल्कि वह देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए आवश्यक है कि देश के नागरिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करें और उसे अपने जीवन में सही ढंग से लागू करें।

आज कौशल विकास के कई अवसर युवाओं के सामने हैं जिससे वे न केवल रोजगार पा सकते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। नई तकनीकों और नवाचारों का ज्ञान प्राप्त कर युवा भारत अपनी एक मजबूत और प्रतिस्पर्धात्मक ताकत बनने की क्षमता रखता है। शिक्षा नागरिकों को अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक तो करती ही है, साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण आयामों के प्रति भी नागरिक बोध भी कराती है। यह समाज में जाति, वर्ग, जेंडर विभेद को दूर करने का एक माध्यम भी है ताकि सभी नागरिकों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर सेवा का समान अवसर उपलब्ध हो सके। स्वावलंबन और नागरिक बोध से युक्त भारत की जनसंख्या न केवल उसकी शक्ति है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस महती संकल्पना को साकार में करने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए महिला शिक्षा के महत्व को समझना आवश्यक है। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण एक दूसरे से गहरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों, अवसरों और जिम्मेदारियों को समझ सकती हैं। महिला शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानित और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की प्रक्रिया केवल महिलाओं के व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित महिला ही सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकती है, अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करती कर सकती है तथा पूरे परिवार और समाज को भी प्रगति की दिशा में ले जा सकती है। महिलाओं का शिक्षित होना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना समाज में समानता की मुख्य कुंजी है। महिलाएं शिक्षा के माध्यम से न केवल रोजगार प्राप्त करती हैं बल्कि वे अपने परिवार की आर्थिक सुदृढ़ीकरण में योगदान करती हैं। इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होती है और उनकी आर्थिक रूप से निर्भरता समाप्त होती है। आर्थिक सक्षमता महिलाओं में निर्णय की क्षमता का विकास करती है और वही स्थिति उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होती है। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं स्वयं और परिवार के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने में सक्षम होती हैं। वे पोषण, स्वच्छता और देखभाल के महत्व को बेहतर समझती हैं। उनकी यह काबिलियत न केवल उनकी बल्कि पूरे परिवार और समाज की जीवनशैली में

सुधार करती है और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करती है। समाज में स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण तभी संभव है जब उस समाज की महिला सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को उनके अधिकारों, अवसरों और विकल्पों में पूरा समर्थन मिले, ताकि वे समाज में आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और समृद्ध जीवन जी सकें। यह उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। यह जरूरी है कि महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षा दी जाए, ताकि वे अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकें। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनके आत्मविश्वास से उनकी आवाज बुलंद हो और वे नीतियों में परिवर्तन ला सकें। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर लड़की को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। इसके लिए विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और छात्रवृत्तियां प्रदान करना जरूरी है। समाज को भी यह समझने की आवश्यकता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि समग्र समाज के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए समाज को भी अपनी मानसिकता में बदलाव लाने, भेदभाव को समाप्त कर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की पहल करनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की सुरक्षा भी अहम है। सरकार और समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं बिना किसी डर के अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रभावी कानून और नीतियां भी लाई गई हैं। महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देना, उनकी देखभाल भी सशक्तिकरण का एक आवश्यक पहलू है। एक स्वस्थ महिला ही सशक्त बनकर अपने परिवार और समाज का सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। इसके लिए हमें शैक्षणिक संस्थानों में भी छात्राओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समान स्तर पर लाना होगा। महिला शिक्षा के माध्यम से उन्हें समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना हम सबका कर्तव्य है। अगर हम एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र चाहते हैं तो हमें महिलाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण के सही अवसर प्रदान करने होंगे।

(लेखिका छत्रपति हर्षोदिप्त तौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) में कुलपति हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

## लैंगिक समानता
अर्चना कुमारी

# 'आधी आबादी' को पूरा हक मिलना चाहिए

भारत में महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। यूं तो यह आधी आबादी कभी शोषण तो कभी अत्याचार के मामलों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। हालांकि जब भी हम महिलाओं की समानता की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि किसी भी वर्ग में समानता के लिए सबसे पहले अवसरों की समानता का होना बेहद जरूरी है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि देश में आधी आबादी राजनीति में अभी भी हाशिये पर है। ये स्थिति तब है, जबकि जितनी भी महिलाओं को राजनीति के निचले पायदान से ऊपरी पायदान तक जितना भी और जब भी मौका मिला, उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमताओं का लोहा मनवाया है। ऐसे में यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि आजादी के 75 सालों में लैंगिक समानता की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियां आखिर गिनती की ही क्यों रह गई हैं? आखिर सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक असमानता क्यों बरकरार है? वह भी तब, जब हम इस वर्ग को 'आधी आबादी' का संबोधन देते हैं। यह बात सही है कि स्त्री शक्ति ने देश-दुनिया में समय-समय पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, लेकिन महिलाओं को कमतर होने का अहसास दिलाने की पुरुष वर्ग की मानसिकता आज भी स्त्रियों को उनके हकों से वंचित कर रही है। नारी सशक्तीकरण की बातें कागजी योजनाओं में काफी अच्छी लगती हैं पर धरातल पर अभी काफी कुछ होना बाकी है। खास तौर से आधी आबादी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बराबरी का हक देने को लेकर। यह विडम्बना ही है कि विधायिकाओं में 50 फीसदी नहीं, बल्कि महज 33 फीसदी आरक्षण की सालों से चल रही मांग आज तक अधूरी ही है। पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर आरक्षण से महिलाओं को मौका जरूर मिला लेकिन यहां भी कितना सशक्तीकरण नारी शक्ति का हो पाया है यह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वावलंबी, ऊंचे पदों पर बैठी महिलाओं के विपरीत लैंगिक भेदभाव की उस तस्वीर को भी देखना होगा जहां महिलाओं को यह तक पता नहीं कि कानून ने किन-किन क्षेत्रों में उनको कितना संरक्षित कर रखा है। वहीं संसद में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारत की मौजूदा जनसंख्या के अनुसार, लोकसभा में एक निर्वाचित सांसद औसतन 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं एक निर्वाचित महिला सांसद औसतन 92 लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व करतीं हैं। जाहिर है महिला अधिकारों और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दावों और उसकी वास्तविकता के मध्य एक गहरा विरोधाभास और राजनीतिक दलों का दोगलापन है।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि डॉ. आंबेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुंमुखी विकास नहीं कर सकता। उनका दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी, जब उन्हें घर-परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। लेकिन ये सच है कि पितृसत्तात्मक मानदंडों और परम्परागत मानसिकता के चलते ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं को हाशिए पर रखा गया। आजादी के बाद भारत के संविधान ने ये व्यवस्था दी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन भारत में अधिकांश विधानसभाओं में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व का परिदृश्य आज भी निराशाजनक है। वास्तव में भारत की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है।

वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की ओर से जारी रिपोर्ट में भारत का नाम 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे प्रमुख कारण अब तक समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे का मौजूद होना है। हमें इस बात को समझना होगा कि पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी न केवल न्याय और लोकतंत्र के लिए अहम है, बल्कि ये सुव्यवस्थित मानव अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है।जाहिर है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और प्रशासन से लेकर राजनीति तक बेटियों को अभी काफी अवसर और सुविधाएं देना बाकी है। यह काम सरकारों को भी करना है और समाज को भी।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

## जब मन अशांत हो, इष्टदेव के मंत्रों करे जप

संकलित
दर्शन

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं। ये सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

## सफलता के लिए योजना बनाकर काम करे

संकलित
प्रेरणा

जब भगवान विष्णु श्रीकृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे। देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी-वसुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। सातवीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए। भगवान विष्णु ने योगमाया से कहा था कि आप इस सातवीं संतान को देवकी के गर्भ से निकाल कर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सूचना दी जाएगी कि सातवां गर्भ गिर गया है। योगमाया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब आठवीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योगमाया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागर से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस आठवीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी, उसी के अनुसार श्रीकृष्ण का अवतार हो गया। इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी।

## अटुकल पोंगाला उत्सव

## आज की पाती

### प्रकृति स्वरूपा है नारी ब्रह्मांड का आधार है नारी

प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाईयां बहुत ही खौफनाक हैं। महिलाओं पर जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि नारी प्रकृति स्वरूपा है, नारी ब्रह्मांड का आधार है, नारी जलवा जननी है, न मजबूर व लाचारी इसे बेचारी। सजीवन एक खूबसूरत यात्रा है। इसी यात्रा में हम संघर्ष करते हुए सदैव अविजमान रहते हैं।

-नवदान खाजपेरी, भिलाई

## ट्रेंड

### तमिल में पाठ्यक्रम

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के ओ जल्द से जल्द तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए। इससे तमिल माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों को लाभ होगा।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

### विकास का दीप जलाएंगे

विपक्ष सरकारों ने दिल्ली के हर विभाग, हर व्यवस्था को इतना बदहाल कर दिया है। हमें एक जगा लगा हुआ सिस्टम विरासत में मिला है लेकिन हम अपनी बुलंद हौसलों और कर्तव्यनिष्ठा से दिन-रात काम करके दिल्ली के विकास का दीप जलाएंगे।

-रेखा गुप्ता, सीएम, दिल्ली

### महिलाओं को प्रोत्साहन

इस पहचान के लिए मैं बहुत आभारी हूं, मैं और अधिक महिलाओं को आगे आने और अपनी यात्रा की पटकथा लिखने में यथासंभव सहायता देने के लिए प्रोत्साहित करती हूं।

-किरण मजूमदार-शॉ, उद्यमी

### उम्र सिर्फ एक संख्या

जिस शख्स ने दिल्ली में 28 साल की उम्र में 65 साल के बुजुर्ग की भूमिका निभाई हो, और ज्यादातर अपनी उम्र से बड़े किरदारों के रोल किए हो, उसकी जवानी तो अब शुरू हुई है। उस विशिष्ठता संस्था है, मैं इसका आदर्श उदाहरण हूं।

-अनुपम खेर, अभिनेता

## करंट अफेयर

# ट्रंप ने सुनीता विलियम्स के घने बालों की प्रशंसा की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के घने बालों की सराहना की और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे दो अंतरिक्ष यात्रियों को संदेश दिया कि उन्हें जल्द धरती पर वापस लाया जाएगा। ट्रंप (78) ने अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे बुच विल्मोर और विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लाने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक बचाव दल को कक्षा में भेजने की संभावना का जिक्र किया और आठ दिन के मिशन के नौ महीने तक जारी रहने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की आलोचना की। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, 'बाइडन ने उन्हें वहीं फंसा छोड़ दिया।' उन्होंने कहा, 'हमारे दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। मैंने एलन (मस्क) से कहा, 'मेरा एक काम करो। क्या तुम उन्हें बाहर निकाल कर ला सकते हो? उन्होंने कहा 'हां'। वह वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दो सप्ताह में। ट्रंप ने कहा कि मस्क अभी एक यान तैयार कर रहे हैं जो ऊपर जाएगा और उन्हें वहां से ले जाएगा।

## ऑफ बीट

# पुराना पीठ दर्द मस्तिष्क से होता है उत्पन्न

पुराने पीठ दर्द से पीड़ित अधिकांश लोग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि उनका दर्द चोट या शरीर में अन्य समस्याओं जैसे गठिया या उभरी हुई डिस्क के कारण होता है। लेकिन हमारी शोध टीम ने पाया है कि मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया के रूप में दर्द के मूल कारण के बारे में सोचने से रिकवरी को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हम दर्द पुनर्संसाधन थेरेपी नामक एक मनोवैज्ञानिक उपचार का अध्ययन कर रहे हैं जो मस्तिष्क में अप्रभावी और अनावश्यक दर्द संकेतों को 'बंद' करने में मदद कर सकता है। पुराने समय से चला आ रहा दर्द आज सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह अमेरिका में विकलांगता का प्रमुख कारण है, और इसकी आर्थिक लागत मधुमेह या कैंसर से भी अधिक है। सबसे आम दीर्घकालिक दर्द पीठ दर्द है। कई मरीज - और डॉक्टर - पीठ की विभिन्न समस्याओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें संदेह है कि यह दर्द का कारण हो सकता है। इसलिए वे हर तरह के उपचार आजमाते हैं, लेकिन अक्सर कोई फायदा नहीं होता।

## अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हरिभूमि विशेष

कविता जोशी.नई दिल्ली। न रहने के लिए घर, न खाने के लिए दो वक्त की पूरी रोटी, न पहनने-ओढ़ने के लिए बराबर कपड़े। लेकिन इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद मां को देखकर मिला एक हौसला ही था कि जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर करना है जो बाकी के लिए मिसाल बन जाए। इन चंद पंक्तियों में छिपी है एक साधारण सी साइकिल से कई बार अकेले भारत भ्रमण कर चुकी देश की जानी-मानी एकल साइक्लिस्ट मध्य-प्रदेश की रहने वाली 26 वर्षीय आशा मालवीय के जीवन की पूरी कहानी। जो आज न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों महिलाओं को अपने घर की चारदीवारी लांघकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही हैं। 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2025' पर हरिभूमि ने आशा से फोन पर खास बातचीत की और उनकी मुश्किल साइकिल यात्राओं, जीवन के संघर्षों से सीखे अनुभवों से लेकर महिलाओं के लिए दिए प्रेरणादायक संदेश को जाना। पेश है बातचीत के अंश-

# साइकिल से कन्याकुमारी से सियाचिन पहुंची 'आशा' बनी करोड़ों महिलाओं की 'आशा'

'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2025' पर हरिभूमि से खास बातचीत की साइकिल से भारत भ्रमण कर चुकी जानी-मानी साइक्लिस्ट आशा मालवीय ने

### आपका शुरुआती जीवन कैसा था?

मैं मध्य-प्रदेश के राजगढ़ जिले के नाटाराम गांव की रहने वाली हूं। मेरे परिवार में मेरी मां और एक छोटी बहन है। जीवन की शुरुआत ही परेशानियों से हुई, मैं दो या तीन साल की रही होंगी तभी मेरे पिता का देहांत हो गया। परिवार में मैं, मेरी मां और एक बहन थे। रहने के लिए एक झोपड़ी, घर नहीं जिसे चारों तरफ से पॉलीथिन से ढका गया था। मेरी मां हम दोनों बहनों को पालने के लिए मजदूरी करती थी। उनके पास पहनने के लिए पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन किसी तरह से मजदूरी कर जो पैसा मिलता। उससे ही गुजारा होता। मुझे आज भी याद है कि कभी हम एक वक्त के खाने का जुगाड़ गांव में किसी से मांग कर करते थे तो कभी खाने को कुछ नहीं मिलता था।

### अपने जीवन में किससे प्रेरणा मिली?

मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी मां हैं। उन्होंने ही मुझे पाल-पोसकर इतना बड़ा किया है। मां को देखकर लगता था कि अगर उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी तो मैं क्यूं मानू। हमें अपने जीवन में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे हर निर्णय के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे, दूसरा कोई नहीं। जब भी कोई काम करे तो सबसे पहले अपने मन की सुनें, दुविधा में कोई काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब मैं अकेले साइकिल से भारत भ्रमण पर निकल रही थी तो मुझे पता था कि ये निर्णय मेरा है और इसे पूरा भी मुझे ही करना होगा। एक बार कोई मुश्किल काम हाथ में लेने के बाद जब वो पूरा होता है तो उसका अपना ही मजा होता है।

### इतनी चुनौतियों के बाद पढ़ाई कैसे पूरी की?

पांचवीं कक्षा तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते वक्त मेरी मां के एक परिचित ने हमें कुछ मदद दी। मैं पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए जो मदद मिली वो बहुत का काम कर गई। दसवीं में पहुंची तो पढ़ाई के साथ थोड़ा-बहुत नौकरी करना शुरू किया। मेरे स्कूल के पास बाइक का कुछ काम होता था, वो किया। फिर एक प्राइवेट नौकरी के साथ-साथ स्नातक और परास्नातक की डिग्री ले ली है।

### सबसे ज्यादा चुनौती कहां आई?

कुल 17 हजार 500 किमी. की मेरी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण चरण लेह-लद्दाख में देखने को मिला। जहां मैंने खारदुंगला, बारालाचा और उमिंगला जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित कुल 11 दर्रों को पार किया। इन जगहों पर ऑक्सीजन की काफी कमी थी, मेरी साइकिल नॉर्मल थी, कई बार टूटी, मैं गिरी भी लेकिन फिर जैसे-तैसे मैंने साइकिल खुद से ठीक की। कभी इतनी दिक्कत होती थी, रास्ता इतना मुश्किल होता कि उसमें साइकिल चल ही नहीं पाती थी तब मैं अपनी साइकिल हाथ से उठाकर ही आगे बढ़ती थी। शुरुआत में मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन बाद में मुझे सेना की मदद मिली, मेरी यात्रा के पड़ाव में रुकने के लिए उन्होंने सहायता की। यात्रा में मैं दिन रात दोनों समय साइकिल चलाती हूं।

### देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?

साइकिल चलाना सिर्फ मेरी रुचि नहीं बल्कि इससे मैं अपने देश, दुनिया की महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूं। क्योंकि आज भी महिलाएं ये सोचती हैं कि उन्हें घर से बाहर जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत है। वो अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, सुरक्षा को लेकर खतरा है। मुझे इसी सोच को बदलना था कि महिलाएं ये नहीं कर सकतीं, वो नहीं कर सकतीं। मैं अपने संदेश में यही कहूंगी कि जिंदगी में जो भी करें, पूरे विश्वास से करें, अपने मन की आवाज को सुनें, सफलता जरूर मिलेगी। रही बात साइकिल से देश घूमने की तो इससे जितना स्वास्थ्य को फायदा होता है, उतना गाड़ियों से संभव नहीं है। साइकिल चलाकर हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट रहते हैं।

### यात्रा में कैसा दिखा अपना देश?

यात्रा में मैंने सबसे ज्यादा मौसम के बदलाव महसूस किए हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती भी रहे। जब मैंने पिछले साल जून में कन्याकुमारी से सियाचिन तक अपनी साइकिल यात्रा शुरू की तो कन्याकुमारी में मौसम बिलकुल अलग था, उससे आगे बढ़ने पर कुछ और फिर अंत में लेह, लद्दाख और सियाचिन आते-आते पूरा नजारा ही बदल गया। उसने मेरी भारत को देखने की पूरी सोच ही बदल दी। आज जब मैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अपना संदेश देती हूं तो उसमें भी कहती हूं कि पहले जैसे कहते थे भारत मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेकिन अब इसे कहिए कन्याकुमारी से सियाचिन तक। नॉट ओनली कश्मीर तक उससे आगे भी हमारा भारत है।

# देश की 50 फीसदी महिलाओं की मेंटल हेल्थ खराब वर्क-लाइफ बैलेंस, आर्थिक दबाव बिगाड़ रहे सेहत

नई दिल्ली। आज के समय में खराब मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या बन गया है। महिलाएं भी इसका शिकार हो रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में आत्महत्या करने वालों में 36.6% महिलाएं हैं, जिनमें 18-39 वर्ष की युवतियां सबसे अधिक हैं। इसके बावजूद, समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फैले डर और कलंक के कारण महिलाएं इलाज कराने से बच रही हैं। एक सर्वे में खुलासा हुआ कि महिलाएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर खुलकर बात करने से डरती हैं, ताकि कॅरियर पर असर न पड़े। इसके अलावा यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और वर्क-लाइफ बैलेंस के कारण भी महिलाओं की मानसिक सेहत बिगड़ रही है।अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की एमपावर संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट देशभर की 13 लाख महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य आंकड़ों पर आधारित है। इसमें कॉलेज छात्राओं, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स, ग्रामीण महिलाओं और सेना में कार्यरत महिलाओं की मानसिक चुनौतियों के बारे में बताया गया है।

### कॉरपोरेट जगत में कामकाजी महिलाएं

42% महिलाओं में डिप्रेशन और एंग्जायटी के लक्षण पाए गए। 80% महिलाएं मातृत्व अवकाश और कॅरियर बोध में भेदभाव झेलती हैं। 90% महिलाओं का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उनके कार्य प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार के साथ फ्रेजेक्ट संचेतना के तहत 12.8 लाख ग्रामीण महिलाओं पर किए गए सर्वे में सामने आया कि वित्तीय अस्थिरता, सामाजिक कलंक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण वे गंभीर अवसाद और चिंता से जूझ रही हैं।

### दवाओं से ठीक हो सकती है ये बीमारी

मनोचिकित्सक डॉ. अंकिता गौतम ने कहा कि अक्सर महिलाओं को अवसाद, चिंता, अनिद्रा, व्यक्तित्व विकार, संबंधों की चुनौतियां और वैवाहिक असहमति एक गंभीर चुनौती है। डॉ. गौतम के आने कहा कि मनोचिकित्सीय विकारों को दवाओं, मनोचिकित्सा या दोनों के संयोजन से प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है, यह व्यक्ति की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। लगातार मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के सबसे आम ट्रिगर्स में से एक है।

18-35 वर्ष की उम्र की लड़कियों की मानसिक स्वास्थ्य प्रवृत्तियां कुछ इस तरह से हैं

मुंबई- एकेडमिक स्ट्रेस और कॉरपोरेट बर्नआउट सबसे अधिक है। दिल्ली- सुरक्षा चिंताओं और उत्पीड़न के कारण पॅटीएसडी और एंग्जायटी की समस्या अधिक है। कोलकाता- मजबूत सामाजिक नेटवर्क के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से महिलाएं कोसों दूर हैं।

### अच्छी नींद और योग का भी अहम रोल

हर सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं आज तनाव का शिकार हो रही हैं। वह मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। महिलाओं को योग, नियमित शारीरिक गतिविधि, ध्यान, संतुलित आहार, सुपुष्टकारपूर्ण नींद और मजबूत सामाजिक समर्थन की जरूरत है। इसके अलावा जो महिलाएं तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की समस्या से जूझ रही हैं। उन्हें समय-समय पर मनोचिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता है।

# चांद पर मौजूद है बर्फ का जखीरा?

## लैंडिंग के डेढ़ साल बाद इसरो के चंद्रयान-3 ने दुनिया को चौंकाया

नई दिल्ली। चंद्रयान-3 से मिले डाटा की रिसर्च से पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों में पहले के अंदाज़े के मुताबिक ज्यादा बर्फ हो सकती है। अहमदाबाद के वैज्ञानिक दुर्गा प्रसाद करनम के मुताबिक चांद की सतह पर तापमान में बड़ा बदलाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इन बर्फ के कणों की रिसर्च करने से यह समझने में मदद मिलेगी कि वे कैसे बने और कहां से आए। यह रिसर्च 'कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट' नाम की पत्रिका में छपी है। भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के रहने और खोज करने के लिए बर्फ बहुत जरूरी संसाधन होगा।

### कैसा है चांद का तापमान?

चंद्रयान-3 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था। इस जगह को बाद में 'शिव शक्ति पॉइंट' नाम दिया गया। यह जगह लगभग 69 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। यहां दिन में तापमान 82 डिग्री सेल्सियस तक और रात में -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां, लैंडिंग वाली जगह के पास की एक सपाट जगह का तापमान दिन में 60 डिग्री सेल्सियस था। तापमान का यह अंतर नासा के आर्टेमिस मिशन के संभावित स्थलों से मेल खाता है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर पर एक खास उपकरण 'चास्टे' लगाया गया था, जिसने सतह और 10 सेंटीमीटर नीचे तक का तापमान मापा।

### सीधे भाप में बदल जाता है बर्फ

जब बर्फ को पानी में बदलने की जरूरत के बारे में पूछा गया, तो करनम ने बताया कि चांद की सतह पर बहुत कम दबाव होता है, जिससे पानी तरल रूप में नहीं रह सकता। इसलिए, बर्फ पिघलकर पानी नहीं बनेगी, बल्कि सीधे भाप में बदल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक की जानकारी के मुताबिक चांद पर कभी जीवन के मुताबिक परिस्थितियां नहीं थीं।

# एलन मस्क को फिर लगा झटका

स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट गोंच के बाद फटा, आसमान में दिखा मलबा

वॉशिंगटन। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को एक बार फिर झटका लगा है। गुरुवार को स्पेसएक्स ने लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही अंतरिक्ष में अपने स्टारशिप रॉकेट से संपर्क खो दिया। इसके बाद रॉकेट आसमान में फट गया और ये मलबे में तब्दील हो गया। इस मिशन की लाइव स्ट्रीम में अंतरिक्ष में स्टारशिप के टूटने के बाद दक्षिण फ्लोरिडा और बहामास के पास आसमान में आग के मलबे की लकीरें दिखाई दीं, जो इसके इंजन कटऑफ के साथ अनियंत्रित रूप से घूमने के तुरंत बाद हुआ।

### नासा रख रहा था नजर

इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में कुछ नकली सैटेलाइट्स को छोड़ना और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटना था, जिसमें यह असफल रहा। नासा भी इस मिशन पर बारीकी से नजर रख रहा था।

### स्पेसएक्स ने जारी किया बयान

स्पेसएक्स ने इस मिशन में असफलता के बाद अपने बयान में कहा, 'स्टारशिप के ऊपर जाने के दौरान इसमें अविनियोजित रूप से खोजें हुई और संपर्क टूट गया। हम इसके मूल कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस परीक्षण के डेटा की समीक्षा करेंगे। हालांकि हमेशा की तरह ही आज की उड़ान भी हमें स्टारशिप की विश्वसनीयता में सुधार के लिए अतिरिक्त सबक प्रदान करेगी।'

### दो महीने में मिली दूसरी नाकामयाबी

स्टारशिप की करीब दो महीने में यह दूसरी नाकामयाबी मिली है। इसे पहले जनवरी में भी कंपनी का लॉन्च असफल होकर रॉकेट का जलता हुआ मलबा टर्क्स और कैकोस द्वीप पर बरसा गया था। स्पेसएक्स ने गुरुवार को विशाल स्टारलिंक रॉकेट को नकली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए परीक्षण उड़ान पर लॉन्च किया था। 123 मीटर लंबा रॉकेट टेक्सास से उड़ा। जब यह धूर हिंद महासागर के ऊपर बढ़ रहा था तो इसका चालक दल से संपर्क टूट गया।

## सम्पादकीय

# गरीब मुस्लिमों के हित में है वक्फ बिल मुस्लिम महिलाओं-पसमांदा वर्ग के लोगों की बेहतरी की राह खुलेगी

हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जगदंबिका पाल के नेतृत्व वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के सभी 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी। इसके बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड में व्याप्त अनियमितताओं एवं विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1995 के कुछ प्रविधानों को हटाने की बात करता है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में सुधार होगा। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण पाना, वक्फ संपत्तियों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग हितधारक समुदाय के लाभ के लिए ही किया जा सके। सरकार के इन प्रयासों के बावजूद विपक्ष एवं उलेमाओं का एक वर्ग और तथाकथित सेक्युलर-लिबरल बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने तो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने का एलान किया है। इस विधेयक का विरोध करने वालों के अपने कुछ तर्क हैं और आशंकाएं भी। वे इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सरकार का हस्तक्षेप मानते हैं।

उनका मानना है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है। इस विधेयक के संदर्भ में सत्तापक्ष और विपक्ष के तो अपने-अपने तर्क हैं ही, जिस मुस्लिम समुदाय के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उसके भीतर भी इस विधेयक को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मुस्लिम समाज को एक समतावादी समाज माना जाता है, लेकिन व्यवहार में भारतीय मुस्लिम समाज में भी भेद और स्तरीकरण दिखाई देता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था का अस्तित्व है। इसमें तीन प्रमुख श्रेणियां देखी जाती हैं। अशराफ उच्च वर्ग के मुसलमान माने जाते हैं, जिनका दावा है कि वे अरबी, तुर्की, फारसी या अफगान वंश से संबंधित हैं। अशराफ में सैयद, शेख, पठान और मुगल जैसी उच्च जातियां आती हैं। अजलाफ निम्न वर्ग के मुसलमान माने जाते हैं, जिनका संबंध परिवर्तित हिंदुओं से है। इस श्रेणी में कारीगर, किसान और श्रमिक वर्ग के मुसलमान शामिल होते हैं। अरजाल सबसे निचली श्रेणी के मुसलमान माने जाते हैं, जो मुख्यतः दलित जातियों से मतांतरित हुए हैं। इन्हें समाज में सबसे अंतिम पायदान पर रखा जाता है। नीचे के इन दो मुस्लिम वर्गों को मिलाकर पसमांदा मुस्लिम समूह की रचना होती है। पसमांदा मुस्लिम एक सामाजिक-आर्थिक और जातिगत श्रेणी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को संदर्भित करती है। 'पसमांदा' शब्द का अर्थ है पीछे छूट गए: या त्यक्तिः। यह उन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

अधिकतर पसमांदा मुस्लिम अधिकार कार्यकर्ता वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। हैरानी नहीं कि उनकी नजर में वक्फ संशोधन बिल से वक्फ की संपत्तियों के पंजीकरण, सत्यापन, लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और गरीब मुसलमानों को वक्फ के विवादों से मुक्ति मिलेगी। प्रायः मुसलमानों की हर संस्था पर अशराफ वर्ग यानी खुद को विदेशी मूल का मुसलमान कहने वालों का कब्जा है। वे यह नहीं देख पा रहे हैं कि संशोधित वक्फ बिल के प्रस्तावों में महिलाओं के साथ-साथ पसमांदा वर्ग के पिछड़े मुसलमानों के लिए भी ऐसे अहम प्रविधान किए गए हैं, जिनसे महिलाओं-पसमांदा वर्ग के लोगों की बेहतरी की राह खुलेगी।

## आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधियां लगाते जो पूरा करोगे। कल आप एक लक्ष्य पाने में सफल होते हैं कि आपके जीवन के लिये सौभाग्य होगा है, तभी आपके लिये कुछ होगी और पुरानी दशा, अच्छी दिन बनी से सहायक रहेगा। पहेलियाँ हल न किये तभी हमारे सहयोग में और अधिक मुद्दों को सुलझाने वाला सहायतापूर्ण अन्य को समझ होगे, विशेष परिस्थितियों वालों के लिये, तभी एक सहायतापूर्ण तभी लाभ और बाधाओं में लाभ प्रदान करेगा

**मेष**
आज का दिन शुभ फलदायी है। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से आज आप वैचारिक स्थिरता का अनुभव करेंगे। इसके परिणामस्वरूप आप लगन के साथ काम कर पाएंगे।

**वृष**
व्यापार के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा बढ़ सकती है। पदोन्नति की संभावना है। पिता की संपत्ति से लाभ होगा। कला एवं खेल-कूद में निपुण व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका मिलेगा। सरकार के साथ धन का व्यवहार सफल रहेगा।

**मिथुन**
दुर्घटना में संभलना अनिवार्य है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा। मानसिक चिंता के कारण मन व्यग्र रहेगा। अनुचित कार्यों में शक्ति का व्यय होगा। आध्यात्मिकता और ईश्वरीय शक्ति आपकी सहायक सिद्ध होगी।

**कर्क**
ईश्वर की आराधना एवं आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान कर सकती है। आज आप दैनिक कामों से दूर आनंद-प्रमोद में खोए रह सकते हैं। किसी मनोरंजन स्थल या पर्यटन स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। संतान और जीवनसाथी से सुख मिलेगा।

**सिंह**
समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। मित्रों और स्वजनों के साथ घूमना-फिरना आनंददायक हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय गुजरेगा। आज आपके लिए आर्थिक लाभ का दिन है। घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा।

**कन्या**
आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है। किसी अन्य तरीके से भी आर्थिक लाभ होगा। मित्रों के साथ मुलाकात हो सकती है। व्यापार में लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।

**तुला**
आज आप खर्च में संयम बनाए रखें। धन संबंधी एवं लेन-देन संबंधी सभी कामों में सावधानी रखने की जरूरत है। किसी के साथ विवाद न हो, इसका ध्यान रखें। मित्रों एवं परिवारजनों के साथ मनमुटाव होने की आशंका बनी रहेगी।

**वृश्चिक**
चिंता से मुक्ति का अनुभव करेंगे। मित्रों के साथ किसी प्रकृतिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। आज का दिन भोजन सुख के लिए अच्छा है। आपके दृढ़ मनोबल और भरपूर आत्मविश्वास से हर काम सफलतापूर्वक संपन्न होंगे।

**धनु**
शारीरिक कष्ट, विशेषकर आंखों में पीड़ा होने की आशंका रहेगी। परिजनों और स्नेहियों के साथ किसी घटना की संभावना है। आपकी बात-चीत या व्यवहार से किसी को कोई भ्रम न हो इसका ध्यान रखें। आज कोई भी काम बिना विचारे नहीं करें।

**मकर**
जमीन जायदाद के काम में सावधानी रखें। आज आप का दिन बहुत शुभ है। धार्मिक कार्य एवं यात्रा के लिए समय अनुकूल है। मित्रों एवं सम्बंधियों से हुई मुलाकात के कारण आनंद होगा। मित्रों से लाभ होगा।

**कुंभ**
अपने उत्तदायित्व अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आर्थिक योजना बना सकेंगे। आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे खर्च होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा। आप के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

**मीन**
विदेश जाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा। स्नेहीजनों के समाचार मिलने से आनंद होगा। भाई-बहनों से आर्थिक रूप से लाभ होगा। आप की वाणी पर संयम रखें। नियम विरुद्ध काम ना करें। नए संबंधों से नुकसान हो सकता है।

## आज का इतिहास | बढ़ता राजस्थान

### 8 मार्च की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय की मौत के बाद 1702 में महारानी ऐनी ने सत्ता संभाली।
- ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने महिलाओं के मताधिकार से संबंधित विधेयक को 1907 में ठुकरा दिया।
- काम के लिए बेहतर वेतन, कम घंटे और वोट देने का अधिकार को लेकर 1908 में न्यूयॉर्क में कई महिलाओं ने एक रैली में हिस्सा लिया।
- अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने 1909 में पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था।
- कोपनहेगेन (डेनमार्क) में 1910 में हुए महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तय करने का प्रस्ताव रखा।
- यूरोप में 1911 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
- स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 1921 में पार्लियामेंट से बाहर निकलते वक्त राष्ट्रपति एडवर्डो दातो की हत्या।
- महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया।
- द्वितीय विश्व शुद्ध के दौरान 1942 में जापानी सेना ने वर्मा के रंगून पर कब्जा किया।
- एअर इंडिया इंटरनेशनल की 1948 में स्थापना।
- इराक के गवर्निंग काउंसिल द्वारा एक नए संविधान पर 2004 में हस्ताक्षर किए गए।
- रूस ने ईरान मामले पर अपना प्रस्ताव 2006 में वापस लिया।
- फ्रिल्म फ्रेयर आफ फुटपाथ ने 2008 में काहिरा इंटरनेशनल फ़ेस्टीवल फ़ॉर चिल्ड्रेन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- भारत के अझणी गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा ने 2009 में थाइलैंड ओपन खिताब जीता।
- उत्तर कोरिया ने 2013 में दक्षिण कोरिया के साथ सभी शांति समझौतों को समाप्त कर दिया।

### 8 मार्च को जन्मे व्यक्ति

- 'गाँधी स्मारक निधि' के प्रथम अध्यक्ष, गाँधीवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चन्द भार्गव का 1889 में जन्म।
- प्रसिद्ध मराठी लेखक हरी नारायण आप्टे का 1864 में जन्म।
- भारतीय राजनीतिज्ञ और ब्रिटिश भारत के उड़ीसा प्रान्त के मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास का 1889 में जन्म।
- भारतीय कलाकार दामेर्ल रामाराव का 1897 में जन्म।
- प्रसिद्ध फिल्म गीतकार साहिर लुधियानवी का 1921 में जन्म हुआ।
- राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का 1953 में जन्म।
- भारतीय अभिनेता फरदीन खान का 1975 में जन्म हुआ।
- भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर का 1989 में जन्म हुआ।
- भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दस सर्वश्रेष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ियों में से एक जिम्मी जॉर्ज का 1955 में जन्म।

# महिला दिवस : कुछ कर गुजरने की जिद्द ही प्रेरणा स्त्रोत बनती है वेदों से लेकर आधुनिक काल तक नारी मानव जीवन की प्रेरणा स्रोत

विवेक वैष्णव

**भारतीय सनातन संस्कृति एक सम्पन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध है जहां महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है। सनातन संस्कृति में महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि महिलाओं को शिक्षा, यज्ञ, ज्ञान, आध्यात्म आदि क्षेत्रों में स्वतंत्रता और समानता मिली थी। वेदों से लेकर आधुनिक काल तक नारी को मानव जीवन की प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा गया है। भारतीय समाज में नारी को देवी, शक्ति, लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। यहां महिला और पुरूष के बीच समानता की नहीं बल्कि अर्धनारीश्वर की संकल्पना के साथ स्त्री और पुरूष को एक दूसरे के पूरक होने की बात की जाती है।**

आज महिलाएं धरती से लेकर चांद तक का सफर तय कर चुकी हो लेकिन आज भी समाज में समानता के लिए उन्हे कही ना कही संघर्ष करना ही पड़ता है। समाज को तब तक विकसित नही किया जा सकता है जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में स्वतंत्र और सशक्त न हो जाए। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों को बनाए रखना, चुनौतियों को पहचानना और उनके अधिकारों और लैंगिक समानताओं पर ध्यान केन्द्रित करना है। महिला दिवस महज एक दिवस का उत्सव नही बल्कि महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक कदम है। वर्ष 2025 की थीम ''कारंवाई में तेजी लाना'' का उद्देश्य लैंगिग समानता प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में प्रगति में तेजी लाना है।

पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को अमेरीका की सोशलिस्ट पार्टी ने मनाया था। इसके बाद 1910 में इसे वैश्विक मान्यता तब मिली जब जर्मन समाजवादी नेता क्लारा जेटकिन ने 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा। पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 19 मार्च 1911 में जर्मनी, आस्ट्रिया, डेनमार्क व स्विटजरलैण्ड में मनाया गया। यह दिन भी इसलिए चुना गया क्योंकि 1848 में इसी दिन परशिया के राजा ने महिलाओं के लिए वोट शुरू करने का वादा किया था लेकिन इसे पूरा करने में वे विफल रहे थे। वर्ष 1857 में 8 मार्च को ही महिला कपड़ा श्रमिकों के एक समूह ने अनुचित कार्य स्थितियों और असमान अधिकारों के विरोध में मार्च निकाला था। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की चिंताओं पर वैश्विक ध्यान आकर्शित करने के लिए 1975 में आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा करते हुए मैक्सिको सिटी में पहला सम्मेलन आयोजित किया था। 8 मार्च को रूस के पेत्रोग्राद में महिलाओं ने प्रदर्शन किया था तथा इस प्रदर्शन ने रूसी क्रांति को महत्वपूर्ण दिशा दी थी। इस प्रदर्शन को याद करने के लिए 8 मार्च को चुना गया। यह प्रदर्शन जूलियन कैलेण्डर में 23 फरवरी को हुआ था जो कि पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेण्डर में 8 मार्च को हुआ था। भारत वो भूमि है जहां प्रभु श्री राम ने भी सीता माता की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ उनकी मूर्ति के साथ किया था। भारतीय संस्कृति में भगवान श्रीकृष्ण को नन्दलाल कहा जाता हैं तो देवकी नंदन और यशोदा नन्दन भी कहा जाता हैं। भगवान श्रीराम दशरथ नन्दन हैं तो कौशल्या नन्दन और सियावर भी हैं। अनादि काल से ही महिलाएं मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले तक महिलाओं ने समाज में बदलाव के बड़े उदाहरण स्थापित किए हैं। भारतीय इतिहास महिलाओं की उपलब्धि से भरा पड़ा है। आनंदीबाई गोपालराव जोशी (1865-1887) पहली भारतीय महिला चिकित्सक थीं और संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी चिकित्सा में दो साल की डिग्री के साथ स्नातक होने वाली पहली महिला चिकित्सक रही है। सरोजिनी नायडू ने साहित्य जगत में अपनी छाप छोड़ी। हरियाणा की संतोष यादव ने दो बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। वॉक्सर एमरी मैरी कॉम एक जाना पहचाना नाम है। हाल के वर्षों में हमने कई महिलाओं को भारत में शीर्ष पदों पर और बड़े संस्थानों का प्रबंधन करते हुए भी देखा है। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष, अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी, सोमा मंडल सेल अध्यक्ष आदि नामचीन महिलाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राधिका पई ने 2011 में दैनिक उपयोगिता वस्तुओं की मार्केटिंग के लिए शॉपक्लूज नामक ऑन लाईन स्टार्टअप शुरू यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी बनी। राजोशी घोष के हसुरा, स्मिता देवराज के लीड स्कूल, दिव्या गोकुलनाथ के बायजू जैसे यूनिकॉर्न हैं जो महिला स्टार्टअप की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बयां करते है। महिला ई-हाट, स्टार्टअप स्कीम, पोषण अभियान, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कदम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए केन्द्र की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह भी वर्तमान सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज महिलाएं भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों में लड़ाकू जहाज उड़ाने, युद्धपोत चलाने से लेकर तोप चलाने में भी अपना योगदान दे रही हैं। आज भी विश्व परिदृश्य के साथ ही भारत दृष्टिकोण में भी महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त करने की दिशा में सरकारों की विभिन्न प्रयास करने पड़ रहे हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हमें भारत की संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए वर्षों का संघर्ष करना पड़ा। विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों के अनुसार प्रगति की वर्तमान दर से पूर्ण लैंगिग समानता तक पहुंचने में 2158 तक का समय लगेगा।

# त्रिभाषा फार्मूला को राजनीतिक अखाड़ा बनाने के पीछे किसका स्वार्थ है?

रामस्वरूप रावतसरे

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और त्रिभाषा फार्मूला एक बार फिर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से ही केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को रोकना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य को 2,152 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस पैसे की जरूरत है। स्टालिन ने केंद्र सरकार से जल्द ही पैसे रिलीज करने की मांग भी की थी।**

बीते दिनों मुख्यमंत्री स्टालिन ने श्रमैद्र प्रधान के एक बयान की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें प्रधान यह कहते हुए दिख रहे थे कि तमिलनाडु को भारतीय संविधान की शर्तों को मानना ??होगा और तीन भाषा नीति ही कानून का शासन है। जब तक तमिलनाडु एनईपी और तीन भाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक प्रदेश को समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। मीडिया के अनुसार, स्टालिन ने यह भी कहा है कि हिंदी सिर्फ मुखौटा है और केंद्र सरकार की असली मंशा संस्कृत थोपने की है। उन्होंने कहा कि हिंदी के कारण उत्तर भारत में अवधी, बृज जैसी कई बोलियां खत्म हो गईं। राजस्थान का उदाहरण देते हुए स्टालिन ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार वहां उर्दू को हटाकर संस्कृत थोपने की कोशिश कर रही है। अन्य राज्यों में भी ऐसा होगा इसलिए तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। दरअसल यह विवाद लगभग एक सदी से चला आ रहा है. जानते हैं इसकी जड़ कहां है? तीन भाषा की नीति हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषा से जुड़ी है। पूरे देश में हिंदी भाषा में पढ़ाई करवाना, एक पुरानी चली आ रही व्यवस्था का ही हिस्सा था। सबसे पहले साल 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। त्रिभाषा सूत्र की चर्चा आजादी के कुछ समय बाद ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा से जुड़े सुझावों को लेकर बनाए गए राधाकृष्णन आयोग (1948-49) की रिपोर्ट से ही शुरू हो गई थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि प्रादेशिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। इसके बाद साल 1955 में डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना। इस आयोग ने राज्य की अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी की पढ़ाई का द्विभाषा सूत्र दिया और अंग्रेजी या किसी और एक भाषा को वैकल्पिक भाषा बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद कोठारी आयोग बना. उसकी सिफारिश पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन ये समाधान या सिफारिश दक्षिणी राज्यों में धरातल पर नहीं लाई जा सकी। एनईपी 2020 ने तीन-भाषा फॉर्मूले को बरकरार रखा है, जिसे पहली बार 1968 के एनईपी में पेश किया गया था। हालांकि, इन दोनों में एक मुख्य अंतर यह है कि उस समय एनईपी ने हिंदी को पूरे देश में एक अनिवार्य भाषा बनाने की वकालत की थी। इसके उलट एनईपी 2020 को अधिक लचीलापन बनाया गया, जो तकनीकी रूप से किसी भी राज्य पर कोई विशिष्ट भाषा नहीं थोपती है। इसमें कहा गया है कि बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होंगी। हालांकि, इन तीन में से कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। इसका मतलब है, राज्य की भाषा के अलावा, बच्चों को कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी होगी-लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हिंदी ही हो। 2020 की शिक्षा नीति द्विभाषी शिक्षण पर भी जोर देती है, जिसमें घरेलू भाषा/मातृभाषा और अंग्रेजी शामिल हैं।

## शख्सियत | बढ़ता राजस्थान

श्री हितेश गैरा
( डायरेक्टर आर्शिवाद गार्डन )

नमस्कार साथियो हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं हितेश गेरा जोकि आशीर्वाद गार्डन के डायरेक्टर है । दोस्तो हितेश का अर्थ होता है दूसरों की भलाई सोचने वाला और ये शख्सियत अपने नाम के अर्थ को पूर्णतः सार्थक करती है जैसा नाम वैसा ही काम हमेशा दूसरों की भलाई सोचना और मदद के लिए तत्पर रहने जैसा स्वभाव है हमेशा हंसमुख चेहरा और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास ही इनकी पहचान है। इनका जन्म 11 नवंबर 1979 को अलवर में हुआ। प्राथमिक शिक्षा बडोडामेव सरकारी विद्यालय में हुई उसके बाद 12 अलवर में रीनी स्कूल से किया । इसके बाद सन 2002 में डी फार्मा डीग से किया साथ साथ मे ग्रेजुएशन भी पूरी की उसके बाद 2004 में जयपुर के प्राइवेट कॉलेज से होटल में मैनेजमेंट का कोर्स किया। फिर होटल मैनेजमेंट का कोरस पूरा करके मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव की नौकरी की 2016 तक लेकिन नौकरी में संतुष्टि नही मिली तो एक नई उड़ान भरी और 2016 में ही कुछ लागत से अपने कैटरिंग के व्यवसाय में पैर रखा । और क्वालिटी और तसल्लीपूर्वक लोगो का काम करके जल्दी ही कामयाबी हासिल की और ये कामयाबी की रफ्तार आज तक निरंतर जारी है । हितेश बताते है कि उनकी डी फार्मा की पढ़ाई खराब नही गयी उसमे जो उन्होंने सीखा उसको वह आज अपने बिजनेस में फॉलो करके ही कामयाबी पा रहे है और नौकरी से वो बिजनेस में सिर्फ इसलिए आये क्योकि वो नौकरी करने से ज्यादा नौकरी देने में विश्वास रखते है। टीम बढ़ता राजस्थान इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

## 2025_065 | बढ़ता राजस्थान

**Suduko**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | | | 2 | 6 | | |
| 6 | | | 1 | | | 8 | | |
| | | 5 | | 7 | | 2 | | |
| | | 9 | | | | 5 | 7 | |
| 2 | 6 | | | | | | | 4 |
| | 1 | | 2 | 4 | 8 | 9 | | 6 |
| 7 | | 1 | | 6 | | | 9 | |
| | 5 | | 7 | | | | 6 | 1 |
| 4 | 3 | | 5 | 1 | 9 | 7 | | |

Ans_2025_064

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 |

### कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खण्डवा,निम्बई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 183/ 116 "प्रतिज्ञा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पालन*। प्रधान संपादक-रास बिहारी विजयवर्गीय मो.नं. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-भाईपास निम्बई, टोंक मो.नं.9414823448 अलवर कार्यालय-गेहनाव सिंह का नोहरा,अलवर मो.नं. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.नं.7023350734 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

जनाधिकार: मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा.लि. का संवाददाता सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री को किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।



बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 18

# एक अन्य व्यापारिक बाधा

भारत या दुनिया भर में व्यापार के बारे में होने वाली चर्चा टैरिफ यानी शुल्कों पर ही केंद्रित रहती है। भारत ने लगातार टैरिफ में इजाफा करने के बाद हाल के महीनों में और केंद्रीय बजट में भी यह संकेत दिया है कि आयात शुल्क में कमी की जाएगी। इस नीतिगत बदलाव के बारे में कहा जा रहा है कि इससे भारत में मूल्यवर्धन होगा और भारतीय उत्पादकों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। बहरहाल आर्थिक खुलापन और एकीकरण अकेले टैरिफ का काम नहीं है। नियमन, प्रतिबंध और कोटा भी इसमें भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर इन्हें व्यापार के 'गैर टैरिफ अवरोध' कहा जाता है। भारत के नीति निर्माताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि गैर टैरिफ अवरोधों को लेकर उनका रुख, टैरिफ में कमी से होने वाले लाभों के विरोधाभासी है।

हाल के वर्षों में भारत के अफसरशाहों ने एक नई तरह का गैर टैरिफ अवरोध लागू किया है। यह संरक्षणवादी और राज्य से संबंधित उपाय तथाकथित 'गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों' या क्यूसीओ की आड़ में छिपा हुआ है। जैसा कि अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन तथा अन्य ने कहा है, क्यूसीओ का अधिक इस्तेमाल भारत के व्यापार और उसकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। हालांकि सांकेतिक तौर पर इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय बाजार में उपलब्ध वस्तुएं स्थानीय मानकों को पूरा करें लेकिन हकीकत यह है कि इन ऑर्डर का इस्तेमाल आयात शिपमेंट को जानबूझकर देर से मंगाने या दूसरी जगह भेजने जैसे कामों के लिए किया जाता है। ऐसे तकरीबन 800 आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इनके दायरे में स्टील से लेकर चमड़ा तक तमाम क्षेत्र आते हैं और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक आने वाले महीनों में तीन गुना क्यूसीओ जारी किए जा सकते हैं। इससे कारोबारियों और व्यापारियों के लिए जीवन मुश्किल होगा। कुछ मौकों पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्यूसीओ में किन उत्पादों को संदर्भित किया जा रहा है। दूसरे मौकों पर ऑर्डर पूरी तरह नए वर्गीकरण को शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए विशिष्ट स्टील के प्रकार। उत्पादक अथवा आयातक अक्सर निश्चित नहीं होते कि उनकी शिपमेंट आएगी और समय पर स्वीकृति पा सकेगी। इससे शेड्यूल और लागत पर असर पड़ता है और निर्यातक अनुबंध के अपने दायित्वों को अक्सर निभा नहीं पाते।

क्यूसीओ के पीछे वजह है चीन से आने वाली खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं को रोकना जिनके बारे में लोगों को चिंता है कि वे भारतीय बाजारों में हावी हैं। परंतु ऐसे ऑर्डर अक्सर बताते हैं कि ऐसे नियंत्रणों से रोकथाम नहीं हो सकी है और ये असली समस्या से अधिक दिक्कतदेह साबित हुए हैं। अफसरशाही प्रोत्साहन लाइसेंस-परमिट राज की अतियों के दौर से ही अपरिवर्तित हैं। अधिक नियंत्रण और अधिक विवेकाधिकार का अर्थ है अधिक शक्ति और अधिक लॉबीइंग। ऐसे व्यवहार के तमाम नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। अधिकतम क्षमता के लिए यह आवश्यक है कि नीति निर्माण में ऐसे विवेकाधिकारों का त्याग किया जाए। निश्चित तौर पर अधिकारियों को मनमाने ढंग से उत्पाद श्रेणियां बनाने या पहचानने तथा फिर उन लागू होने वाले नियम बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कोई बाजार अर्थव्यवस्था ऐसे हालात में प्रभावी नहीं हो सकती। इसका निवेश पर भी बुरा असर होता है। लंबी और विभाजित आपूर्ति श्रृंखला वाली कंपनियां भारत में अपना प्रतिष्ठान स्थापित करने और रोजगार तैयार करने से हिचकिचाती हैं क्योंकि उन्हें यह अंदाजा नहीं होता है कि उन्हें क्या वास्तविक कीमत चुकानी होगी। श्रम गहन क्षेत्रों मसलन रेडीमेड वस्त्रों आदि के क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों का प्रदर्शन कमजोर है। क्यूसीओ ने इन्हें अधिक प्रभावित किया है।

सरकार ने ऑर्थर खुलेपन को लेकर उच्चस्तरीय निर्णय लिया है और यह भारत के विनिर्माण और व्यापार के लिए अच्छा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और चोरी छिपे अपनाया जा रहा संरक्षणवाद समग्र नीतिगत लक्ष्य के साथ विरोधाभासी है। क्यूसीओ की समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

# डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में विघटन का दौर

**पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन का रुख भारत की मदद कर सकता है लेकिन कारोबारी जंग और वैश्विक संस्थानों को कमजोर बनाना मददगार नहीं होगा। बता रहे हैं अजय छिब्बर**

विश्व व्यवस्था आज जिस दौर से गुजर रही है उसे मैं 'विशाल विघटन' के रूप में परिभाषित करना चाहूंगा। वर्ष 2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट को ' विशाल अपस्फीति' कहा गया था। 2020 की महामारी को 'विशाल लॉकडाउन' का नाम दिया गया था। इन घटनाओं ने बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रभाव डाला लेकिन विश्व व्यवस्था को भंग नहीं किया। एक बार जब दुनिया समन्वित राजकोषीय और मौद्रिक नीति तथा तेजी से टीके के विकास के जरिये इनसे उबर गई तो हालात सामान्य हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो व्यवस्था बनी थी अब उसे भंग किया जा रहा है। ऐसा विरोधी ताकतें नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद कर रहे हैं जिनका मानना है कि उनके साझेदारों समेत दुनिया ने अमेरिका का फायदा उठाया है।

उनका नारा है 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' यानी अमेरिका को दोबारा महान बनाना है। इस कोशिश में उनके हथियार हैं मौजूदा वैश्विक समझौतों (पेरिस समझौता) और संस्थानों (विश्व स्वास्थ्य संगठन) से दूरी बनाना, साझेदारों (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो) से अधिक मांग करते हुए उनका रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के दो फीसदी तक बढ़ाना, अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ बढ़ाना और लाखों प्रवासियों को वापस भेजना। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को अमेरिकी मदद की छमाही समीक्षा शुरू की है। इनमें विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल हैं।

अमेरिका का व्यापार भारित टैरिफ 2.2 फीसदी है जो उसके कई साझेदारों से कम है। केवल जापान में यह 1.7 फीसदी है। यूरोपीय संघ में यह टैरिफ 2.7 फीसदी, चीन में 3 फीसदी, कनाडा में 3.4 फीसदी, मेक्सिको में 3.9 फीसदी, वियतनाम में 5 फीसदी, ब्राजील में 6.7 फीसदी, दक्षिण कोरिया में 8.4 फीसदी और भारत (ट्रंप के शब्दों में टैरिफ किंग) में 12 फीसदी है। परंतु ट्रंप ने टैरिफ में भारी इजाफा किया है। उन्होंने स्टील और एल्युमीनियम पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया है। कनाडा और मेक्सिको के साथ व्यापार समझौते के बावजूद उन्होंने उन पर 25 फीसदी का शुल्क लगाया। चीन पर 10 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया और भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ पर बराबरी का शुल्क लगाने की घोषणा की है। चीन ने बदले में अमेरिकी कृषि निर्यात पर 15 फीसदी शुल्क लगाया तो ट्रंप ने प्रतिक्रिया में टैरिफ 10 फीसदी और बढ़ाने की घोषणा कर दी।

इसके परिणामस्वरूप कीमतों में इजाफा होगा, ब्याज दरें ऊंची रहेंगी और वैश्विक वृद्धि में धीमापन आएगा। आर्थिक नीति और व्यापार की अनिश्चितता बढ़ी है और शेयर बाजार तेजी से गिर रहे हैं। ट्रंप पहले स्वतंत्र रही एजेंसियों पर भी नियंत्रण चाह रहे हैं। ये एजेंसियां उपभोक्ताओं के संरक्षण और अर्थव्यवस्था के नियमन से जुड़ी हैं। कमजोर नियमन से शुरुआत में निवेश बढ़ सकता है लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आएगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी होगी। अगर चीन, कनाडा और संभवतः मेक्सिको की तरह अधिकांश देश विरोध करते हैं तो विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। सन 1930 में ऐसे ही टैरिफ ने विश्व व्यापार में जंग के हालात पैदा किए और 'महामंदी' के हालात बने।

अमेरिका में नया बना डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी यूएसएड जैसी सरकारी एजेंसियों में कटौती करके हजारों की संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। ट्रंप के शुल्क और व्यय कटौती की मदद से चार लाख करोड़ डॉलर की कर कटौती की भरपाई की जा सकती है, यह कर कटौती अमीरों के लिए है। साझेदारों से रक्षा व्यय बढ़ाने को कहने के अलावा उनकी योजना अगले पांच साल में अमेरिकी रक्षा बजट 40 फीसदी कम करने की है और संकेत हैं कि रूस और चीन भी ऐसा ही करेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन का सौदा करके नाटो को कमजोर किया है। यह काफी हद तक अफगानिस्तान में तालिबान के साथ उनके विवादित समझौते की तरह ही है। यूरोप यकीनन अपने रक्षा व्यय में इजाफा करेगा और जापान तथा दक्षिण कोरिया भी। यूनाइटेड किंगडम ने पहले ही इसे जीडीपी की तुलना में 2.5 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है।

ट्रंप ने जमीन और खनिज हथियाने के साम्राज्यवादी रास्ते को खोल दिया है। वह 20 लाख फिलिस्तीनियों को बेदखल कर गाजा को हथियाना चाहते हैं, खनिजों के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, पनामा नहर पर दोबारा नियंत्रण करना चाहते हैं और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। यूक्रेन में माफिया शैली में खनिज लूटने की उनकी कोशिश पर फिलहाल लगाम लगी है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में चीन को निशाना बनाने के लिए क्वाड को पुनर्जीवित किया लेकिन शी चिनफिंग के साथ समझौता करके अब वे अपने क्वाड साझेदारों को अधर में छोड़ सकते हैं। वह चीन को अलग-थलग करने के लिए रूस को चीन से दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं।

भारत को क्या करना चाहिए? भूराजनीतिक रूप से उनका पुतिन समर्थक रुख भारत के हित में है। खासतौर पर अगर वह रूस को चीन से दूर करने में कामयाब रहते हैं। चीन भी फिलहाल भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाह सकता है। परंतु वैश्विक संस्थानों पर उसके हमले शायद भारत के हित में नहीं हों। एक नए साम्राज्यवादी 'जंगल राज' में सैन्य और आर्थिक शक्ति ही मायने रखेगी। भारत अपने जीडीपी का 1.5 फीसदी से भी कम हिस्सा रक्षा पर (पेंशन को हटाकर) खर्च करता है। उसे ध्यान देना चाहिए।

आर्थिक मोर्चे पर भारत ने स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ पर तत्काल प्रतिरोध नहीं दिखाया है और वह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। कम टैरिफ के अलावा ट्रंप चाहते हैं कि भारत और अधिक तेल, गैस और ऊर्जा तथा रक्षा उपकरण खरीदे। अगर अमेरिका वैश्विक कीमत पर ईंधन पर बेचे और उपयुक्त रक्षा और ऊर्जा उपकरण तकनीक हस्तांतरण के साथ बेचे तो वह भारत के लिए स्वीकार्य हो सकता है। तकनीक और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस संबंधी सहयोग बढ़ाने पर विचार हो रहा है। यूके और यूरोपीय संघ दोनों पर ट्रंप टैरिफ का खतरा है और वे भारत के साथ अधूरे व्यापार समझौता इस साल पूरा करना चाहते हैं। अगर पश्चिम एशिया का विवाद हल हो गया तो भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर नए सिरे से सामने आ सकता है।

द्विपक्षीय व्यापार समझौता जरूरी है लेकिन आसान नहीं। खासतौर पर कृषि उत्पादों के मामले में जहां भारत अमेरिका के चार फीसदी के बजाय 65 फीसदी व्यापार भार वाला टैरिफ लगाता है। अमेरिका के बाइडन प्रशासन द्वारा 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट भारत के टैरिफ और गैर व्यापार अवरोधों की निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। ट्रंप की समीक्षा तो और भी नकारात्मक हो सकती है। अगर अमेरिका भी गैर टैरिफ अवरोधों और भारत के बढ़ते गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों, वस्तु एवं सेवा कर जैसे आंतरिक करों या चीन से आने वाले औषधि और आईफोन के कलपुर्जों जैसे आपूर्ति श्रृंखला के हिस्सों को निशाना बनाता है तो उसके साथ व्यापार बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप ने कहा कि मोदी उनसे बेहतर वार्ताकार हैं। इसका परीक्षण शीघ्र होगा। फिलहाल हमें उथलपुथल के लिए तैयार रहना होगा।

*(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी के प्रतिष्ठित विजिटिंग स्कॉलर हैं)*

# कार्यस्थलों पर महिलाओं की बाधाएं हों कम

**कार्यबल** में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्त्वपूर्ण है जो न केवल देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देती हैं बल्कि इससे विभिन्न उद्योगों के कार्यस्थल में भी विविधता आती है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2023-24 की सर्वेक्षण अवधि के दौरान महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 40.3 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों के लिए यह 76.3 प्रतिशत थी। हालांकि वर्ष 2017-18 से महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में लगातार सुधार हुआ है लेकिन इसमें और सुधार की काफी गुंजाइश है। कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी से भारत की समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है जिसका विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य में योगदान होगा।

**पीएलएफएस का रुझान:** पीएलएफएस पिछले छह वर्षों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है जो आबादी में उन महिलाओं का प्रतिशत है जो कार्यरत हैं या काम की तलाश में हैं। वर्ष 2017-18 में महिलाओं के लिए एलएफपीआर 23.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी वास्तव में कार्यरत लोगों को ही मापती है जो वर्ष 2017-18 के 22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 40.3 प्रतिशत हो गई।

महिलाओं के रोजगार में आई तेजी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं के रोजगार में वर्ष 2023-24 में 46.5 फीसदी की तेजी आई जो वर्ष 2017-18 के 23.7 फीसदी से अधिक है और यह करीब 23 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का रोजगार 2017-18 के 18.2 फीसदी से बढ़कर 2023-24 में 26 प्रतिशत हो गया जो करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

इसमें अहम प्रगति जरूर दिखी है लेकिन बच्चों की देखभाल और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं जैसी चुनौतियां महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को प्रभावित करती हैं। हालांकि उच्च शिक्षा तक बढ़ती पहुंच और सरकारी पहलों से मिलने वाला समर्थन धीरे-धीरे इन बाधाओं को भी कम कर रहा है। अब कुछ उन महत्त्वपूर्ण वजहों पर विचार करते हैं जिसके चलते महिलाओं की कार्यबल भागीदारी नहीं हो पाती है:

**बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियां:** वर्ष 2020-2024 के लिए पीएलएफएस डेटा उन कारकों को उजागर करता है जिसके चलते महिलाएं कार्यबल से दूर हो जाती हैं। इससे उन क्षेत्रों की अहम जानकारी मिलती हैं जहां नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इन कारकों में सबसे प्रमुख, बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियां हैं जो महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में लगातार सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। वर्ष 2023-24 में 43.04 प्रतिशत महिलाओं ने काम न करने के लिए इन जिम्मेदारियों को मुख्य कारण बताया। यह वर्ष 2022-23 से थोड़ा कम है लेकिन ये आंकड़े महिलाओं के आर्थिक अवसरों पर घरेलू काम के लगातार प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

अमित निर्मल और सविंद्र सिंह

इस चुनौती से निपटने के लिए, कुछ ऐसी नीतियां अधिक महिलाओं को कार्यबल से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं जिनके चलते घरेलू जिम्मेदारियां कम होती हैं जैसे कि क्रेच सुविधा का विस्तार और काम के लचीले तरीकों को बढ़ावा देना आदि। मूल विचार यह है कि बच्चों की देखभाल से जुड़ी सुलभ सुविधाओं से महिलाओं को काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने में मदद मिल सकती हैं जिससे आर्थिक गतिविधियों में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

जनवरी 2024 में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नियोक्ताओं को महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक सुझाव दिया था। इसकी प्रमुख सिफारिशों में से एक 'वर्किंग वीमन हब' को महिलाओं के लिए साझा कार्यस्थल के रूप में स्थापित करना था। ये केंद्र शहरी, कस्बाई और उपनगरीय क्षेत्रों में बनाने का प्रस्ताव था ताकि महिला श्रमिकों के लिए आने-जाने के समय को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सलाह यह दी गई कि कामकाजी माताओं को समर्थन देने के लिए इन केंद्रों के भीतर ही क्रेच सुविधाएं दी जाएं। 'घर के पास काम' वाले मॉडल को सुविधाजनक बनाकर, इन केंद्रों की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में अहम योगदान देने की उम्मीद है।

**पढ़ाई जारी रखने की इच्छा:** आंकड़ों में एक और अहम रुझान दिख रहा है कि अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कार्यबल से बाहर होने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। शिक्षा को कारण बताने वाली महिलाओं का हिस्सा वर्ष 2020-21 के 33.16 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 37.94 प्रतिशत हो गया। यह बदलाव उच्च शिक्षा और करियर में प्रगति करने पर बढ़ते जोर को दर्शाता है। शिक्षा तक अधिक पहुंच के चलते महिलाएं दीर्घकालिक करियर के लिए जरूरी कौशल से खुद को लैस कर रही है, जिससे अधिक कुशलता वाली नौकरियों में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ रही है।

**सामाजिक कारण:** काम में भागीदारी न करने के लिए सामाजिक कारणों का हवाला देने वाली महिलाओं का अनुपात भी कम हुआ है। वर्ष 2020-21 में, 4.34 प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक बाधाओं को अपनी कार्यबल भागीदारी में एक प्रमुख बाधा बताई लेकिन वर्ष 2023-24 तक यह संख्या घटकर सिर्फ 2.52 प्रतिशत रह गई। इससे पता चलता है कि बदलते सामाजिक मानदंड और प्रगतिशील नजरिये के कारण धीरे-धीरे वैसी सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं कम हो रही हैं जिनके कारण पारंपरिक रूप से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सीमित रही है।

**प्रशिक्षण और सुविधाजनक नौकरी की उपलब्धता:** दिलचस्प बात यह है कि प्रशिक्षण या योग्यता की कमी और सुविधाजनक स्थानों पर काम उपलब्ध न होने जैसी बाधाएं लगातार कम हुई हैं। प्रशिक्षण या योग्यता की कमी बताने वाली महिलाओं की तादाद का प्रतिशत वर्ष 2020-21 के 3.43 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 2.07 प्रतिशत हो गया, जो महिलाओं के लिए लक्षित शैक्षणिक और कौशल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इसी तरह, सुविधाजनक स्थानों पर काम की कमी बताने वाली महिलाओं की तादाद इस अवधि के दौरान 0.81 प्रतिशत से घटकर 0.41 प्रतिशत हो गई जो सुविधाजनक नौकरी तक पहुंच बनाने में धीरे-धीरे ही सही सुधार का संकेत देता है।

**महिला श्रमिकों के लिए सरकारी सहायता:** भारत सरकार ने महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने और महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ रोजगार संतुलन में मदद करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। प्रमुख उपायों में मातृत्व अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी, अनिवार्य क्रेच सुविधाएं, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के लिए सहायता और श्रम कानूनों के माध्यम से महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षा के दायरे को मजबूत करना शामिल है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड-अप इंडिया जैसी कौशल विकास योजनाएं और स्वरोजगार पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य सामूहिक रूप से महिलाओं की समानता सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यबल में महिलाओं के योगदान को बढ़ाना है जो विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्त्वपूर्ण है जहां समावेशी विकास देश को समृद्धि और विकास के नए शिखर पर ले जाएगा।

*(अमित निर्मल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त सचिव और सविंद्र सिंह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय के सहायक निदेशक हैं। ये उनके निजी विचार हैं)*

## आपका पक्ष

### देश में महिला सशक्तीकरण की राह

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। देश की महिलाओं को अब हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार मिल रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का हो या अन्य ओर कोई क्षेत्र। इसी कारण आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खेलों में महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है। खेलों में पी.टी. उषा, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, दीपिका कुमारी, साइना नेहवाल, गीता फोगाट, सानिया मिर्जा और बहुत-सी ऐसी युवतियां हैं, जिन्होंने खेल में अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया है। विज्ञान में कल्पना चावला ने शानदार प्रदर्शन कर यह दर्शाया कि अगर लड़कियों को हुनर दिखाने का मौका मिले तो वह जीत का परचम लहरा सकती हैं। वहीं सामाजिक बुराइयों का अंत करने के लिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। हालांकि आज भी देश सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह के मकड़जाल से मुक्त नहीं हो पाया है। इसके लिए हर वर्ग के लोगों को बेटे-बेटी में भेदभाव की मानसिकता खत्म करने तथा सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पर अमल करना चाहिए। समय के साथ महिलाओं की दशा और सोच में काफी बदलाव आया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र, चाहे वह राजनीति का हो, सामाजिक हो या फिर अन्य अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं।

*राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

पिछले साल आयोजित पेरिस ओलिंपिक में मनु भाकर ने दो पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया था

### ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तीकरण

पंचायतों में महिला नेतृत्व एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। 'सशक्त पंचायत नेत्री' अभियान की शुरुआत महिलाओं को सशक्त बनाने और पंचायतों में उनकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार कई महिला प्रधान के कामकाज में उनके पुरुष रिश्तेदार हस्तक्षेप करते हैं, जिससे महिलाओं की लोकतंत्र में वास्तविक भागीदारी सीमित हो जाती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें नेतृत्व कौशल विकसित करने और सरकारी तंत्र से समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी न केवल लैंगिक समानता के लिए महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी से पंचायतों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता आती है और महिलाओं की जरूरतों और हितों को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सकता है। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं जैसे कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम। हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पंचायतों में महिलाओं का सशक्तीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सरकार, नागरिक समाज और समुदायों को मिलकर काम करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं बिना किसी डर या दबाव के पंचायत में नेतृत्व कर सकें।

*राजूराम प्रजापत, नागौर*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आयरलैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में संघर्ष आज एक प्रमुख मुद्दा है और भारत का मानना है कि मतभेदों को बातचीत एवं कूटनीति के जरिये सुलझाया जाना चाहिए।